चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 19 अक्टूबर–25 अक्टूबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार विधानसभा चुनाव

राजनीतिक दलों ने जनता के साथ धोखा किया

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

देश के सभी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा. उनका मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे. अगर यह बात सही है, तो यकीन मानिए, भारत के प्रजातंत्र का भविष्य अंधकारमय है. अगर बिहार विधानसभा चुनाव से ही देश की राजनीति का भविष्य तय होना है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इस चुनाव में जो कुछ हो रहा है, वही देश की राजनीति में होने वाला है. राजनीतिक दल बिहार में जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, उससे देश को कमज़ोर करने वाली ताकतों, नक्सलवादियों और आतंकवादियों को बल मिलेगा. बिहार चुनाव सीधे तौर पर अराजकता को न्योता है. राजनीतिक दलों ने अवसरवादिता, दिशाहीन संवाद, भद्दी टिप्पणियां, विचारहीनता, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, स्वार्थ, धनबल और अपराधीकरण आदि की सारी सीमाएं लांघ दी हैं. राजनीतिक दलों और नेताओं ने बिहार चुनाव को सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को गुमराह कर वोट लेने का खेल बना दिया है. सारे दलों के एजेंडे से जनता गायब है. जनता की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है. ग़रीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी, लचर स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत समस्याएं चुनाव से गायब हैं. राजनीतिक दलों पर सिर्फ़ चुनाव जीतने की धुन सवार है. हक़ीकत यह है कि बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों ने जनता के साथ साफ़-साफ़ धोखा किया है. सवाल यह है कि ऐसे राजनीतिक दल और नेता बिहार की जनता के वोट के लायक भी हैं क्या?

मनीष कुमार

किसने, क्या, कब और कैसे पाया, यही राजनीति का सही अर्थ है. राजनीति की यह सटीक और व्यवहारिक परिभाषा हेरॉल्ड लॉसवेल ने दी. इसका मतलब यह है कि राजनीति असल में सरकारी संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई है. संसाधनों की हिस्सेदारी में किसे कब और कितना हिस्सा मिलता है, उसी से यह पता चलता है कि कौन सत्ता के नज़दीक है और कौन सबसे दूर. जिन वर्गों को सरकार से फ़ायदा होता है, जिन्हें ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं बनाती है, वही राजनीति की मुख्य धारा में होते हैं, वही सत्ता के क़रीब होते हैं. जिन लोगों को सरकारी नीतियों एवं योजनाओं से फ़ायदा नहीं होता, वे राजनीति के हाशिये पर होते हैं, वे सिर्फ़ चुनाव में वोट डालने वाले एक मतदाता हैं, जिनका सरकार पर न तो कोई ज़ोर होता है और न सरकार उनके बारे में सोचने के लिए बाध्य होती है. हक़ीकत यह है कि बिहार के ग़रीब, पिछड़े, दलित और मुसलमान राजनीति के हाशिये पर हैं. उन्हें सरकार की तरफ़ से आज तक कोई राहत नहीं मिली. बिहार का यह वर्ग नारकीय ज़िंदगी जीने को मजबूर है. लेकिन, चुनाव के दौरान उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि वह राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है. राजनीतिक दल वादा भी करते हैं कि सरकार बनते ही सबसे पहला काम उसकी समस्याओं को हल करने का होगा. कोई इस वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा देता है, तो कोई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है. आज़ादी हासिल हुए 68 साल हो गए, हर रंग की सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन उसकी हालत साल दर साल खराब होती गई. हर राजनीतिक दल को उसका वोट चाहिए, लेकिन उसकी समस्याएं ख़त्म करने की बात कहने की जहमत कोई नहीं उठाता.

राजनीतिक दलों को अपशब्द कहने और कुतर्क करने से फ़ुर्सत हो, तब तो जनता की समस्याओं पर बात करने का उन्हें वक्त मिले. बिहार चुनाव में देश के महान–महान नेता एक–दूसरे के लिए शैतान, पिशाच, बह्मपिशाच और हत्यारा जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं. यह हालत तब है, जब देश के प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री की तरह जगह–जगह घूमकर रैलियां कर रहे हैं. उम्मीद तो यह थी कि भाषा और संवाद का स्तर ऊंचा होगा, लेकिन अफ़सोस, उन्होंने भी इसे हवा दी. यहां यह कहना पड़ेगा कि अकेले नीतीश कुमार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने भाषणों और बयानों में राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया. नीतीश कुमार इस चुनाव में सबसे मर्यादित नेता नज़र आ रहे हैं, लेकिन वह चुनाव के मुद्दे नियंत्रित करने में असफल रहे हैं. इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा गोमांस बन गया है.

युवाओं के पास नौकरी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अस्पतालों में न डॉक्टर हैं और न दवाएं. राज्य आर्थिक विकास के मामले में देश ही नहीं, अफ्रीका जैसे देशों से पीछे छूट गया है. घरों में बिजली नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए लोग पलायन कर रहे हैं. लेकिन, इन सब मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है. सब इस बात का फ़ैसला करने में जुटे हैं कि गोमांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं. फिजूल के मुद्दों को हवा देने में मीडिया भी बराबर का दोषी है. कोई यह नहीं पूछ रहा है कि राज्य सरकार ने पिछले पांच सालों में क्या किया या फिर केंद्र सरकार ने पिछले डेढ़ साल में बिहार को क्या दिया? चुनाव वह प्रक्रिया है, जिसमें जनता राजनीतिक दलों की ज़िम्मेदारी तय करती है, लेकिन बिहार चुनाव में राजनीतिक दल बड़ी चतुराई से जनता को जातिवाद और धार्मिक उन्माद के दलदल में धकेल कर अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गए. राजनीतिक दलों ने जनता को न सिर्फ़ धोखा दिया, बल्कि

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मुसलमान हमेशा छले गए

भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान बिहार में रहते हैं. अगर सरकारी एवं ग़ैर सरकारी आंकड़ों को ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि बिहारी मुसलमानों की हालत समाज के सबसे निचले वर्ग से भी बदतर है. वह इसलिए भी, क्योंकि दलित, महादलित एवं पिछड़ी जातियों को सरकारी मदद मिलती है, आरक्षण मिलता है, लाल कार्ड बांटे जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को उनकी समस्याओं से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि आज़ादी के वक्त मुसलमानों की हालत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन सरकारी रवैये की वजह से दूसरे समुदायों के मुक़ाबले मुसलमान हर क्षेत्र में पिछड़ते चले गए. बिहार में 16.5 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है. बिहार के 87 प्रतिशत मुसलमान गांवों में रहते हैं, सिर्फ़ 13 प्रतिशत शहर में रहते हैं. गांवों की हालत खराब है. वहां ग़रीबी है, अशिक्षा है, बेरोज़गारी है. खराब हालात के बावजूद गांवों में रहने वालों में जो सबसे पिछड़ा तबका है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान, भूमिहीन या छोटे किसान हैं.

बिहार में 28.4 प्रतिशत मुसलमान भूमिहीन किसान हैं. सिर्फ़ 35 प्रतिशत मुसलमानों के पास ज़मीन है, जो आम आबादी के अनुपात में काफ़ी कम है. बिहार में क़रीब 58 प्रतिशत ग्रामीणों के पास ज़मीन है. खेती करने वाले मुसलमानों की संख्या और भी कम है. जिनके पास ज़मीन है, वह भी इतनी कम है कि उनका गुज़र-बसर नहीं हो पाता. हैरानी की बात यह है कि सिर्फ़ तीन प्रतिशत मुस्लिम किसानों के पास ट्रैक्टर है और सिर्फ़ दस प्रतिशत के पास पंपिंग सेट. हिंदुओं के मुक़ाबले मुस्लिम किसान ग़रीब हैं. यही वजह है कि 75 प्रतिशत ग्रामीण मुसलमान खेतों में मज़दूरी करके अपना परिवार चलाते हैं. पिछले पांच सालों में सिर्फ़ 0.32 एकड़ प्रति परिवार की दर से 2.4 प्रतिशत मुसलमानों ने ज़मीन खरीदी, लेकिन 0.49 एकड़ प्रति परिवार की दर से 2.5 प्रतिशत मुसलमानों ने अपनी ज़मीन बेची है. इसका मतलब यह है कि ज़मीन के मालिकाना हक़ से मुसलमान धीरे-धीरे बाहर होते जा रहे हैं. बिहार के गांवों में रहने वाले मुसलमानों में 2.1 प्रतिशत लोग कारीगर हैं, जिनकी वार्षिक आय महज सोलह हज़ार रुपये है. मतलब यह कि मुसलमान कारीगरों के परिवार ग़रीबी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भीषण गर्मी में काम करने पर मजबूर हैं फौजी P-3

बिहार चुनाव : व्यक्तिगत आक्षेप ही हथियार P-4

कहती है एडीआर रिपोर्ट कोई दल पाक-साफ़ नहीं P-5

बिहार विधानसभा चुनाव

राजनीतिक दलों ने जनता के साथ धोखा किया

पृष्ठ 1 का शेष

एक रणनीति के तरह भ्रमित किया है, ताकि वे अपनी अनैतिक राजनीति को परवान चढ़ा सकें.

राजनीतिक दलों एवं नेताओं ने मीडिया की मदद से एक तरफ़ जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाकर जातिवाद और धार्मिक उन्माद में लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ़ अपना खेल शुरू कर दिया है. सभी राजनीतिक दलों ने बिहार की राजनीति को फिर से अपराधियों के हवाले करने की तैयारी कर ली है. हर राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देने पर आमादा है, जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है. हर दल अपराधियों, सरगनाओं और उनके रिश्तेदारों को टिकट दे रहा है. बिहार में ऐसे नेताओं को बाहुबली कहते हैं. हैरानी की बात यह है कि राजनीतिक दल अपराधियों को उम्मीदवार भी बना रहे हैं, साथ ही यह कह रहे हैं कि राजनीति का अपराधीकरण ख़त्म हो. बिहार में राजनीति और अपराध का पुराना रिश्ता रहा है. हक़ीकत तो यह है कि बिहार ने वह दौर भी देखा, जब राजनीति का अपराधीकरण नहीं, बल्कि अपराध का राजनीतिकरण हुआ था. बिहार देश का पहला राज्य है, जहां राजनीति का अपराधीकरण हुआ. देश में बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना 1967 में बेगूसराय में हुई थी. उस वक्त यह मुंगेर ज़िले का अंग था. पुलिस की ओर से गोलियां भी चली थीं और बूथ कैप्चर करने वाला एक शख्स मारा भी गया था.

यह वह ज़माना था, जब चुनाव में ताक़तवर लोग बैलेट बॉक्स लूट ले जाते थे और अधिकारियों से बैलेट छीनकर बोगस वोटिंग करते थे. कमज़ोर वर्ग के लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया जाता था. आज हालत यह है कि बिहार की हर सीट पर कोई न कोई बाहुबली चुनाव लड़ने लगा है. इससे राज्य का सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ है. विकास की गति रुक गई है और राजनीति में पढ़े-लिखे लोगों का आना बंद हो गया है. लोग राजनीति को अपराध के पर्याय के रूप में देखने लगे हैं. अपराधियों का राजनीति में प्रवेश अब संस्थागत तरीक़े से हो रहा है. लोग पहले अपने इलाक़े में गुंडागर्दी करते हैं, अपराध की दुनिया में अपनी ख़तरनाक छवि बनाते हैं और फिर किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन जाते हैं. अपराधी इस तरह बड़ी आसानी से चुनावी राजनीति में प्रवेश करने में कामयाब हो जाते हैं. दूसरी तरफ़ राजनीतिक दल हैं, जिनका यह कर्तव्य है कि वे ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें, लेकिन अफ़सोस कि वे उन्हें अपना प्रत्याशी बना रहे हैं. अब चुनाव आयोग कड़ी निगरानी करता है. आज बिहार में पांच चरणों में चुनाव इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ पूरे राज्य में सुरक्षाबलों को लगाना मुश्किल है. अब चुनाव भी पहले की तरह नहीं होते, लेकिन समस्या यह है कि जो लोग पहले नेताओं के लिए बूथ लूटते थे, वे आज खुद उम्मीदवार बन बैठे हैं.

बिहार में राजनीति के अपराधीकरण के लिए राजनीतिक दल ज़िम्मेदार हैं. आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने में कोई भी दल पीछे नहीं है. पहले चरण में चुनाव मैदान में उतरे सभी 587 उम्मीदवारों में से 174 यानी 30 प्रतिशत उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले हैं. उनमें से 130 पर गंभीर मामले चल रहे हैं. पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची देखकर बाकी के चरणों के उम्मीदवारों की छवि का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. वैसे तो विभिन्न राजनीतिक दल एक-दूसरे पर अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार में कोई भी राजनीतिक दल दूध का धुला नहीं है, सबके दामन में दाग़ है. जो लोग राज्य में क़ानून-व्यवस्था की बात करते हैं, उनसे यह सवाल करना ज़रूरी है कि उनकी पार्टी ने अपराधियों को क्यों टिकट दिया? क्या उन्हें लगता है कि जिन अपराधियों की जगह जेल में है, उन्हें विधानसभा में बैठा देने से बिहार में क़ानून-व्यवस्था की हालत ठीक हो जाएगी? राजनीतिक दलों से यह पूछना चाहिए कि क्या अपराधियों को विधायक बनाने से बिहार का विकास होगा या फिर सुशासन आ जाएगा? ऐसे माहौल में जब लोगों को खराब-अयोग्य उम्मीदवारों के बीच चुनाव करना पड़ता है, तो वे वोट देने में रुचि नहीं लेते. उन्हें लगता है कि उनके वोट का हक़दार कोई भी उम्मीदवार नहीं है. ऐसा सोचना ग़लत है, क्योंकि इससे आपराधिक छवि वाले नेताओं को फ़ायदा होता है. वे जीत जाते हैं. अगर राजनीतिक दल अपराधियों को विधायक बनाने पर आमादा हैं, तो जनता को भी फ़ैसला करना चाहिए कि चाहे जो भी हो, वह अपना वोट उसी उम्मीदवार को देगी, जो अपराधी या आपराधिक छवि वाला न हो. लेकिन, इन बातों से राजनीतिक दलों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. इसलिए वे जानबूझ कर ऐसी ग़लतियां दोहराते हैं.

राजनीतिक दलों एवं नेताओं ने मीडिया की मदद से एक तरफ़ जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाकर जातिवाद और धार्मिक उन्माद में लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ़ अपना खेल शुरू कर दिया है. सभी राजनीतिक दलों ने बिहार की राजनीति को फिर से अपराधियों के हवाले करने की तैयारी कर ली है. हर राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देने पर आमादा है, जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है. हर दल अपराधियों, सरगनाओं और उनके रिश्तेदारों को टिकट दे रहा है.

बिहार के हर राजनीतिक दल ने एक और महापाप किया है, उन्होंने मालदार और धनाढ्य लोगों को टिकट दिया. पहले चरण के 146 उम्मीदवार (25 प्रतिशत) करोड़पति हैं. अगर कुल उम्मीदवारों की घोषित आय का औसत निकाला जाए, तो वह 1.44 करोड़ रुपये प्रति उम्मीदवार होगी. कई राजनीतिक दलों पर टिकट बेचने का भी आरोप लगा. इससे ज़मीनी कार्यकर्ता खुद को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं. जिन कार्यकर्ताओं ने पांच सालों तक पार्टी के लिए खून-पसीना बहाया, उन्हें दरकिनार करके बिहार में राजनीतिक दलों ने ऐसे-ऐसे लोगों टिकट दे दिया, जिनका न तो कभी राजनीति से सरोकार रहा और न समाज से. राजनीतिक दलों की दलील सिर्फ़ यह है कि उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं. इन राजनीतिक दलों से यह सवाल करना ज़रूरी है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके साधारण कार्यकर्ता चुनाव हार जाएंगे और जिनके पास पैसा-ताक़त है, वे चुनाव जीत जाएंगे? यह तो जनता के विवेक पर ही सवाल उठाने वाला तर्क है. जिसके पास पैसा है, वह पैसे के बल पर वोट मांगेगा, गांधी के आदर्शों पर वोट नहीं मांगेगा. ऐसे उम्मीदवार वोट खरीदने की कोशिश करते हैं. असहाय राजनीतिक कार्यकर्ता थक-हार कर इन धनाढ्यों के लिए प्रचार करने को मजबूर हैं. राजनीतिक दलों को यह भी समझना चाहिए कि ज़माना बदल रहा है. युवा वर्ग राजनीति में ईमानदार, साफ़-सुथरी छवि वाले और पढ़े-लिखे लोगों को देखना चाहता है, लेकिन राजनीतिक दल ठीक इसका उलटा कर रहे हैं. राजनीतिक दलों से ज़्यादा उम्मीद करना भी बेकार है, क्योंकि उनके लिए चुनाव जीतना ही एकमात्र मक़सद है. भले ही उन्हें अपने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को नाराज़ क्यों न करना पड़े, लोगों की आकांक्षाओं-आशाओं की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े. यानी राजनीतिक दल किसी भी क़ीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं.

संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र का मंदिर हैं. वहां जाने का अधिकार सिर्फ़ योग्य, कर्मठ, ईमानदार एवं जनहितैषी शख्स को है, जो नुमाइंदगी का फ़र्ज़ बख़ूबी निभा सके. दाग़दार दामन वालों, सौदेबाज़ बहुरूपियों और काले धन के धनकुबेरों को संसद-विधानसभा में भेजना लोकतंत्र और देश की गरिमा की अनदेखी नहीं, बल्कि चुनाव के नाम पर जनता के साथ धोखा है. राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि राजनीति और चुनाव का अपराधीकरण रोकने का पहला दायित्व उन्हीं का है. सबसे पहले उन्हें अपराधियों और आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट न देने का संकल्प लेना होगा. बिहार की जनता को इस बार पूरी सावधानी से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, वरना अगले पांच सालों तक हाथ मलने के अलावा उसके पास और कोई चारा शेष नहीं रहेगा. ■

manishbph244@gmail.com

मुसलमान हमेशा छले गए

पृष्ठ 1 का शेष

रेखा से नीचे हैं. बिहार में शिक्षा की हालत बदतर है. साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत है. रोहतास, मुंगेर और पटना इसमें सबसे आगे हैं. जबकि मुस्लिम बाहुल्य जिले किशनगंज, अररिया और कटिहार साक्षरता के मामले में पीछे हैं. किशनगंज और कटिहार में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है. उन्हें साल भर में सिर्फ़ 230 दिन ही काम मिल पाता है, बाकी के दिनों में वे बेरोज़गार रहते हैं. एक दिन की कमाई 28-32 रुपये है. मतलब यह कि उनकी मासिक आय महज 600 रुपये है. इस कमाई से न तो घर चलाया जा सकता है और न इज्जत बचाई जा सकती है. इसका मतलब यह है कि बिहार के मुसलमान ग़रीबी और अभाव का दंश झेल रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक़, ग्रामीण मुसलमानों की सालाना आय 4,640 रुपये है और शहर में रहने वालों की सालाना आय 6,320 रुपये. गांवों में रहने वाले मुसलमानों में से 49.5 प्रतिशत और शहर में रहने वाले मुसलमानों में से 44.5 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. यानी बिहार में मुसलमानों की क़रीब आधी आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे है. ज़्यादातर लोग क़र्ज़ में डूबे हुए हैं. बिहार के गांवों में सभी धर्म के लोगों को मिलाकर 10.1 प्रतिशत के पास पक्के मकान हैं, जबकि शहरी मुसलमानों में से 25 प्रतिशत के पास पक्के मकान हैं. मतलब यह कि गांव के मुसलमान धीरे-धीरे ग़रीब होते चले गए. उनके पास पूर्वजों के बनाए

पक्के मकान तो हैं, लेकिन कमाने का ज़रिया नहीं है.

अगर हम शहरों की बात करें, तो दूसरे समुदाय से मुसलमानों की आर्थिक स्थिति गांव के मुक़ाबले और भी ज़्यादा खराब है. गांवों में ज़्यादातर मुसलमानों के पास पक्के मकान हैं, लेकिन शहरों में दूसरे लोगों के मुक़ाबले मुसलमानों के पास पक्के मकान नहीं हैं. बिहार के शहरों में 75 प्रतिशत घरों में बिजली है, लेकिन मुसलमानों में 47.2 प्रतिशत लोगों के घरों में बिजली है. राजनीति में भी मुसलमान हाशिये पर चले गए हैं. ये आंकड़े सरकार के पास भी हैं. सरकार के पास यह जानकारी है कि मुसलमानों की हालत दूसरे समुदायों से कहीं ज़्यादा खराब है. मुसलमानों की हालत आज ऐसी नहीं हुई है, बल्कि आज़ादी के बाद से ही उनकी हालत बदतर होती जा रही है. उनकी हालत सुधारने के लिए सरकार को नीतिगत तरीक़े से आगे आना चाहिए था, लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की. बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार ने महादलितों के लिए योजनाएं बनाईं, वैसी योजनाएं मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी थीं. बिहारी मुसलमानों की सुकून भरी ज़िंदगी पर ही सवालिया निशान लग गया है.

ऐसे में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मुसलमानों की संख्या इतनी है कि वे पचास सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं. समस्या यह है कि मुसलमानों की हालत पर आवाज़ उठाना तो दूर, राजनीतिक दल उस पर बात करने से भी बचते हैं. अक़लियत का वोट बाज़ार में नीलाम कर दिया जाता है. ग़रीबी, अशिक्षा एवं बेरोज़गारी के भंवर में फंसे बिहारी मुसलमानों को राजनीति की वह सटीक परिभाषा याद रखने की ज़रूरत है, जो हेरॉल्ड लॉसवेल ने दी थी. उन्हें राजनीतिक दलों से यह ज़रूर पूछना चाहिए कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों को सरकारी संसाधनों में कब और कितना हिस्सा मिला है? ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 33
दिल्ली, 19 अक्टूबर-25 अक्टूबर, 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार
एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन
सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378
पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भारतीय सेना के टैंक युद्धाभ्यास के दौरान आग का गोला बन जाते हैं. उनके अंदर बैठे सैनिक भयानक गर्मी के कारण अपना दिमागी संतुलन ठीक नहीं रख पाते, फिर वे युद्ध कैसे लड़ेंगे! मानसिक असंतुलन के कारण होने वाली मानवीय चूकों से युद्धाभ्यास के दरम्यान ही मेजर ध्रुव यादव जैसे कई अफसर एवं सैनिक शहीद होते रहते हैं, लेकिन नौकरशाही के चंगुल में फंसा रक्षा मंत्रालय इस तरफ़ ध्यान नहीं दे रहा है. भारतीय थलसेना की आर्मर्ड कोर (टैंक दस्ता) के आला अफसर बताते हैं कि आर्मर्ड कोर के अफसर एवं सैनिक भीषण गर्मी में टैंक के भीतर काम करने से मना कर रहे हैं.

सेना में एसी निकलवा कर खरीदे जा रहे टैंक

भीषण गर्मी में काम करने पर मजबूर हैं फौजी

प्रभात रंजन दीन

भारतीय सेना एक बड़े अंदरूनी विरोध का सामना कर रही है. थलसेना की आर्मर्ड कोर में तैनात सैनिक भीषण गर्मी में भट्ठी की तरह दहकते टैंकों के अंदर काम करने से इंकार कर रहे हैं. भारतीय सेना को बिना एसी वाले टैंक दिए जाने का जबरदस्त विरोध हो रहा है. गर्मी के कारण टैंकों के नाजुक पुर्जे नष्ट हो रहे हैं. भीषण गर्मी से सैनिकों का मानसिक संतुलन ठीक न रहने से हादसे हो रहे हैं. एसी निकलवा कर टैंक खरीदे जाने की प्रक्रिया बंद किए जाने की सिफारिशों को पिछले एक दशक से ताक पर क्यों रख दिया गया है, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. दोयम दर्जे के व्यवहार से सेना युद्ध के लिए तकनीकी तौर पर और मनोबल के साथ खुद को तैयार कैसे कर सकेगी, यह सवाल दिनोंदिन गहराता जा रहा है. पाकिस्तान की तरफ़ से सीमा पर उकसावे की लगातार कार्रवाई हो रही हो और भारत के सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग तक सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दे चुके हों, ऐसे संवेदनशील समय में भी भारतीय थलसेना के टैंकों में वातानुकूलन मशीनें (एसी) लगाने में सरकार कोताही कर रही है, यह हैरत करने और देश के लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली ख़बर है.

भारतीय सेना के टैंक युद्धाभ्यास के दौरान आग का गोला बन जाते हैं. उनके अंदर बैठे सैनिक भयानक गर्मी के कारण अपना दिमागी संतुलन ठीक नहीं रख पाते, फिर वे युद्ध कैसे लड़ेंगे! मानसिक असंतुलन के कारण होने वाली मानवीय चूकों से युद्धाभ्यास के दरम्यान ही मेजर ध्रुव यादव जैसे कई अफसर एवं सैनिक शहीद होते रहते हैं, लेकिन नौकरशाही के चंगुल में फंसा रक्षा मंत्रालय इस तरफ़ ध्यान नहीं दे रहा है. भारतीय थलसेना की आर्मर्ड कोर (टैंक दस्ता) के आला अफसर बताते हैं कि आर्मर्ड कोर के अफसर एवं सैनिक भीषण गर्मी में टैंक के भीतर काम करने से मना कर रहे हैं. कभी सख्त फौजी अनुशासन का हवाला देकर, तो कभी समझा-बुझाकर उनसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन स्थिति अत्यंत भयावह और अमानवीय है. उसका नकारात्मक असर प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास पर पड़ रहा है. टैंकों के संवेदनशील उपकरण खराब हो रहे हैं, वह अलग. सेना के अफसर सैन्य क़ानून के तहत खुला बयान नहीं दे सकते, लेकिन उनकी पीड़ा चीख की तरह महसूस की जा सकती है. भारतीय सेना के मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में ही है. यहां उन चीखों की अनुगूंज सुनी जा सकती है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अराजक स्वरूप में सड़कों पर दिखती है, लेकिन सेना अपनी ईमानदार अभिव्यक्ति भी नहीं दे सकती.

सेना की उसी पीड़ा को अभिव्यक्ति देते हुए हम आपको इस बारे में ख़बरदार कर दें कि टैंकों के प्रशिक्षण या टैंकों के युद्धाभ्यास वाले क्षेत्र में आप रहते हों, तो सतर्क रहें और सैनिकों को अपनी तरफ़ से जितनी शीतलता प्रदान कर सकें, उतना अच्छा होगा. यह राष्ट्र-धर्म है. इसका पालन यदि सरकार नहीं कर रही है, तो आम नागरिक अपने धर्म से क्यों वंचित हों! यह ख़बर महज अख़बार की औपचारिकता निभाने के लिए नहीं लिखी जा रही, बल्कि चौथी दुनिया के ज़रिये आप नागरिकों तक एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. भारतीय सेना के मध्य कमान के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडीशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश जैसे सात राज्य आते हैं. मध्य कमान प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए मुफीद क्षेत्रों में शुमार है, लेकिन यह मसला केवल मध्य कमान तक सीमित नहीं है. देश भर में जहां भी आर्मर्ड कोर (टैंकों) के रेजिमेंट, डिवीजन, कैविलरी या फॉर्मेशंस हैं, उन सब जगहों से एक ही आवाज़ आ रही है. खास तौर पर देश के विशाल एवं संवेदनशील दक्षिणी-पश्चिमी सेक्टर (राजस्थान-गुजरात सीमा क्षेत्र) में पड़ने वाली असहनीय गर्मी में टैंकों का युद्धाभ्यास फौजियों के लिए अत्यंत तकलीफदेह साबित हो रहा है. संबद्ध सैन्य कमानों के सेना कमांडर इसे लेकर अत्यंत चिंतित हैं और इस बारे में सेनाध्यक्ष को भी अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इस आपातकालीन-महत्व के मसले को रक्षा मंत्रालय पर काबिज नौकरशाह (आईएएस अफसर) दबाए बैठे हैं. मध्य कमान में टैंकों के बेड़े प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में बबीना (झांसी), कानपुर, मेरठ, रुड़की और झारखंड में नामकूम में हैं. झांसी के बबीना में भारी-भरकम 31 आर्मर्ड डिवीजन है.

आप यह जानते-समझते चलें कि टैंकों के निर्माण के समय ही अन्य उपकरणों की तरह उनमें एसी मशीनें भी फिट की जाती हैं, लेकिन निर्माता देशों से टैंकों की खरीद करने वाले भारतीय प्रतिनिधि-अधिकारी उनमें से एसी मशीनें निकलवा देते हैं. उनका तर्क होता है कि ऐसा करने से टैंक की क़ीमत थोड़ी कम हो जाती है. ऐसे भौंड़े तर्कों पर भारतीय सेना के लिए टैंक खरीदे जाते हैं और भारतीय फौजियों के लिए असहनीय यातना का सामान खरीदा जाता है. रक्षा उपकरणों की खरीदारी में मोटा कमीशन खाने वाले नेताओं, नौकरशाहों और दलालों को भारतीय सैनिकों की अनिवार्य-सुविधा देखी नहीं जाती और कुछ हज़ार रुपये की एसी मशीनें टैंकों से निकलवा दी जाती हैं. हज़ारों करोड़ रुपये के टैंकों की खरीद में कुछ हज़ार की एसी मशीनें निकलवा कर सरकारी कोष को बचत कराई जा रही है या यह भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ डालने का क्रमश: प्रयास है, इसे आसानी से समझा जा सकता है. अगर यह भारतीय सैनिकों की पीड़ा से जुड़ा मसला न होता, तो एसी निकलवा कर टैंक खरीदने के तर्क को लोग किसी फूहड़ चुटकुले की तरह लेते. यह अत्यंत गंभीर मसला है कि भारतीय रक्षा प्रणाली ऐसे ही फूहड़ चुटकुलेबाजों के बूते चल रही है. पाकिस्तानी सैनिक वातानुकूलित टैंकों में युद्धाभ्यास करते हैं और महान भारतवर्ष के सैनिक टैंकों के अग्नि-कक्ष में बैठकर अपने शौर्य का नहीं, बल्कि अपने धैर्य का इम्तिहान देते हैं.

रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम ने वर्ष 1999 में ही टैंकों में एसी होने की अनिवार्यता रेखांकित कर दी थी. यह तय हो गया था कि एसी निकलवा कर टैंक खरीदे जाने की प्रक्रिया फौरन बंद हो और सभी सक्रिय टैंकों में तत्काल एसी फिट कराए जाएं. लेकिन अफ़सोस यह है कि इस सिफारिश की फाइल नौकरशाहों ने दबा दी और भारतीय सैनिकों की त्रासदी का दौर अब भी जारी है. यह नौकरशाही और लालफीताशाही के गंदे मनोभाव उजागर करने वाला पहलू है. दु:खद यह है कि भारतीय सेना के लिए जो टैंक या अन्य उपकरण खरीदे जाते हैं, उनका ज़मीनी स्तर पर इस्तेमाल करने वाले अफसरों और सैनिकों से उनकी अनुभवजनित राय नहीं ली जाती. तकनीकी विशेषज्ञों के परीक्षण दल ने यह भी पाया था कि बिना एसी के लंबे समय तक गर्मी सहने और धूल की वजह से टैंकों के प्रदर्शन स्तर में काफी कमी आ गई है. इसके बावजूद एसी निकलवा कर टैंक खरीदे जाते रहे. इनमें टी-90 जैसे टैंक भी शामिल हैं. सेना के एक आला अधिकारी इसे नौकरशाहों का घटियापन बताते हुए कहते हैं कि खुद अपने बाथरूम में भी एसी रखने वाले आईएएस अफसर दूसरे को ज़रूरत के समय भी एसी का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते. यह आधिकारिक तथ्य है कि तमाम तकनीकी आपत्तियों को ताक पर रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने एसी मशीनें निकलवा कर टैंक खरीदने का करार किया. इस वजह से आर्मर्ड कोर के टैंकों के संवेदनशील पुर्जे बेकार होने की स्थिति में आ गए हैं. कई टैंकों के उपकरण तो बदले भी जा रहे हैं. रक्षा मंत्रालय के ही आधिकारिक दस्तावेज़ बताते हैं कि युद्ध में कारगर भूमिका अदा करने वाले टैंकों के गर्मी एवं धूल में काम करने की वजह से उनके मिसाइल दागने के उपकरणों और प्रत्येक क्षण तापक्रम बताने वाले यंत्र की परफॉर्मेंस में गिरावट आई है.

मिसाइल फायर करने की क्षमता के साथ-साथ टैंकों के एक्टिव डिफेंस सिस्टम, थर्मल इमेजिंग प्रणाली, नाइट विज़न और फायर कंट्रोल सिस्टम में काफी खराबी आ रही है. तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने गर्मी वाले सेक्टरों में ये खामियां अधिक पाई हैं. राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर सेक्टर के लंबे रेगिस्तानी सीमा क्षेत्र में तैनात टी-90 टैंक अत्यंत खराब हालत में पाए गए हैं. झांसी के बबीना और रांची के नामकूम जैसे क्षेत्रों में भी खामियां पकड़ी गईं. शर्मनाक बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करके टैंकों का बेड़ा बनाया, लेकिन उसके रखरखाव की कोई फिक्र नहीं की. टैंक खरीदने के पहले भी विशेषज्ञों के दल ने परीक्षण के दौरान टैंकों के भीतरी हिस्सों के बहुत अधिक गर्म होने का उल्लेख करते हुए उनमें एसी लगाने की सिफारिश की थी. रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1999 में ही टैंकों में एसी लगाने की ज़रूरत स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी एसी मशीनें निकलवा कर टैंक खरीदे जाते रहे. पहले खरीदे जा चुके टैंकों में एसी लगाने की तो बात ही दूर रही. ■

feedback@chauthiduniya.com

सैन्य ज़रूरतों की आपराधिक उपेक्षा

वर्ष 1999 में विशेषज्ञ टीम द्वारा की गई एसी युक्त टैंक खरीदने की सिफारिश बार-बार आगे बढ़ाई जाती रही, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. यह सैन्य ज़रूरतों की आपराधिक उपेक्षा का मामला है. सेना मुख्यालय के एसी कक्षों में बैठे रहने वाले अफसरों ने ही कहा कि टैंकों के कपोले (ढक्कन) खोलकर रखने से अंदर गर्मी नहीं लगती. ऐसे नाबालिग-वक्तव्य देने वाले अफसरों को यह नहीं समझ में आता कि युद्ध में टैंकों के कपोले खोलकर नहीं रखे जा सकते. दूसरा यह कि कपोले खोलकर रखने से धूल का गुबार टैंकों के अंदर भरता है, जिससे उपकरण खराब होते हैं और अंदर बैठे सैनिकों को सांस लेने में दिक्कत होती है. सैनिकों के मानसिक संतुलन पर भी खराब असर पड़ता है. इसके बावजूद टैंकों से एसी निकलवा कर उसकी खरीद होती रही. कहा गया कि बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो लगवा लिया जाएगा. इस बेवकूफाना तर्क को आधार बनाकर रक्षा मंत्रालय ने 2001 में एसी हटवा कर 310 टैंकों की खरीद फाइनल की. उसी वर्ष एक हज़ार और टैंकों की खरीद के लिए ऑर्डर जारी हुआ, उनमें भी एसी नहीं था. जब नए टैंकों के संवेदनशील उपकरण अत्यधिक गर्मी के कारण खराब होने लगे, तब रक्षा मंत्रालय ने 2002 में फिर सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया कि टैंकों में एसी लगना ज़रूरी है, लेकिन टैंकों में एसी लगाने का निर्णय लेने में ही चार साल लग गए. अवाडी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में एसी बनने का काम 2006 में शुरू हुआ और ट्रायल में ही फेल हो गया. 2008 में इस मामले को बंद कर दिया गया और बिना एसी के टैंक खरीदे जाने की प्रक्रिया जारी रही. इस दौरान (वर्ष 2014 तक) बिना एसी लगे तक़रीबन दो हज़ार टैंक खरीदे गए. इनमें एक ही क्रम में पहले 310 टैंक, फिर 1,000 टैंक और फिर 347 टैंक खरीदे गए. जब रक्षा मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया, तो उसने भी वही कहा कि टैंकों के कपोले खुले रखने से गर्मी नहीं लगती. रक्षा मंत्रालय ने गर्मी की वजह से संवेदनशील उपकरणों में आने वाली खराबी और सैनिकों के दिमागी असंतुलन के कारण होने वाले हादसों की बात दबा दी. ■

टेट्रा आर्मर्ड व्हीकल्स में भी एसी नहीं

थलसेना के बेतहाशा इस्तेमाल में आने वाली टेट्रा आर्मर्ड व्हीकल्स में भी एसी नहीं हैं. इसके बावजूद उन्हीं वाहनों में उबलते हुए फौजी अपना अभ्यास पूरा करते हैं. टेट्रा के घटिया आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह (मौजूदा केंद्रीय मंत्री) ने भी गंभीर सवाल उठाए थे. तब उन्हें तक़रीबन सात सौ घटिया वाहन खरीदने के बदले 14 करोड़ रुपये रिश्वत देने की पेशकश की गई थी. जनरल सिंह ने आरोप लगाया था कि सेना के लिए 7,000 टैट्रा ट्रक महंगी क़ीमत पर खरीदे गए थे और किसी ने सवाल तक नहीं उठाया था. जनरल सिंह का कहना था कि उक्त ट्रक मानकों के अनुरूप नहीं हैं और ऐसे क़रीब सात सौ ट्रकों का सौदा मंजूर करने के लिए उन्हें 14 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी. ■

रक्षा उपकरणों की खरीदारी में मोटा कमीशन खाने वाले नेताओं, नौकरशाहों और दलालों को भारतीय सैनिकों की अनिवार्य-सुविधा देखी नहीं जाती और कुछ हज़ार रुपये की एसी मशीनें टैंकों से निकलवा दी जाती हैं. हज़ारों करोड़ रुपये के टैंकों की खरीद में कुछ हज़ार की एसी मशीनें निकलवा कर सरकारी कोष को बचत कराई जा रही है या यह भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ डालने का क्रमश: प्रयास है

व्यक्तिगत आक्षेप ही हथियार

सुकांत

विशेष बिहार चुनाव

सत्ता-राजनीति की लीला अपरंपार है और बिहार विधानसभा चुनाव में इससे क़दम-क़दम पर साबका पड़ रहा है. सत्ता बचाने के लिए राजद, जद (यू) एवं कांग्रेस यानी महा-गठबंधन के नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कुछ भी करने को तत्पर हैं, तो वहीं सत्ता पर काबिज होकर विरोधियों को अपनी राजनीति का लोहा मनवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कुछ भी बाकी छोड़ने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते. बिहार ऐसी अहंवादी और वर्चस्ववादी राजनीतिक लड़ाई का पहला गवाह बन रहा है और वह पहली बार यह भी देख रहा है कि कोई प्रधानमंत्री चुनाव अभियान की लगाम अपने हाथ में रखकर सारा कुछ कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में दो दर्जन से अधिक सभाओं को संबोधित किया. पहले ही उन्होंने बिहार के चारों कोनों पर चार रैलियों और सरकारी आयोजन के नाम पर दो जनसभाओं को संबोधित करके माहौल सरगर्म कर दिया था. मोदी के सबसे विश्वस्त एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रत्येक प्रमंडल में कम से कम एक कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ-साथ लगभग सौ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं में भाग ले रहे हैं. मोदी सरकार के बिहारी मंत्री महीनों से सूबे में जमे ही नहीं, बल्कि दरवाजे-दरवाजे खाक छान रहे हैं. यही नहीं, आधा दर्जन से अधिक ग़ैर-बिहारी केंद्रीय मंत्री प्रतिदिन यहां आते हैं, मतदाताओं के राजनीतिक रुझानों के बारे में आधिकारिक बयान देते हैं और फिर रात बिताने दिल्ली लौट जाते हैं. एनडीए के तीर्थयात्रियों में यहां के चुनावी यज्ञ में खुद को अग्निहोत्र साबित करने की होड़ लगी है. उन्होंने इसे अपने राजनीतिक अस्तित्व से जोड़ लिया है, सबहिं नचावत मोदी-शाह गुसाईं.

इस चुनावी परिदृश्य में महा-गठबंधन के दलों की स्थिति दयनीय लगती है. उनके मित्रों में वैसी पार्टियां नहीं हैं, जो बिहार के चुनावी समर में एनडीए को सीमित दायरे में ही सही, परेशानी में डालकर परोक्ष मदद कर सकें. जैसे कई दल और नेता उनके विरोधियों के लिए कर रहे हैं. वस्तुत: राजद और जद (यू) हर व्यवहारिक नज़रिये से बिहारी दल ही हैं. महा-गठबंधन में कांग्रेस एकमात्र पार्टी है, जो राष्ट्रीय है, लेकिन उसके मददगारों की संख्या सीमित है. सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के अलावा किसी अन्य नेता में कांग्रेसियों और आम जन की कोई विशेष रुचि नहीं है. राजद की सारी राजनीतिक कथा लालू प्रसाद या उनके घर से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती है. राजनीति में रोज़गार तलाश रहे प्रमुख के साथ-साथ उनके घर से सभी (राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप एवं तेजस्वी) दल के स्टार प्रचारक हैं. जद (यू) में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के अलावा और भी राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने किसी में कोई चमक नहीं दिखती. हालांकि, महा-गठबंधन ने बार-बार स्वयं को राजनीतिक तौर पर एनडीए से ज़्यादा सुगठित और समावेशी जताने की कोशिश की. मसलन, विधानसभा चुनाव की हवा बननी शुरू हुई थी, तभी नीतीश कुमार को महा-गठबंधन का नेता घोषित कर दिया गया, सीटों का बंटवारा चुनाव अभियान की शुरुआत के साथ हो गया और महा-गठबंधन के सभी दलों की सीटों एवं प्रत्याशियों के नाम भी एक साथ घोषित कर दिए गए.

बिहार के चुनावी अखाड़े में मुख्यत: दो राजनीतिक धाराओं का ज़ोर है, बाकी सारे राजनीति समूह पांचवें सवार की तरह हैं. 243 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यत: महा-गठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार ही आमने सामने हैं. कुछ सीटों, जिनकी संख्या पचास से अधिक नहीं है, को अपवाद मान लिया जाए, तो बाकी क़रीब दो सौ सीटों पर तीसरे या चौथे राजनीतिक ध्रुवों के उम्मीदवारों की भूमिका महा-गठबंधन और एनडीए के आभा मंडल को चमकाने या धूमिल करने तक सीमित दिख रही है.

हालांकि, उसने एक साथ या शामिल दलों ने पृथक रूप से चुनाव घोषणा-पत्र जैसा कोई दस्तावेज़ जारी नहीं किया, पर एनडीए के दृष्टि-पत्र (विजन डॉक्युमेंट) जारी होने के एक माह पहले नीतीश कुमार ने सुशासन का सात सूत्रीय संकल्प-पत्र जारी कर दिया, जो उनका भावी कार्यक्रम है. राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने भी उसे ही अपना कार्यक्रम मान लिया, पर कांग्रेस मौन है. इसके अलावा समावेशी राजनीति कहीं और है या नहीं, इस बारे में सोचने पर निराशा होती है. प्रचार अभियान हो या कोई दूसरा राजनीतिक कार्यक्रम, महा-गठबंधन के दलों के शीर्ष नेता बहुधा साथ नहीं दिखते. राजद प्रमुख का अपना कार्यक्रम चलता है, तो नीतीश कुमार का अपना. कांग्रेस के नेता अपने तरीके से काम करते हैं. होर्डिंग्स और अन्य प्रचार सामग्रियों में समन्वय का स्तर बढ़ा है, पर वह स्वाभाविक राजनीति का आभास नहीं देता. ऐसा लगता है, महा-गठबंधन के घटक दलों के नेताओं में नज़रें चुराने का खेल चल रहा है. चूंकि बिहार में मतदाता समूहों की राजनीतिक गोलबंदी काफी तीखी है और ऐसे उत्तेजक माहौल में इसे लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन यह है तो नकारात्मक ही और इसका असर भी नकारात्मक हो सकता है.

इसके बरअक्स एनडीए ज़्यादा समावेशी और सुगठित होता जा रहा है. एनडीए में चुनाव अभियान ज़ोर पकड़ने के साथ-साथ एकजुटता की डोर मजबूत होती गई. यह अलग बात है कि कई मसलों और स्थितियों को लेकर भाजपा ने अपने राजनीतिक आचरण में चौधराहट दिखाई. एनडीए के प्रचार अभियान के कई आयाम हैं. भाजपा नेताओं के छह-सात समूह निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, कुछ प्रचारक सहयोगी दलों के साथ भी जाते हैं. सहयोगी दलों ने भी विशिष्ट अभियान चला रखा है. लोजपा, रालोसपा और हम के नेता क्षेत्र में खास तौर पर एक साथ जाते हैं. पटना हवाई अड्डे से प्रतिदिन क़रीब डेढ़ दर्जन हेलिकॉप्टर उड़ान भरते हैं, जिनमें एक दर्जन से अधिक में एनडीए के नेता होते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं के मंच पर एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहते हैं और सभी को मौक़ा मिलता है. मोदी का प्रचार अभियान भाजपा उम्मीदवारों के निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहता. वह मख्दुमपुर (जीतन राम मांझी का निर्वाचन क्षेत्र) गए और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी उनकी सभाएं हुईं. ऐसा ही अमित शाह के साथ है. कहने का मतलब यह कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए काम कर रहा है, कोई एक दल नहीं.

बिहार के चुनावी अखाड़े में मुख्यत: दो राजनीतिक धाराओं का ज़ोर है, बाकी सारे राजनीति समूह पांचवें सवार की तरह हैं. 243 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यत: महा-गठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार ही आमने सामने हैं. कुछ सीटों, जिनकी संख्या पचास से अधिक नहीं है, को अपवाद मान लिया जाए, तो बाकी क़रीब दो सौ सीटों पर तीसरे या चौथे राजनीतिक ध्रुवों के उम्मीदवारों की भूमिका महा-गठबंधन और एनडीए के आभा मंडल को चमकाने या धूमिल करने तक सीमित दिख रही है. समाजवादी पार्टी की पहल पर एनसीपी सांसद तारिक अनवर के नेतृत्व में गठित समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के उम्मीदवार राजद प्रमुख लालू प्रसाद के माय (मुस्लिम-यादव) समीकरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं. ऐसे राजनीतिक तत्वों की उपस्थिति बिहार चुनाव में सदैव रही है. क़रीब तीन दर्जन से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस मोर्चे के उम्मीदवार चुनाव में तीसरा कोण बना रहे हैं. यह एनडीए के लिए खुश होने का एक बड़ा कारण है. एनडीए वामपंथी दलों के मोर्चे के चलते भी लाभ की स्थिति में है. वामपंथी मोर्चे के दल भले कमज़ोर हों, पर सूबे के कई हिस्सों में उनकी उपस्थिति है. इस राजनीति के मतदाता समूह मूलत: लालू-नीतीश के नज़दीक रहे हैं. यह अनायास एनडीए के लिए लाभ वाली स्थिति हो गई है. वोट बैंक में इस सेंधमारी ने महा-गठबंधन की हालत पतली कर दी है, जिसकी कोई काट उसके पास नहीं है.

यही नहीं, महा-गठबंधन के नेता लालू प्रसाद की जुबान भी अपना काम कर रही है. पहले वह चुनाव को अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांटने की कोशिश में फंस गए. फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को नरभक्षी कहने की वजह से जांच के दायरे में आ गए. हिंदुओं के गोमांस खाने की चर्चा ने तो उन्हें राजनीतिक हमलों का केंद्र बना दिया. गोमांस प्रकरण ने उनके समर्थक हिंदू सामाजिक समूहों में भी हलचल पैदा कर दी है. हालात संभालने में महा-गठबंधन के नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में अमित शाह भी जांच के दायरे में हैं. उन्होंने लालू प्रसाद को चारा चोर कहा था. बहरहाल, चुनाव अभियान लगातार तल्ख होता जा रहा है. राजनीतिक दलों के पास मुद्दों का अभाव है. वे चर्चा भले विकास की करते हैं, पर सूबे के विकास की कोई रूपरेखा पेश करने में विफल रहे हैं. विकास के किसी मौलिक कार्यक्रम के बदले वे साइकिल, स्कूटी और लैपटॉप बांटने को ही विकास बता रहे हैं. कृषि विकास, औद्योगिक विकास या मानव विकास का कोई कार्यक्रम उनके पास नहीं है. ऐसे में प्रचार अभियान के दौरान दोनों राजनीतिक ध्रुवों के शिखर नेतृत्व से लेकर सामान्य नेता तक व्यक्तिगत आक्षेप की पूंजी से काम चला रहे हैं. बिहार को देने के लिए उनके पास इससे अधिक कुछ भी नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बागी बिगाड़ रहे दलीय उम्मीदवारों का खेल

सरोज सिंह

टिकटों के बंटवारे के बाद संभावित उम्मीदवारों की नाराज़गी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव में जो हो रहा है, वह यकीकन पिछली कहानियों से अलग है. लगभग सभी राजनीतिक दलों के आलाकमानों ने यह कल्पना नहीं की होगी कि टिकटों के बंटवारे के बाद पार्टी एवं शीर्ष नेताओं के ख़िलाफ़ संभावित उम्मीदवारों की नाराज़गी सार्वजनिक तौर पर इस वीभत्स रूप में सामने आएगी. खैर, नाराज़गी तो पार्टी ने झेल ली, पर जो दमदार नेता बागी होकर निर्दलीय या फिर दूसरे दलों से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी की जीत की गणित गड़बड़ कर दी है. चुनाव प्रचार चरम पर है, ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेता प्रयास कर रहे हैं कि बागियों को किसी न किसी तरह मना लिया जाए, पर बागी मानने के लिए तैयार नहीं हैं.

अनूप कुमार

बी एन प्रसाद

गुड्डी देवी

मनोरमा देवी

एमडी शम्स शाहनवाज

राजेश सिंह

राम धनी सिंह

राम जतन सिन्हा

सुमित कुमार

सतीश कुमार

एक मोटे अनुमान के अनुसार, बिहार विधानसभा की कम से कम 35-40 सीटों की गणित बागी अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, जिनमें से कुछ जीतने की स्थिति में हैं, तो कुछ ऐसे हैं, जो खुद भले न जीत पाएं, लेकिन दूसरे की नैया ज़रूर डुबो देंगे. सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जमुई ज़िले की चकाई. यहां से बतौर निर्दलीय नरेंद्र सिंह के पुत्र सुमित कुमार चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें एनडीए से टिकट मिलने की उम्मीद थी, पर ऐसा हो नहीं सका. इलाके में मजबूत पकड़ के बल पर सुमित कुमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फ़ैसला लिया और चकाई के मैदान में उतर गए. नतीजा यह कि एनडीए प्रत्याशी काफी पीछे चले गए और सुमित का मुक़ाबला राजद की सावित्री देवी से है. इसी तरह शेखपुरा में राजद के विजय सम्राट पप्पू यादव के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं. विजय सम्राट के कारण जदयू प्रत्याशी को यहां यादव वोटों का खासा नुक़सान हो रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम जतन सिन्हा इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने कुर्था से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फ़ैसला ले लिया. अब स्वाभाविक है कि राम जतन सिन्हा के फ़ैसले से महा-गठबंधन उम्मीदवार का काफी नुक़सान हो रहा है.

नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे राम धनी सिंह भी बागी होकर चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं. जदयू ने जब टिकट देने से मना किया, तो राघोपुर के विधायक सतीश कुमार ने बिना देर किए भाजपा का दामन थामा और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के ख़िलाफ़ अखाड़े में कूद गए. इसी तरह महुआ में जब लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के नाम की घोषणा की, तो वहां के संभावित प्रत्याशी जुगेश्वर राय ने विद्रोह का बिगूल फूंक कर पप्पू यादव के टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतरने का फ़ैसला कर लिया. अमनौर से राजद के सुनील राय ने भी लालू की एक नहीं सुनी और बागी होकर चुनावी अखाड़े में उतर गए. नतीजा यह हुआ कि जदयू प्रत्याशी मंटू सिंह की हालत पतली हो गई. सीतामढ़ी एवं शिवहर ज़िले के तक़रीबन एक दर्जन बेटिकट कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व को सबक सिखाने की तैयारी में लगे हैं. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही संबंधित क्षेत्र की चुनावी तस्वीर अलग होने की चर्चा शुरू हो गई है. सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से वैश्य बिरादरी की लोजपा की पूर्व विधायक नगीना देवी बतौर वैश्य समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. अगर उनकी चुनावी गणित सफल रही, तो साफ़ है कि वह एनडीए के भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू और महा-गठबंधन के राजद प्रत्याशी सुनील कुशवाहा के लिए सिरदर्द बन सकती हैं.

रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक गुड्डी देवी ने जदयू पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया. भूमिहार बिरादरी की इस महिला प्रत्याशी को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है. अगर यही आलम रहा, तो एनडीए और महा-गठबंधन की ऐंठन धरी रह जाएगी. ज़ाहिर है, एनडीए के रालोसपा प्रत्याशी पंकज कुमार मिश्रा और महा-गठबंधन की राजद प्रत्याशी मंगीता देवी की परेशानी बढ़ सकती है. परिहार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मोहम्मद शम्स शहनवाज भी बागी रुख अख्तियार कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर गए हैं. इसका असर महा-गठबंधन प्रत्याशी एवं राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे के चुनाव नतीजे पर पड़ने की संभावना है. इसी सीट से भाजपा की ज़िला परिषद सदस्य सरिता यादव जन अधिकार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके एनडीए की स्वजातीय प्रत्याशी गायत्री देवी का खेल बिगाड़ने में लगी हैं. सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव ने बतौर स्वतंत्र प्रत्याशी चुनाव लड़ने की घोषणा करके महा-गठबंधन प्रत्याशी सैयद अबु दोजाना का खेल बिगड़ने का रास्ता साफ़ कर दिया है. बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद के चुनावी समर में उतरने की चर्चा ज़ोरों पर है. अगर इसमें सच्चाई है, तो एनडीए और महा-गठबंधन, दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं. इस सीट से रालोसपा के रवींद्र कुमार शाही ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने की घोषणा की है. उनके आगमन के बाद एनडीए की रालोसपा प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता की परेशानी बढ़ सकती है. शिवहर में भी चुनावी समीकरण बदलने की संभावना है. राजद के पूर्व विधायक अजित कुमार झा ने इस बार समाजवादी पार्टी का झंडा थामकर चुनावी समर में उतरने की घोषणा कर दी है. वहीं दूसरी ओर राजपूत बिरादरी के ठाकुर रत्नाकर राणा ने भाजपा से खफा होकर जन समर्थन के बूते स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है. अगर दोनों चुनावी समर में डटे रहते हैं, तो इस सीट से जदयू विधायक सह प्रत्याशी की चुनावी राह आसान हो सकती है. वैसे चुनावी समीकरणों में जोड़-तोड़ की आजमाइश अभी थमी नहीं है. नाम वापसी के बाद ही साफ़ हो सकेगा कि किस क्षेत्र में कौन बागी निर्दल से हटकर दलगत का समर्थन करता है.

गोपालगंज ज़िले के कुल छह विधानसभा क्षेत्रों में टिकट बंटवारे को लेकर संबंधित दलीय कार्यकर्ता अपना विरोध जता रहे हैं. जहां तक उम्मीदवारों की बात है, तो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों को जनता नकारेगी या स्वीकारेगी, यह तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन बागियों के चुनाव मैदान में होने से नतीजे अप्रत्याशित होंगे, यह तय है. गोपालगंज में टिकट न मिलने से भाजपा को बागियों से सामना करना पड़ रहा है. भाजपा का दामन थामे कई नेता चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जो चुनावी फिजा बदल सकते हैं. अगर हथुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहां का नजारा दिलचस्प है. एनडीए के सहयोगी हम के खाते में यह सीट जाने से भाजपा नेता राजेश कुमार सिंह ने बतौर निर्दलीय ताल ठोक दी है. हथुआ विधानसभा क्षेत्र से महा-गठबंधन से राम सेवक सिंह और एनडीए सहयोगी हम से महाचंद प्रसाद चुनाव मैदान में हैं. हथुआ कोयरी-कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है. इन्हीं वोटरों पर राम सेवक सिंह और राजेश कुमार सिंह की नज़र है तथा दोनों एक ही जाति के हैं. राजेश कुमार सिंह के बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है. अनूप कुमार श्रीवास्तव गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया. अनूप पार्टी से नाराज़ होकर बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं.

बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से टिकट के लिए एक दर्जन नेता आमने-सामने थे, लेकिन भाजपा ने मिथलेश तिवारी को उम्मीदवार बना दिया. टिकट न मिलने से क्षुब्ध पूर्व विधायक देवदत्त राय की पत्नी मनोरमा देवी बतौर निर्दलीय और अनूप कुमार तिवारी बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं. ये दोनों एनडीए और महा-गठबंधन को नुक़सान पहुंचा सकते हैं. बरौली विधानसभा क्षेत्र से राजू सिंह को जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तो वह सपा का दामन थामकर चुनाव मैदान में उतर गए. गया ज़िले के दस विधानसभा क्षेत्रों में से पांच ऐसे हैं, जहां के चुनावी समीकरण बागी प्रत्याशियों के कारण बिगड़ सकते हैं. देखा जाए, तो बागियों की ताकत कई सीटों पर जीत-हार तय करने वाली है. बागियों के संकट को अमित शाह ने काफी गंभीरता से लिया है और अपने स्तर से उसे कम करने के लिए यथासंभव प्रयास भी किए. उनके प्रयास कितने सफल रहे, यह तो आठ नवंबर को नतीजे आने के बाद पता चल पाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार चुनाव विशेष

अगर पहले चरण के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और उनकी दलगत स्थिति का जायजा लिया जाए, तो यह साफ़ हो जाता है कि पिछली विधानसभा की तरह आने वाली विधानसभा भी अपराधियों से मुक्त नहीं होगी. विधानसभा में आपराधिक छवि वाले विधायकों की संख्या में बढ़ोत्तरी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. पिछले चुनाव की भांति इस बार भी आपराधिक छवि वाले बहुत सारे उम्मीदवार साफ़ छवि के उम्मीदवारों को हराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनकी जीत वास्तव में जनता की पराजय होगी.

कहती है एडीआर रिपोर्ट

कोई दल पाक-साफ़ नहीं

शफीक आलम

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों के आधार पर उनके वित्तीय, आपराधिक एवं अन्य विवरणों पर एक रिपोर्ट जारी की है. साथ में एडीआर ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मतदाताओं से अच्छी-साफ़ छवि वाले उम्मीदवारों को वोट देने और यदि साफ़ छवि का उम्मीदवार न हो, तो नोटा का इस्तेमाल करने की अपील की गई है. यह रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव मैदान में मौजूद सभी राजनीतिक दल विकास की बात कर रहे हैं, सुशासन भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सभी दलों के बीच आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार मैदान में उतारने के आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है. भाजपा नीतीश के नेतृत्व वाले महा-गठबंधन पर जंगलराज वापस लाने की कोशिश करने का आरोप लगा रही हैं, वहीं खुद भाजपा के नेता अपनी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं. ऐसे में एडीआर द्वारा जारी यह रिपोर्ट क्या कहती है, उस पर एक नज़र डालना आवश्यक हो जाता है.

जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया गया है कि चुनाव में उतरे सभी राजनीतिक दल विकास एवं सुशासन को अपना चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन एडीआर द्वारा जारी आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं. दरअसल, दागी और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने में कोई भी दल पीछे नहीं है यानी चुनाव जिताऊ उम्मीदवार उनके लिए नैतिकता से ऊपर हैं. एडीआर रिपोर्ट में पहले चरण में चुनाव मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया है. कुल 587 उम्मीदवारों में से 174 यानी 30 प्रतिशत उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं, जिनमें से 130 पर गंभीर मामले चल रहे हैं. पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची देखकर बाकी के चरणों के उम्मीदवारों की छवि का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है.

बिहार में पिछले कई चुनावों से राजनीति का अपराधीकरण एक अहम मुद्दा रहा है. चुनाव के दौरान और बाद भी राज्य में सक्रिय तक़रीबन हर राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को इतने ज़ोर-शोर से उठाया कि उसे देखते हुए कम से कम यह उम्मीद रखी जा सकती थी कि सभी नहीं, तो अधिकतर दल, खास तौर पर बड़े दल इसे नापसंद करते हुए आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे. लेकिन, सच्चाई इसके ठीक उलट है. इस दलदल में सभी पार्टियां गर्दन तक डूबी हैं, चाहे वह सुशासन का दावा करने वाली हो, पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली हो या फिर दूसरी पार्टियों को जंगलराज का पर्याय बताने वाली. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पहले चरण के उम्मीदवारों द्वारा स्वघोषित आपराधिक मामलों पर एक निगाह डालना ही काफी है.

जनता को अपना वोट देने का जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार उसे अपने उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का भी है. मतदाता के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि जो लोग चुनाव मैदान में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, उनकी छवि कैसी है? बहरहाल, अगर मैदान में मौजूद उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को दलवार देखा जाए, तो भाजपा के 27 में से 14 (52 प्रतिशत), सीपीआई के 25 में से 14 (56 प्रतिशत), बसपा के 41 में से आठ (20 प्रतिशत), जदयू के 20 में से 11 (46 प्रतिशत), सपा के 18 में से नौ (50 प्रतिशत), राजद के 17 में से आठ (47 प्रतिशत), कांग्रेस के आठ में से छह (75 प्रतिशत) और लोजपा के 13 में से आठ (62 प्रतिशत) उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. जहां तक गंभीर मामलों का सवाल है, तो भाजपा के 27 में से 10 (37 प्रतिशत), सीपीआई के 25 में से सात (28 प्रतिशत), बसपा के 41 में से छह (15 प्रतिशत), जदयू के 20 में से नौ (38 प्रतिशत), सपा के 18 में से सात (39 प्रतिशत), राजद के 17 में से छह (35 प्रतिशत), कांग्रेस के आठ में से चार (50 प्रतिशत) और लोजपा के 13 में से छह (46 प्रतिशत) उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं.

16 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या के आरोप की घोषणा की है, जिनमें वारसलीगंज के जदयू उम्मीदवार एवं वर्तमान विधायक प्रदीप कुमार भी शामिल हैं, जिन पर हत्या के चार मामले दर्ज हैं. बाकी उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या के एक-एक मामले की घोषणा की है. हत्या का प्रयास करने के मामले घोषित करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 37 है. हिसवा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार राम स्वरूप यादव पर सबसे अधिक पांच मामले दर्ज हैं. बाकी उम्मीदवारों में जदयू के तीन, भाजपा, बसपा एवं जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के एक-एक और एक निर्दलीय शामिल हैं. ग़ौरतलब है कि पिछली विधानसभा (2010) में एडीआर ने 243 विधायकों में से 242 के हलफनामों का अध्ययन किया था. इनमें से 141 (58 प्रतिशत) विधायक ऐसे थे, जिनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले लंबित थे. 2005 की विधानसभा में यह संख्या 117 (50 प्रतिशत) थी. 2010 की विधानसभा में गंभीर आपराधिक मामले वाले विधायकों की संख्या 85 थी.

अगर पहले चरण के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और उनकी दलगत स्थिति का जायजा लिया जाए, तो यह साफ़ हो जाता है कि पिछली विधानसभा की तरह आने वाली विधानसभा भी अपराधियों से मुक्त नहीं होगी. विधानसभा में आपराधिक छवि वाले विधायकों की संख्या में बढ़ोत्तरी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. पिछले चुनाव की भांति इस बार भी आपराधिक छवि वाले बहुत सारे उम्मीदवार साफ़ छवि के उम्मीदवारों को हराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनकी जीत वास्तव में जनता की पराजय होगी. चुनाव में पार्टियों को कामयाबी तक पहुंचाने में ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल होता है. चूंकि आम कार्यकर्ता ग़रीब होता है और चुनाव में खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वह ज़मीन से जुड़ा होने के बावजूद चुनाव नहीं लड़ पाता. राजनीतिक दलों पर करोड़पतियों से पैसे लेकर टिकट देने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं. यह चुनाव भी ऐसे आरोपों से मुक्त नहीं है. इसमें बड़ी-छोटी सभी पार्टियां शामिल हैं. हाल में भाजपा सांसद आरके सिंह ने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है.

बहरहाल, चुनाव आम आदमी की पहुंच से कितनी दूर चला गया है, इसका अंदाज़ा बिहार जैसे ग़रीब राज्य के उम्मीदवारों की घोषित संपत्तियों से ही लगाया जा सकता है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चरण के उम्मीदवारों में 146 (25 प्रतिशत) करोड़पति हैं. अगर कुल उम्मीदवारों की घोषित आय का औसत निकाला जाए, तो यह 1.44 करोड़ रुपये प्रति उम्मीदवार होगी. अगर दलगत स्थिति देखी जाए, तो भाजपा के 27 में से 18 (67 प्रतिशत), जदयू के 24 में से 19 (71 प्रतिशत), राजद के 17 में से 11 (65 प्रतिशत), सपा के 18 में से छह (33 प्रतिशत), कांग्रेस के आठ में से छह (75 प्रतिशत) और लोजपा के 13 में से आठ (32 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं. यही नहीं, 23 उम्मीदवारों ने अपनी आय एक करोड़ रुपये से अधिक घोषित की, लेकिन उन्होंने अपना आयकर रिटर्न पेश नहीं किया. वारिस नगर विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बिनोद कुमार सिंह 74 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरे नंबर पर खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी पूनम देवी यादव हैं, जिनके पास 42 करोड़ रुपये की संपत्ति है. बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनहित दल के उम्मीदवार सुरेश सदा और हिसुआ से मूल निवासी समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप राजबंशी ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है.

जहां तक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, तो तीन उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने खुद को निरक्षर घोषित किया है. जबकि 52 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने खुद को साक्षर बताया है. 332 (57 प्रतिशत) उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या उससे कम बताई है, जबकि 241 (41 प्रतिशत) ने स्नातक या उससे अधिक योग्यता ज़ाहिर की है. जहां तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल है, तो वह भी काफी निराशाजनक है. कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या केवल 56 (नौ प्रतिशत) है. सत्ता में महिलाओं की भागीदारी यूं ही सवालों के घेरे में है. अक्सर आधी आबादी को सत्ता में भागीदारी देने की बात कही जाती है. बिहार में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण हासिल है. बावजूद इसके महिला उम्मीदवारों की संख्या में कमी चिंताजनक है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा शगुन नहीं है. इस संबंध में भी राजनीतिक दलों को सोचने की ज़रूरत है. कुल मिलाकर पहले चरण के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि सरकार चाहे जिसकी बने, विधानसभा की तस्वीर पहले से भिन्न नहीं होगी. ■

shafique.aalam@gmail.com

एडीआर की नज़र में गंभीर आपराधिक मामले

1. पांच साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध.
2. ग़ैर ज़मानती अपराध.
3. चुनाव से संबंधित अपराध (धारा 171 या रिश्वतखोरी).
4. सरकारी खजाने को नुक़सान पहुंचाने से संबंधित अपराध.
5. हमला, हत्या, अपहरण एवं बलात्कार से संबंधित अपराध.
6. लोक प्रतिनिधि अधिनियम में उल्लेखित अपराध (धारा 8).
7. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध.
8. महिलाओं के ऊपर अत्याचार संबंधी अपराध.

बिहार में पिछले कई चुनावों से राजनीति का अपराधीकरण एक अहम मुद्दा रहा है. चुनाव के दौरान और बाद भी राज्य में सक्रिय तक़रीबन हर राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को इतने ज़ोर-शोर से उठाया कि उसे देखते हुए कम से कम यह उम्मीद रखी जा सकती थी कि सभी नहीं, तो अधिकतर दल, खास तौर पर बड़े दल इसे नापसंद करते हुए आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे. लेकिन, सच्चाई इसके ठीक उलट है.

नेताओं के लिए उम्र के कोई मायने नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव में हलफनामों को लेकर भी एक विवाद खड़ा हो गया है, जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्रों तेज प्रताप यादव एवं तेजस्वी यादव से जुड़ा है. लालू यादव के दोनों पुत्र चुनाव मैदान में हैं. उन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में अपनी जो आयु बताई है, वह विवादों के घेरे में आ गई है. इस विवाद का दिलचस्प एवं हास्यास्पद पहलू यह है कि छोटे भाई की उम्र अधिक हो गई है और बड़े भाई की उम्र कम. तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर अपनी सफ़ाई पेश की कि मतदाता सूची की त्रुटि के कारण दोनों भाइयों की उम्र में अंतर पैदा हुआ और यह सब क़ानून के मुताबिक हुआ. बहरहाल, सच्चाई जो भी हो, लेकिन मतदाता सूचियों में लोगों के नाम और उम्र में गड़बड़ी

की शिकायत कोई नई और अनोखी बात नहीं है. ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं. मसलन, बिहार में ही ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, जिनकी उम्र ने ऐसी हास्यास्पद स्थिति न पैदा की हो. मिसाल के तौर पर दरभंगा के भाजपा सांसद कीर्ति झा आज़ाद की उम्र वर्ष 2009 में 48 वर्ष थी, जो 2014 में 55 वर्ष हो गई. कीर्ति आज़ाद ने 10 वर्षों में 12 वर्षों का सफ़र तय कर लिया. इसी तरह राजद के जयप्रकाश नारायण यादव की उम्र वर्ष 2004 में 54 वर्ष थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी उम्र 60 वर्ष बताई गई, जबकि दोनों चुनावों के बीच 10 वर्ष का फासला है. वर्तमान में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है. वर्ष 2004 में उनकी उम्र 56 वर्ष थी और 2009 में 59 वर्ष. यदि दो या दो से अधिक चुनाव लड़े सभी उम्मीदवारों की उम्र का जायजा लिया जाए, तो यह सूची बहुत लंबी हो जाएगी. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को स्वयं से संबंधित जानकारियों के बारे में जो हलफनामा यानी शपथ-पत्र दिया जाता है, उसमें इस तरह की ग़लत बयानी क्यों की जाती है? ज़ाहिर है, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है, वह इतनी बड़ी ग़लती नहीं करेगा कि दो अलग-अलग हलफनामों में परस्पर विरोधाभासी जानकारी देगा. यहां कमी चुनाव आयोग की भी है. अगर चूक चुनाव आयोग की तरफ़ से हो रही है, जैसा तेजस्वी यादव ने दावा किया है, तो उसे इसे फ़ौरन दुरुस्त करना चाहिए. दूसरे यह कि यदि ग़लती उम्मीदवारों की तरफ़ से हो रही है, तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वरना ऐसे हलफनामों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ■

नरेंद्र मोदी को यह एहसास है कि बिहार की जंग जीतने के लिए यदुवंशियों का दिल जीतना बेहद ज़रूरी है. इसलिए वह अपनी लगभग सभी सभाओं में स्थानीय मुद्दों का उल्लेख करने के बाद सारा फोकस यदुवंशियों को रिझाने में कर रहे हैं. उनका सीधा-सीधा निशाना लालू प्रसाद पर है. सभा में उमड़ी भीड़ की ओर मुखातिब होते नरेंद्र मोदी कहते हैं, अब लालू प्रसाद की नौटंकी नहीं चलेगी. यह 1990 नहीं है, अब साल 2015 चल रहा है. लालू प्रसाद को बिहार की जनता को यह बताना चाहिए कि देश के क़ानून ने उन्हें चुनाव लड़ने से क्यों रोक दिया.

मोदी मैजिक पर एनडीए की नैया

सरोज सिंह

बिहार चुनाव विशेष

भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में उमड़ रही भीड़ को अगर पैमाना मान लिया जाए, तो यह कहने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की नैया पार लगाने की पूरी ज़िम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पर है. बिहारी वोटरों की भारी भीड़ तपती गर्मी में भी नरेंद्र मोदी को सुनने आ रही है और सभा के बाद उनके द्वारा कही गई बातों पर ग़ौर कर रही है. चूंकि एनडीए अपना चुनाव नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर ही लड़ रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा उम्मीद उन्हीं से है और नरेंद्र मोदी इस मामले में एनडीए को निराश भी नहीं कर रहे हैं. अपनी ताबड़तोड़ रैलियों में नरेंद्र मोदी अब साफ़ कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव विकासराज और जंगलराज के बीच है और निर्णय बिहार की महान जनता को करना है. जनता से सवाल-जवाब की शैली में नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में आई भारी भीड़ से पूछते हैं, आपको जंगलराज दोबारा चाहिए कि विकासराज? वह कहते हैं, आप एक निर्णय कीजिए, मैं बिहार के भाग्य को बदल कर रख दूंगा.

नरेंद्र मोदी को यह एहसास है कि बिहार की जंग जीतने के लिए यदुवंशियों का दिल जीतना बेहद ज़रूरी है. इसलिए वह अपनी लगभग सभी सभाओं में स्थानीय मुद्दों का उल्लेख करने के बाद सारा फोकस यदुवंशियों को रिझाने में कर रहे हैं. उनका सीधा-सीधा निशाना लालू प्रसाद पर है. सभा में उमड़ी भीड़ की ओर मुखातिब होते नरेंद्र मोदी कहते हैं, अब लालू प्रसाद की नौटंकी नहीं चलेगी. यह 1990 नहीं है, अब साल 2015 चल रहा है. लालू प्रसाद को बिहार की जनता को यह बताना चाहिए कि देश के क़ानून ने उन्हें चुनाव लड़ने से क्यों रोक दिया. गुस्से में पता नहीं, वह क्या-क्या खाने की बात कर रहे हैं और बाद में कहते हैं कि मेरे मुंह में शैतान घुस गया. अब यह सोचने की बात है कि करोड़ों लोगों को छोड़कर शैतान ने लालू जी का ही ठिकाना क्यों चुना?

नरेंद्र मोदी को नज़दीक से जानने वाले बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की गणित यह कहती है कि अगर यादवों के वोटों में 25 से 30 फ़ीसद भी बंटवारा हो गया, तो बिहार में अकेले अपने दम पर भाजपा की सरकार बन सकती है. अगर यह विभाजन ज़्यादा हुआ, तो दो तिहाई बहुमत से भी सरकार बन सकती है. इसलिए अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी सबसे अधिक आलोचना लालू प्रसाद की कर रहे हैं और यदुवंशियों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें सत्ता में सम्मानजनक भागीदारी मिलेगी. नरेंद्र मोदी बार-बार जंगलराज का ज़िक्र कर रहे हैं. भीड़ से वह पूछते हैं, आपको विकासराज चाहिए या जंगलराज? जंगलराज ने बिहार में बस फिरौती उद्योग लगाया. विकास की जब बात आती है, तो वह कहते हैं, सूबे की सभी सरकारों ने यहां की दो ताकतों की अनदेखी कर दी. पहली ताकत यहां का पानी और दूसरी यहां की जवानी. यही दो ताकतें न केवल बिहार, बल्कि पूरे भारत का भाग्य बदल सकती हैं. बिहार के कुछ इलाकों में इतना पानी है कि जिसके लिए हिंदुस्तान के कई इलाके तरसते हैं. यहां के युवा दूसरे राज्यों का भाग्य बदल रहे हैं. अगर इन दोनों ताकतों का ही बिहार में उपयोग कर लिया जाए, तो बिहार को कहीं दूसरी जगह ताकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी.

अपनी सभाओं में नरेंद्र मोदी महा-गठबंधन पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे हैं. वह कहते हैं, लालू, नीतीश और कांग्रेस ने महा-गठबंधन नहीं, बल्कि महा-स्वार्थबंधन बनाया है. कांग्रेस ने बिहार में 35 साल, बड़े भाई लालू ने 15 साल और छोटे भाई नीतीश कुमार ने दस साल राज किया. इन तीनों की वजह से बिहार की तीन पीढ़ियां बर्बाद हो गईं, लेकिन अब यह नहीं होगा. बिहार को बढ़ाना होगा, उसे पढ़ाना होगा.

अपनी सभाओं में नरेंद्र मोदी महा-गठबंधन पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे हैं. वह कहते हैं, लालू, नीतीश और कांग्रेस ने महा-गठबंधन नहीं, बल्कि महा-स्वार्थबंधन बनाया है. कांग्रेस ने बिहार में 35 साल, बड़े भाई लालू ने 15 साल और छोटे भाई नीतीश कुमार ने दस साल राज किया. इन तीनों की वजह से बिहार की तीन पीढ़ियां बर्बाद हो गईं, लेकिन अब यह नहीं होगा. बिहार को बढ़ाना होगा, उसे पढ़ाना होगा. नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं कि ये तीनों केवल कुर्सी के लिए एक हुए हैं, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है. नरेंद्र मोदी की सभाएं जिन इलाकों में हो रही हैं, वहां तो एनडीए में जोश बढ़ ही रहा है, पर इसका दूसरा फ़ायदा यह हो रहा है कि टीवी और अख़बारों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों तक उनका संदेश प्रमुखता से पहुंच रहा है. इससे दूसरे इलाकों में भी नरेंद्र मोदी के भाषणों पर बहस छिड़ती जा रही है. नरेंद्र मोदी बिना लाग लपेट अपनी बात कह रहे हैं, जो लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रही है. नरेंद्र मोदी की सभाओं का एक फ़ायदा यह भी दिख रहा है कि भाजपा के भीतर जो अंतर्विरोध कई सारी सीटों को लेकर स्थानीय स्तर पर उभर आया था, वह स्वत: ख़त्म होता जा रहा है. पक्ष हो या विपक्ष, सारी बहस उनके बयानों और सवालों पर आकर सिमटती जा रही है. नरेंद्र मोदी की सभाओं में जिस तरह भीड़ आ रही है, उससे साफ़ है कि उनके प्रति बिहार के लोगों का आकर्षण बरकरार है.

जहां तक महा-गठबंधन का सवाल है, तो लालू प्रसाद स्टार प्रचारक के तौर पर उभरे हैं. उनकी सभाओं में भी अच्छी भीड़ आ रही है और वह भी अपना संदेश बहुत साफ़ शब्दों में दे रहे हैं. लालू अपने माय यानी मुसलमान और यादव समीकरण को ही दुरुस्त करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं. लालू यादव को भी एहसास है कि भाजपा की पूरी ताकत यादवों के वोट बांटने में लगी है, इसलिए वह अपनी हर सभा में उन्हें सतर्क कर रहे हैं. लालू प्रसाद कहते हैं, मंडलराज को फिर से लाना है, तो सभी पिछड़ों को साथ देना होगा. जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो उनके भाषणों में दो बातों पर विशेष ज़ोर रहता है, नरेंद्र मोदी की आलोचना और बिहार का स्वाभिमान. नीतीश कहते हैं, अगर बिहार की जनता मुझे वोट नहीं देगी, तो लूजर वह होगी, मैं नहीं. मेरा तो पूरा फोकस बिहार के विकास पर है और यह आगे भी जारी रहेगा. नीतीश कुमार कहते हैं, मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो टेस्टेड हूं. अब अनाप-शनाप वादे करने वाले समझें कि जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी? उधर कांग्रेस का प्रचार अभियान बिखरा-बिखरा लग रहा है. सोनिया और राहुल गांधी की सभाओं का बहुत कम असर जनता पर हो रहा है. यह कहना ग़लत नहीं होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी लालू और नीतीश के भरोसे ही चुनावी अखाड़े में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार तो अपने-अपने खेमे के लिए ज़ोर लगा रहे हैं. अब यह जनता को तय करना है कि उसे किसकी बात सबसे ज़्यादा रास आई. ■

feedback@chauthiduniya.com

जावेद बनेंगे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत!

इस्लाम की जन्मस्थली सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त करने के लिए एक अच्छे मुस्लिम चेहरे की तलाश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही. भारतीय विदेश सेवा में कोई ऐसा अधिकारी मिल नहीं रहा. और जो हैं, वे या तो अभी कनिष्ठ हैं या फिर जाने में हिचक रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, दौड़ में काफी नाम आए और कटते चले गए. सऊदी अरब में भारतीय राजदूत की नियुक्ति ज़रूरी होती जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां और इजरायल जाने का कार्यक्रम इसी वर्ष के अंत या अगले वर्ष की शुरुआत तक बनना तय है. बिना भारतीय राजदूत के मोदी का वहां जाना हास्यास्पद जैसा होगा. चौथी दुनिया का यह अंक छपने तक, एक नाम पर पीएमओ में काफी विचार-विमर्श हुआ. वह हैं, मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने जावेद का नाम चलाया है. कहा जाता है कि वह मोदी के अमेरिका यात्रा पर जाने से पहले दिल्ली आए थे और विशेष अधिकारियों से मिलकर गए. जावेद को लेकर पीएमओ और विदेश मंत्रालय के एक वर्ग में ज़्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि हाल में चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार हुई इंद्राणी मुखर्जी एवं उनके पति पीटर मुखर्जी की जावेद से दोस्ती जगजाहिर हो गई है. इंद्राणी मुखर्जी द्वारा जेल में आत्महत्या की कथित कोशिश ने मुंबई पुलिस-प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया है.

जावेद भारतीय पुलिस सेवा के 1980 बैच के अधिकारी हैं और वह लखनऊ के एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं. कुछ समय तक उन्होंने दिल्ली पुलिस में भी काम किया. वह मुंबई के पेज थ्री वर्ग में एक जाने-माने चेहरे रहे हैं. मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें उस समय पुलिस कमिश्नर बना दिया, जब राकेश मारिया शीना हत्याकांड की जांच बतौर पुलिस कमिश्नर बहुत बारीकी से कर रहे थे. मारिया को अचानक हटाने के बाद मीडिया और पुलिस में शक की सुइयां घूमने लगीं और कुछ दिनों में ही जावेद को मानना पड़ा कि वह इंद्राणी एवं पीटर मुखर्जी को अच्छी तरह से जानते हैं और वे उनकी ईद की दावत में आए थे. अब इंद्राणी द्वारा आत्महत्या की कथित कोशिश से शक गहरा गया है कि कहीं कोई इंद्राणी को मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इस सबके बीच जावेद का नाम सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के पद की दौड़ में शामिल होना दाल में कुछ काला होने का इशारा कर रहा है. जावेद कुछ दिनों बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं. एक पुलिस अधिकारी को इतने महत्वपूर्ण देश में राजदूत बनाकर भेजने का विचार यह दर्शाता है कि उन्हें अच्छा पुरस्कार देने की कोशिश की गई है. लेकिन सवाल उठता है क्यों? भारतीय विदेश सेवा के किसी अधिकारी को न भेजना तय है, लेकिन देश में कई अच्छे मुस्लिम चेहरे हैं. हां, यह ज़रूर है कि मोदी सरकार उन्हें अपना नहीं मानती.

सवाल यह उठता है कि जावेद ने ऐसा क्या किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फणनवीस उन पर इतने फिदा हैं कि उन्होंने दिल्ली में उनका नाम इस पद के लिए चलवा दिया? कहा जा रहा है कि जावेद फणनवीस के क्षेत्र नागपुर से उन्हें जानते हैं. सऊदी अरब सबसे अधिक भारत को तेल बेचता है. मिडिल-ईस्ट में सबसे अधिक भारतीय वहां काम करते हैं. आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में सऊदी अरब ने भारत की काफी मदद की है और कई जेहादी तत्वों को उसने भारत को सौंपा है. सूत्रों के अनुसार, भारतीय राजदूत के चयन पर आख़िरी फ़ैसला प्रधानमंत्री के इशारे पर होगा और इस चयन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अहम भूमिका मानी जा रही है. इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कहीं दूर-दूर तक दखलंदाज़ी नहीं है. नाम का चयन होने पर केवल उन्हें बता दिया जाएगा. विदेश सेवा के इतिहास में किसी कैबिनेट मंत्री का इतना अनादर कभी नहीं हुआ.

अहमद जावेद

आसिफ इब्राहिम

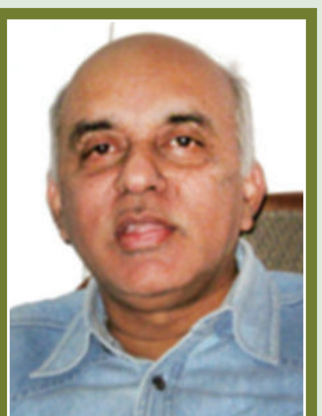
नावेद मसूद

विदेश सेवा में 31 जुलाई तक तीन डिप्लोमेट्स के नाम तय होने थे. शिकागो में तैनात एक मुस्लिम अधिकारी ने मना कर दिया. वह अभी सऊदी अरब नहीं जाना चाहते. वैसे वह मिडिल-ईस्ट में काम कर चुके हैं. तब शुरुआत हुई कोई अच्छा मुस्लिम चेहरा तलाशने की, जो राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में जाना-पहचाना जाता हो. विदेश सेवा से ही एक नाम उभरा, एनआरआई रियाज़ नकवी का. वह एक सेवानिवृत्त सीनियर टेक्नोकेट ऑफिसर हैं. राजीव गांधी सरकार के समय देश में आईटी टेक्नोलॉजी लाने में उनका अहम योगदान रहा. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय उन्हें अमेरिका के सिलिकॉन वैली में प्रथम आईटी राजदूत बनाकर भेजा गया. यह अपने किस्म की पहली डिप्लोमेटिक पोस्ट थी, जिसका अमेरिका में भारतीय दूतावास से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन आईटी मिनिस्टर प्रमोद महाजन से मतभेद होने पर उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था. सुन्नी मुसलमान नकवी उत्तर प्रदेश के जाने-माने परिवार से संबंध रखते हैं. उनके बड़े भाई ज़फर नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री रहे और बाद में नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन बने. यूपीए-2 में ज़फर लखीमपुर खीरी से लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन रियाज़ नकवी ने अपने बड़े भाई के राजनीतिक क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं ली. उन्होंने एक सरकारी अधिकारी के तौर पर लगन से काम किया. विदेश सेवा के उच्चाधिकारियों ने रियाज नकवी को सऊदी अरब भेजने में काफी रुचि दिखाई है. भाजपा के राज्यसभा सदस्य एवं पत्रकार एमजे अकबर का नाम भी उनके संसद में आने से पहले चला. अकबर लंदन में भारतीय उच्चायोग में जाना चाहते थे, फिर उन्होंने सऊदी अरब में राजदूत पद के लिए सोचा और उसके बाद कतर में राजदूत बनने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन मोदी को लगा कि वह संसद में ही ठीक रहेंगे. अकबर अब मंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं. सऊदी अरब में राजदूत बनाने के लिए भाजपा सांसद आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम चला, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं. एचडी देवगौड़ा सरकार में मंत्री रहे सीएम इब्राहिम का नाम भी सुझाया गया, लेकिन पीएमओ ने उसे फौरन काट दिया. इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आसिफ इब्राहिम के नाम पर भी काफी ग़ौर हुआ है. यह नाम अभी भी सूची में है, लेकिन मोदी सरकार में एक वर्ग का मानना है कि आसिफ का बैकग्राउंड शायद सऊदी अरब में एक अच्छा संकेत न भेजे. आसिफ इब्राहिम भी वहां जाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. वह पीएमओ में स्पेशल सेक्रेटरी-एंटी टेरर पद पर काम कर रहे हैं.

कॉरपोरेट मंत्रालय में सचिव पद से सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवा के नावेद मसूद भी शार्टलिस्ट हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में विदेश यात्राओं में काफी व्यस्त होने वाले हैं. अभी बिहार विधानसभा चुनाव ने उनकी नींद उड़ा रखी है. दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा. लगता है, मोदी की सऊदी अरब एवं इजरायल की यात्राएं कुछ समय के लिए टल जाएं. अगर ऐसा होता है, तो सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के नाम का चयन भी टलेगा. हां, विदेश मंत्रालय के अधिकारी चुस्की लेते हुए पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में अच्छे मुस्लिम चेहरों की क्यों कमी है? वे यह भी कहने से गुरेज नहीं करते कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भी कानों तक बात पहुंचनी चाहिए कि मक्का-मदीना की धरती पर भेजने के लिए एक मुस्लिम चेहरे की तलाश है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

शेखावाटी

ग्रामीण भारत में आधुनिक शिक्षा की अनूठी पहल

मोरारका फाउंडेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास एवं ज्ञान को मजबूत बनाना है. ऑनलाइन शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल और ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है. विद्यार्थी शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने के लिए किसी विशेष दिन/समय के अधीन नहीं होते. वे अपनी सुविधानुसार शिक्षा सत्रों को कुछ देर के लिए रोक भी सकते हैं. सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती.

मानसी बत्रा
feedback@chauthiduniya.com

शिक्षा समाज की नींव होती है, शिक्षा एक मजबूत एवं समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करती है. शिक्षा मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे वह एक सभ्य नागरिक बनता है. आज हम भले ही अंतरिक्ष और चांद पर घर बसाने की बात करते हों, लेकिन आज भी हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर काफी पिछड़ा हुआ है. अत्याधुनिक तकनीक, नए पाठ्यक्रम, नई सोच, संचार क्रांति, आधुनिक शिक्षा और अवसर प्रदान करने वाले संसाधन ग्रामीण भारत से कोसों दूर हैं. लेकिन, देश में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, जो ग्रामीण भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य कर रही हैं, जैसे कि मोरारका फाउंडेशन.

क़रीब 20 साल पहले भारत में कंप्यूटर युग का सपना देखा गया था, जो कुछ हद तक पूरा ज़रूर हुआ है, लेकिन देश के हर नागरिक के लिए यह सपना पूरा होने में अभी कुछ और वक्त लगेगा. जहां देश की शहरी आबादी का बड़ा हिस्सा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं ग्रामीण इलाके अब भी इसकी पहुंच से दूर हैं. मोरारका फाउंडेशन राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है. झुंझुनू में दूर-दूर तक नज़र आते

लहलहाते खेत, चरते पशु, रंग-बिरंगे पक्षी, कच्ची पगडंडियों के किनारे बने मिट्टी एवं घास-फूंस के छोटे-बड़े घर, सौंधी खुशबू वाली आबोहवा और प्रकृति के प्रेम से सराबोर वातावरण में मोरारका फाउंडेशन ने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा से लेकर ऑफलाइन शिक्षा और ई-पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व व क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जिससे शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होने के साथ-साथ बहुआयामी हो गया है. फाउंडेशन की ऑनलाइन शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों ने बोर्ड मेरिट, आईआईटी एवं एनआईआईटी में चयनित होकर सफलता की एक नई कहानी लिखी है. मोरारका फाउंडेशन शेखावाटी के ग्रामीण अंचल के स्कूलों में ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने वाला पहला केंद्र बन गया है. मोरारका फाउंडेशन की ओर से किसानों, महिलाओं, लड़कियों एवं विकलांगों की बेहतरी के लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. फाउंडेशन गांवों की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करता रहा है. अर्द्ध रेतीली ज़मीन पर मोरारका फाउंडेशन के निर्देशन में विकास की बहती धारा साफ़ देखी जा सकती है.

मोरारका फाउंडेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास एवं ज्ञान को मजबूत बनाना है. ऑनलाइन शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल और ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है. विद्यार्थी शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने के लिए किसी विशेष दिन/समय के अधीन नहीं होते. वे अपनी सुविधानुसार शिक्षा सत्रों को कुछ देर के लिए रोक भी सकते हैं. सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती. इसके लिए आम तौर पर केवल बुनियादी इंटरनेट उपयोग, ऑडियो-वीडियो की जानकारी काफी है.

मोरारका फाउंडेशन ने नवलगढ़ में 21वीं सदी का पहला ई-पुस्तकालय खोला, जहां उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों एवं हाई स्पीड इंटरनेट द्वारा संसार भर की सूचनाएं एक ही क्लिक पर उपलब्ध हैं. इस ई-पुस्तकालय में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को डॉक्युमेंट्री फिल्मों द्वारा आधुनिक विश्व की तमाम जानकारियां दी जाती हैं. बंगलुरू, दिल्ली और मुंबई आज आईटी के हब माने जाते हैं, लेकिन अब नवलगढ़ के लोगों को भी आईटी का ज्ञान मिल रहा है.

इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी के आधार पर छात्र काम के वक्त भी अपना पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं और उसे किसी दूसरे कंप्यूटर पर अपने घर में भी पूरा कर सकते हैं. विद्यार्थियों में आवश्यक डिजिटल साक्षरता कौशल की मौजूदगी सुनिश्चित करना और क्षमताएं विकसित करना कार्यक्रम का खास उद्देश्य है. आज मोरारका फाउंडेशन के प्रयासों से झुंझुनू में ऑनलाइन शिक्षा तेजी से बढ़ रही है.

फाउंडेशन ने एक और करिश्मा कर दिखाया है. मोरारका फाउंडेशन ने नवलगढ़ में 21वीं सदी का पहला ई-पुस्तकालय खोला, जहां उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों एवं हाई स्पीड इंटरनेट द्वारा संसार भर की सूचनाएं एक ही क्लिक पर उपलब्ध हैं. इस ई-पुस्तकालय में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को डॉक्युमेंट्री फिल्मों द्वारा आधुनिक विश्व की तमाम जानकारियां दी जाती हैं. बंगलुरू, दिल्ली और मुंबई आज आईटी के हब माने जाते हैं, लेकिन अब नवलगढ़ के लोगों को भी आईटी का ज्ञान मिल रहा है. मोरारका फाउंडेशन के प्रयासों से प्रबंधन एवं औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार के लिए विद्यार्थियों और क्षेत्र में कबाड़ के उपेक्षित व्यवसाय से जुड़े युवाओं के लिए एक नई राह खुली है. आधुनिकता की अंधी दौड़ और नित्य नए गैजेट के बाज़ार में आने के कारण आज हर घर में सबसे ज़्यादा कबाड़ इलेक्ट्रॉनिक सामान का होने लगा है. फाउंडेशन की पहल पर नवलगढ़ के न्यू इंडियन आईटीआई कॉलेज में क्यूर इंडिया एंड जीरो वेस्टेज ने विद्यार्थियों को ई-वेस्ट कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में जानकारी दी. इस कार्यक्रम के तहत सभी विद्यार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का संरक्षण करने और उससे रोज़गार हासिल करने के तौर-तरीकों के बारे में विस्तार से समझाया गया. ■

किसी पर विश्वास मत करो

नीरा के एपिरिएंस से उसके चरित्र का पता नहीं लगाया जा सकता. वह हमेशा से एक संदेहास्पद महिला रही है. उसने हमेशा किसी काम को कराने के लिए अपने सहयोगियों तक को धोखे में रखा. हर वक्त वह कुछ रहस्य छिपाकर रखती थी, जिसकी जानकारी उसके नज़दीकी लोगों तक को नहीं होती थी. उदाहरण के लिए, जब वह पहली बार केएलएम के तीन अधिकारियों के साथ मेरे पास एयर क्राफ्ट को अदालत के ज़रिये रिलीज कराने के लिए आई थी, तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि केएलएम पहले अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है और असफल रही है.

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

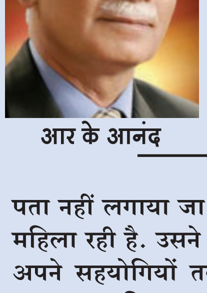

आर के आनंद

मैं यह तथ्य बार-बार नहीं दोहराना चाहता कि नीरा राडिया के पास कितनी सशक्त सूचनाएं होती थीं, उसने कितनी यात्राएं की थीं और वह कितनें सुंदर कपड़े पहनती थी. लेकिन, हमारे जैसे और भी कई लोग, जो यह मानते हैं कि वे नीरा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वे भी यह नहीं समझ सके कि नीरा के एपिरिएंस से उसके चरित्र का पता नहीं लगाया जा सकता. वह हमेशा से एक संदेहास्पद महिला रही है. उसने हमेशा किसी काम को कराने के लिए अपने सहयोगियों तक को धोखे में रखा. हर वक्त वह कुछ रहस्य छिपाकर रखती थी, जिसकी जानकारी उसके नज़दीकी लोगों तक को नहीं होती थी. उदाहरण के लिए, जब वह पहली बार केएलएम के तीन अधिकारियों के साथ मेरे पास एयर क्राफ्ट को अदालत के ज़रिये रिलीज कराने के लिए आई थी, तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि केएलएम पहले अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है और असफल रही है. न मैं यह जानता था कि जब नीरा राडिया मेरे पास इस काम के लिए आई थी, तो उसके साथ ही वह तत्कालीन एनडीए सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से भी एयर क्राफ्ट रिलीज कराने के लिए संपर्क कर रही थी.

सिन्हा से संपर्क करने से पहले वह एयर क्राफ्ट रिलीज कराने के लिए कस्टम कमिश्नर कृष्णकांत से भी संपर्क साध चुकी थी. चूंकि मामला क़ानून मंत्रालय को भेजा जा चुका था, इसलिए कृष्णकांत ने मिलने से मना कर दिया था. नीरा और उसके समर्थकों के लाख दबाव के बाद भी कृष्णकांत उससे नहीं मिले. इधर, मैंने अपने तौर पर अदालत के ज़रिये एयर क्राफ्ट के रिलीज ऑर्डर इस शर्त पर ले लिए कि 12 करोड़ रुपये टैक्स मनी के तौर पर जमा किए जाएंगे. यहां भी नीरा ने कोशिश की कि यह पैसा माफ़ कर दिया जाए और इसके लिए उसने यशवंत सिन्हा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और एयर क्राफ्ट के उड़ान भरने से पहले यह पैसा जमा कराना पड़ा. सिन्हा ने यह स्पष्ट किया था कि उन पर एयर क्राफ्ट रिलीज कराने का जबरदस्त दबाव था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. हालांकि, सिन्हा ने एनडीए के उस राजनेता का नाम नहीं लिया, जिसने उन पर इस काम के लिए दबाव डाला था.

2-जी मामले में उसने ए राजा को दूरसंचार मंत्रालय में लाने के लिए टाटा का भी बतौर लॉबिस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की. कोई भी आदमी यह कल्पना नहीं कर सकता कि भारतीय उद्योग जगत के एक साफ़-सुथरे चेहरे रतन टाटा किसी ऐसे आदमी को मंत्री बनाने के लिए सिफारिशी पत्र लिखेंगे और उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, जो कुछ सालों बाद सीबीआई द्वारा आपराधिक आरोप के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है.

नीरा के संदेहास्पद चरित्र का सिर्फ़ यही एक उदाहरण नहीं है. उसका पता राडियागेट टेप्स में दर्ज बातचीत से लगता है, जिसमें वह अपनी कंपनी वैष्णवी एडवायजरी सर्विसेज (प्रा.लि.) के एसोसिएट डायरेक्टर यतीश वहाल से मुखातिब है. इस बातचीत में उसने न सिर्फ़ टाटा, जो उसके सबसे बड़े क्लाइंट थे, के लिए अपशब्द बोले, बल्कि ट्राई के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बैजल के लिए भी भला-बुरा कहा, जिसे उसने कंसलटेंट के रूप में हायर किया था. नीरा ने वहाल एवं अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सब बैजल को इग्नोर (उनकी उपेक्षा) करें, क्योंकि वह एक बहुत ही कंफ्यूज्ड (भ्रमित) व्यक्ति हैं. खान और कोयले की एक डील के संबंध में उसने टाटा में अपना भरोसा नहीं जताया. उसे यह अंदेशा था कि अगर वह सारे राज बता देगी, तो टाटा सीधे कोल सेक्टर के लोगों से संपर्क साधकर अपना काम निकाल लेंगे और फिर उसे भाव नहीं मिलेगा. उसका हर एक एक्शन डील होता था. 2-जी मामले में उसने ए राजा को दूरसंचार मंत्रालय में लाने के लिए टाटा का भी बतौर लॉबिस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की.

कोई भी आदमी यह कल्पना नहीं कर सकता कि भारतीय उद्योग जगत के एक साफ़-सुथरे चेहरे रतन टाटा किसी ऐसे आदमी को मंत्री बनाने के लिए सिफारिशी पत्र लिखेंगे और उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, जो कुछ सालों बाद सीबीआई द्वारा आपराधिक आरोप के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है. लेकिन नीरा राडिया, जो ए राजा को मंत्री बनवाने के लिए लॉबिंग कर रही थीं, के लिए रतन टाटा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि (यूपीए के एक सहयोगी दल के मुखिया) को पत्र लिखकर राजा को बेहतर बताया और दूरसंचार मंत्री की स्पेक्ट्रम आवंटन नीतियों को तार्किक बताया.

जारी...

(मशहूर वकील आर. के. आनंद क्लोज एनकाउंटर्स विद नीरा राडिया के लेखक हैं.)

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

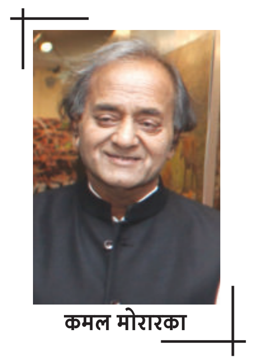

कमल मोरारका

चुनाव नहीं, देश बड़ा होता है

बेशक, वे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त संख्या हो तो. फ़िलहाल उनके पास यह संख्या नहीं है. इसलिए उचित यही होगा कि वे अपने वक्तव्यों के स्वर में नरमी लाएं. और, एक व्यवहारिक समाधान का पता लगाया जाना चाहिए कि आरएसएस जो करना चाहता है, संविधान उसके लिए कितनी अनुमति देता है? मामला अगर इससे आगे बढ़ता है, तो फिर यह न्यायपालिका के पास जाएगा.

देश के अख़बार बिहार की अलग-अलग पार्टियों के चुनाव प्रचार की ख़बरों से भरे पड़े हैं. मुझे नहीं मालूम कि एनडीए के रणनीतिकार कौन लोग हैं, लेकिन यह बुद्धिमतापूर्ण निर्णय नहीं लगता है कि बिहार में प्रधानमंत्री की इतनी ज़्यादा संख्या में रैलियां कराई जाएं. बेशक, वह पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं. यह उनका व्यक्तित्व होगा, जो यह निर्णय करेगा कि लोग कैसे मतदान करते हैं. लेकिन, इसकी ज़रूरत नहीं थी कि वह इतनी सारी जगहों पर जाकर भाषण दें और एक ही बात बार-बार दोहराएं. उन्हें केंद्र की सत्ता में आए डेढ़ साल से अधिक समय हो गया है. इसलिए अब उनकी नीतियों और उनके कामों को खुद बोलना चाहिए, न कि उन्हें अपनी सफलता के बारे में बोलने की ज़रूरत पड़नी चाहिए. यह उनके दूसरे कैबिनेट सहयोगियों एवं पार्टी के नेताओं के लिए ठीक है कि वे जाकर राज्य में उनके कामों का बखान करें. बहरहाल, प्रधानमंत्री ने सक्रिय रूप से चुनाव अभियान में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया और सारी चीजें अपने हाथ में ले लीं. पहले के प्रधानमंत्री किसी राज्य के चुनाव में दो या तीन से अधिक रैलियां नहीं करते थे. जहां तक मुझे जानकारी है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 40 रैलियां करने वाले हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा हैं.

दूसरी तरफ़ विभिन्न पार्टियां लुभावने नारों और जो काम उन्होंने किए हैं, उनके ज़रिये सत्ता में वापसी के लिए ज़ोर लगा रही हैं. नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम, उनकी छवि और जातीय समीकरण उनके पक्ष में जाएंगे, जबकि जबरदस्त धनबल और आरएसएस की अफ़वाह फैलाने की शक्ति-काबिलियत आदि एनडीए के पक्ष में काम करेंगे. आख़िरकार जीत किसकी होगी, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अभी जो लग रहा है, उसके हिसाब से जद (यू)-राजद-कांग्रेस महा-गठबंधन आगे दिख रहा है. पांच नवंबर को जब आख़िरी चरण के चुनाव हो जाएंगे, तब कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि महा-गठबंधन कैसा प्रदर्शन करता है. जहां तक भाषण की विषय-वस्तु का सवाल है, तो प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह इतने अधिक आक्रामक होकर लालू यादव पर व्यक्तिगत हमले करें. अगर भाजपा का कोई दूसरा नेता ऐसा करता, तो कोई खास बात नहीं होती, लेकिन प्रधानमंत्री को खुद को इस तरह के व्यक्तिगत हमलों से अलग रखना चाहिए. ज़ाहिर है, बिहार चुनाव कोई भी जीते, वह प्रधानमंत्री बने रहेंगे और उन्हें जीतने वाले के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा. ट्वीटर जोक्स से भरा पड़ा है, जिसमें लोग री-ट्वीट कर रहे हैं कि ज़ी न्यूज ही एक ऐसा चैनल है, जिसने अभी तक अपनी वफादारी कायम रखी है. यानी जो सर्वे हैं, वे सब ग़लत हैं. टीवी चैनल अपनी मर्जी की चीजें दिखा रहे हैं. हर कोई यह समझता है कि ज़ी न्यूज एनडीए का पक्ष लेगा और बाकी चैनल उससे अलग होंगे.

यद्यपि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के संदेश के पालन की बात कहकर मामला ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन हक़ीकत यह है कि देश के राजनीतिक माहौल को सांप्रदायिक बनाने और उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, जो देश के लिए कतई उचित नहीं है. हर पांच साल में देश एवं राज्यों में चुनाव आएंगे और चले जाएंगे. चुनाव ही सब कुछ नहीं है. चुनाव सबसे बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देश सबसे ऊपर है. हमने देश का निर्माण बहुत मुसीबतों के बाद किया है. 1947 से लेकर अब तक हम पाकिस्तान के रास्ते पर नहीं गए. हालांकि, दोनों देशों ने एक साथ अपना सफ़र शुरू किया था. और, अब हम सारी उपलब्धियों के बाद, चूंकि आरएसएस ने सत्ता हासिल कर ली है, खुद को तबाह कर लें? वे बेहतर कर सकते हैं, अगर एक छोटा-सा सेल स्थापित करें, संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों एवं अन्य प्रावधानों का अध्ययन करें और खुद के विचारों की उनसे तुलना करें. जहां भी उनकी विचारधारा संविधान से मेल नहीं खाती, उन्हें चाहिए कि वे अपनी विचारधारा को संविधान के हिसाब से ठीक कर लें, क्योंकि संविधान ही सर्वोपरि है.

बेशक, वे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त संख्या हो तो. फिलहाल उनके पास यह संख्या नहीं है. इसलिए उचित यही होगा कि वे अपने वक्तव्यों के स्वर में नरमी लाएं. और, एक व्यवहारिक समाधान का पता लगाया जाना चाहिए कि आरएसएस जो करना चाहता है, संविधान उसके लिए कितनी अनुमति देता है? मामला अगर इससे आगे बढ़ता है, तो फिर यह न्यायपालिका के पास जाएगा. न्याय पालिका ऐसे मामलों में उलझना नहीं चाहती, क्योंकि राजनीतिक दल आख़िरकार राजनीतिक दल हैं और सबकी अपनी-अपनी विचारधारा है. जब तक राजनीतिक दल ज़िम्मेदारी के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक भारतीय लोकतंत्र नहीं चल सकता. कुछ वर्षों के बाद संघर्ष शुरू हो जाएगा और वैसी ताकतें हावी हो जाएंगी, जिनका राजनीति या सिविल सोसायटी से कोई संबंध नहीं होगा, जैसा कि हमारे पड़ोस में हुआ.

बिहार चुनाव असल मुद्दा है. एक महीने से भी कम समय में नतीजे आ जाएंगे. हमें आशा करनी चाहिए कि मतदाता एक स्थिर सरकार चुनेंगे, न कि एक एमएलए इधर से, एक एमएलए उधर से लेकर सरकार बनाने की स्थिति पैदा करेंगे. जब नवंबर में सरकार बनेगी, तो मैं आश्वस्त हूं कि सरकार चाहे जिसकी बने, केंद्र सरकार उसके साथ पूरा सहयोग करेगी और प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किए हैं, उन्हें वह पूरा करेंगे. वह बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, जिन्हें हम अव्यवहारिक भी मान सकते हैं, क्योंकि राज्य अपनी गति से आगे बढ़ेगा. लेकिन, जो भी करने की ज़रूरत है, वह किया जाना चाहिए. केवल यह कहना कि वहां जंगलराज है, क़ानून-व्यवस्था खराब है, इसका कोई मतलब नहीं है. ये सारी चीजें पीछे छूट चुकी हैं. पिछले दो वर्षों में बिहार में हमने क़ानून-व्यवस्था के खराब होने की कोई बड़ी ख़बर नहीं सुनी है. नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से भी अब तक कोई आरोप नहीं लगा. यह अच्छी बात है. उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ यही आरोप है कि जबसे उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा है, बिहार में विकास का कोई काम नहीं हुआ है. न तो यह आरोप सत्यापित किया जा सकता है और न यह सही है. आशा करते हैं कि अगले कुछ हफ़्तों का चुनाव प्रचार घटिया नहीं होगा और शालीनता बरकरार रहेगी तथा जो सबसे लोकप्रिय पार्टी हो, वह जीते. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

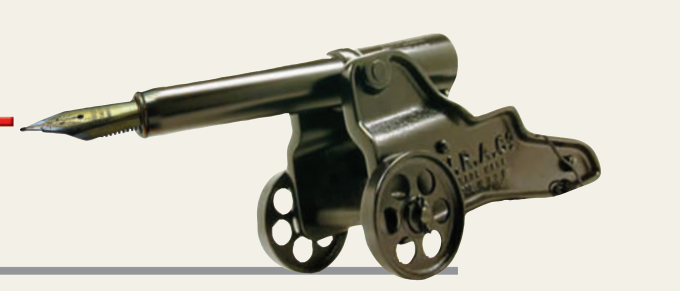

जब तोप मुक़ाबिल हो

बिहार चुनाव निराश कर रहा है

"बिहार में चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी परम आवश्यक समझ रही है और इसके लिए वह साम, दाम, दंड, भेद का प्रचंड इस्तेमाल कर रही है. दूसरी तरफ़ नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस का महा-गठबंधन किसी भी क़ीमत पर इस चुनाव में हारना नहीं चाहता. अगर भाजपा हारती है, तो पार्टी के भीतर अंतर्विरोध बढ़ जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर अपने मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा या तत्काल उनके विभाग बदलने पड़ेंगे."

बिहार विधानसभा चुनाव तो लग रहा है कि पिछले सारे चुनावों के रिकॉर्ड तोड़ देगा. पहले यह माना जाता था कि राजनीति में भाषा का संयम बड़े नेता अवश्य रखेंगे, पर बिहार में तो बड़े नेताओं ने ही सीमा तोड़ दी है. प्रधानमंत्री किसी को शैतान कह रहे हैं, जवाब में कोई किसी को कुत्ता पालक कह रहा है. ऐसी-ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका ज़िक्र करना कम से कम मुझे ठीक नहीं लगता. पर इतना अवश्य लगता है कि विधानसभा का यह चुनाव भाषा की सारी मर्यादाओं को लगभग लांघ चुका है और जब तक यह चुनाव समाप्त होगा, तब तक राजनीति के कैंपेन की एक नई भाषा लिख चुका होगा. अब यह पता नहीं कि इस भाषा का असर बिहार की जनता के ऊपर क्या पड़ेगा? क्या चुनाव में गाली-गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों को जनता जिताएगी या नहीं जिताएगी? इन सवालों के जवाब में एक तथ्य यह सामने आया कि जनता भी इस भाषा का आनंद उठा रही है. वह न केवल आनंद उठा रही है, बल्कि इसमें हिस्सेदार भी बनती जा रही है. इसलिए यह कहना कि जनता हमेशा सही फ़ैसले लेती है, कितना न्यायसंगत है, कहा नहीं जा सकता. हर नेता की सभाओं में भीड़ दिखाई दे रही है और वह नेता द्वारा किए जा रहे प्रचार की शैली में निकलने वाली गालियों पर तालियां बजा रही है. इतना भी होता, तो भी सहन किया जा सकता था, लेकिन इससे आगे और कुछ हो रहा है.

बिहार में जिन लोगों के पास भी स्मार्टफोन है, उनके फोन के ऊपर ऐसे-ऐसे संदेश आ रहे हैं, जिन्हें पढ़कर सांप्रदायिक उन्माद तेजी के साथ बढ़ सकता है. इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, जिन्हें देखकर नफरत पैदा हो सकती है. पैदा हो सकती है, हम यह क्यों कहें, नफरत पैदा होगी ही. एक वीडियो में धर्म विशेष का व्यक्ति भैंस के ऊपर बैठकर उसका सिर काटकर चाकू से उसे गोद रहा है. एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति गाय काटता हुआ दिखाई दे रहा है और धार्मिक नारे लगा रहा है. संदेश ऐसे-ऐसे आ रहे हैं, जो बताते हैं कि अगर संभला न गया, तो एक क्षण में आग दावानल की तरह फैल सकती है. आग लगने का सारा इंतजाम बिहार में हर तरफ़ दिखाई दे रहा है और मजे की बात यह है कि इसे रोकने की कोशिश कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है.

बिहार में चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी परम आवश्यक समझ रही है और इसके लिए वह साम, दाम, दंड, भेद का प्रचंड इस्तेमाल कर रही है. दूसरी तरफ़ नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस का महा-गठबंधन किसी भी क़ीमत पर इस चुनाव में हारना नहीं चाहता. अगर भाजपा हारती है, तो पार्टी के भीतर अंतर्विरोध बढ़ जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर अपने मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा या तत्काल उनके विभाग बदलने पड़ेंगे. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जीत जाते हैं, जो वैसे ही संवादहीनता को अपना शस्त्र बना चुके हैं, तो वह इसे और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी में यह संवादहीनता बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है.

दूसरी तरफ़ अगर लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस का महा-गठबंधन चुनाव जीतता है, तो भी वह सरकार कितनी

ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में मान रही है, क्योंकि उसका मानना है कि जो भी वोट ओवैसी काटेंगे, वे लालू यादव, नीतीश कुमार या कांग्रेस के समर्थक वोट होंगे. वहीं दूसरी तरफ़ नीतीश कुमार का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल में कोई समर्थन नहीं मिल रहा है. इसलिए उन्होंने सिर्फ़ छह उम्मीदवार मैदान में उतारे, जबकि उनकी घोषणा 25 उम्मीदवार उतारने की थी. इसका एक मतलब यह हो सकता है कि बिहार का मुसलमान मजबूती के साथ यह संदेश देने में सफल हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा.

स्थिर रहेगी, यह कहा नहीं जा सकता. तीनों पार्टियों के अपने अलग-अलग एजेंडे हैं और शायद अभी भी उनमें यह समझदारी नहीं पैदा हुई है कि चुनाव के बाद नतीजे चाहे जो हों, उन्हें एक रहना है. नीतीश कुमार एवं लालू यादव को पूरा भरोसा है कि वे चुनाव में जीतेंगे और उनका गठबंधन सत्ता में आएगा तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे. रणनीति के तहत लालू यादव ने पिछड़ों एवं अगड़ों के बीच की रेखा बिहार में और मजबूत कर दी है. कांग्रेस का प्रचार अभियान चल रहा है, लेकिन उसे मिली चालीस सीटें कितने जीते उम्मीदवारों के साथ वापस आएंगी, अभी कोई नहीं कह सकता. और, सबसे बड़ा फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं. ओवैसी ने 25 उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन वह छह उम्मीदवारों के ऊपर आ गए. उन्होंने एक टीवी चैनल पर कहा कि वह तो सिर्फ़ छह सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव का गठबंधन सारी वसीटों पर चुनाव लड़ रहा है, उन्हें लेकर कोई चिंता किसी में क्यों नहीं होती?

दरअसल, ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में मान रही है, क्योंकि उसका मानना है कि जो भी वोट ओवैसी काटेंगे, वे लालू यादव, नीतीश कुमार या कांग्रेस के समर्थक वोट होंगे. वहीं दूसरी तरफ़ नीतीश कुमार का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल में कोई समर्थन नहीं मिल रहा है. इसलिए उन्होंने सिर्फ़ छह उम्मीदवार मैदान में उतारे, जबकि उनकी घोषणा 25 उम्मीदवार उतारने की थी. इसका एक मतलब यह हो सकता है कि बिहार का मुसलमान मजबूती के साथ यह संदेश देने में सफल हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा. और, भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को उसी तरह अपनी जीत का ट्रम्प कार्ड मान बैठी, जैसे उसने महाराष्ट्र में माना था. महाराष्ट्र में यह माना जा रहा है कि ओवैसी की वजह से कांग्रेस और एनसीपी के वोट कटे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सत्ता में आईं.

ये अंतर्विरोध हैं, लेकिन इन अंतर्विरोधों का कोई मतलब नहीं है. इन अंतर्विरोधों का मतलब तब होता, जब राजनीतिक भाषा, राजनीतिक शैली और राजनीतिक समझ चुनाव में दिखाई देती. इतना ही नहीं, कम से कम यह समझदारी होती कि अगर लोग आमने-सामने आ जाएंगे, तो विकास की बात, जिसे राजनीतिक दल कह रहे हैं, वह तो कहीं लुप्त हो जाएगी. फिर तो नफरत होगी, हिंसा होगी, लाशें होंगी और सारे धर्मों की अच्छी बातों का एक साथ खून हो जाएगा. अफ़सोस इसी बात का है कि इन बातों को न भारतीय जनता पार्टी समझ रही है या शायद समझना नहीं चाहती और न लालू यादव एवं उनके साथी समझ रहे हैं, शायद वे भी नहीं समझना चाहते. इसका मतलब बिहार में जो नई शैली पैदा हो रही है, वह इस देश के लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करेगी. शायद भारत में लोकतंत्र का सबसे विद्रूप स्वरूप देखना हमारी किस्मत में लिखा है. चलिए देखते हैं, लोकतंत्र के कौन-कौन से बदरंग चेहरे हमें बिहार चुनाव में दिखाई देते हैं या लोकतंत्र का सबसे विद्रूप स्वरूप किस तरह सामने आता है. पर मन डर रहा है, मन कांप रहा है और वे सारे लोग, जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, बिहार चुनाव को देखकर आंसू तो बहा ही रहे हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

फूलन को आत्मसमर्पण करने से किसने रोका-3

दो पाटों के बीच फंस गए डाकू

घनश्याम तो 15 नवंबर की रात बारह बजे रामपुरा से निकल कर पचनदा के बीहड़ों में गायब हो गया, किंतु पुलिस अधिकारियों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ. फलस्वरूप 17 नवंबर को रामपुरा के समरजीत इंटर कॉलेज में आत्मसमर्पण की पूरी तैयारी हो गई. पुलिस की ओर से तंबुओं, कनातों एवं 50 कुर्सियों का इंतजाम किया गया था. इधर 16 नवंबर की रात्रि को ही अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक आरपी गोविल कालपी के अतिथि गृह में आकर ठहर गए, किंतु जब उन्हें आत्मसमर्पण विफल होने का पता चला, तो वह काफी क्षुब्ध हुए. अब उन्होंने एक नई रणनीति बनाकर सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह प्रेस के समक्ष साफ़ इंकार कर दें कि आत्मसमर्पण की कभी कोई बात हुई थी. दूसरी ओर आत्मसमर्पण का तमाशा देखने के इच्छुक रामपुरा पहुंचे हज़ारों दर्शकों एवं अनेक पत्रकारों को निराश वापस लौटना पड़ा.

इस संपूर्ण घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि जालौन पुलिस जहां एक ओर चुपचाप आत्मसमर्पण के लिए उतावली थी, वहीं राज्य सरकार के दृष्टिकोण को पूरी तरह समझने और समीपवर्ती ज़िलों को विश्वास में लेने की उसने कोई कोशिश नहीं की. बताया जाता है कि 16 नवंबर की शाम को जब यह ख़बर लखनऊ पहुंची, तो उद्योग मंत्री वीर बहादुर सिंह एवं आबकारी राज्य मंत्री राम रतन सिंह ने राज्य के पुलिस महानिरीक्षक श्री दीक्षित से यह पूछा कि आख़िर किस नीति के तहत वह आत्मसमर्पण करा रहे हैं. बताया जाता है कि श्री दीक्षित ने इन मंत्रियों से कहा कि उन्हें अभी तक इस आत्मसमर्पण कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है तथा इस संबंध में वह तत्काल कोई कठोर क़दम उठाएंगे. फलस्वरूप 17 नवंबर को बहुत सवेरे ही एक हेलिकॉप्टर श्री गोविल को लेने कालपी पहुंच गया तथा दोपहर बाद तक श्री गोविल एवं जालौन के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ आ गए. उन्होंने पुलिस महानिदेशक के समक्ष अपनी सफाई पेश की. इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने दस्यु उन्मूलन अभियान तेजी से शुरू करने का निर्णय लिया है.

उत्तर प्रदेश सरकार जहां विफल रही, मध्य प्रदेश पुलिस ने अपना काम वहीं से शुरू किया. जब उसे पता चला कि घनश्याम और फूलन के समर्पण की संभावना है, तो भिंड के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र चतुर्वेदी 19 नवंबर को चुपचाप उरई आए. वहां उन्होंने उन वकीलों से भेंट की, जिनके बारे में उन्हें मलखान का समर्पण कराने वाले एक पत्रकार ने सुराग दिया था कि वे घनश्याम से संपर्क रखते हैं. राजेंद्र चतुर्वेदी ने कुछ मुखबिरों और छोटे राजनीतिक नेताओं ने भी मुलाकात की. किसे कितना इनाम मिलेगा, इसका भी सौदा होने लगा. लेकिन जैसी की आशा थी, जालौन पुलिस ने राजेंद्र चतुर्वेदी का बहिष्कार कर दिया. यहां तक कि उन्हें रात में ओढ़ने के लिए रजाई एवं कंबल तक उरई के वकीलों के यहां से मंगाने पड़े. जब राजेंद्र चतुर्वेदी भिंड लौटने लगे, तो गोपालपुरा से सटे पहुज नदी के किनारे एक स्थान पर उनकी भेंट मुसलिम से हुई, जिसकी योजना पहले से बनी हुई थी. मुसलिम को उन्होंने कोई नुक़सान न पहुंचाने और उसे ले जाने के लिए मलखान को भेजने का वादा किया.

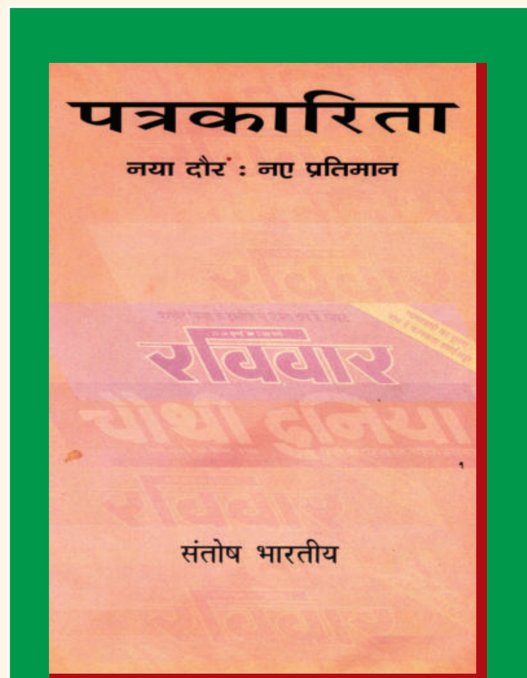

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

इसके साथ ही राजेंद्र चतुर्वेदी ने घनश्याम एवं फूलन के मध्य प्रदेश में बसे रिश्तेदारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे दोनों को मध्य प्रदेश में समर्पण के लिए तैयार करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें धोखा ही देगी. उन्होंने घनश्याम के एक रिश्तेदार को बताया कि 16 नवंबर को यदि घनश्याम फरार न रहता, तो उसे निश्चित रूप से गोली मार दी जाती. उन्होंने साफ़-साफ़ कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस समर्पण की नीति पर भरोसा रखती है. जब जालौन पुलिस को यह पता चला, तो वह बौखला गई. उसने घनश्याम के घर वालों को संदेश भिजवाया कि यदि घनश्याम ने मध्य प्रदेश में समर्पण किया, तो वह उन सबको दीवार में चिनवा देगी.

22 नवंबर को मलखान मध्य प्रदेश पुलिस की एक बिना निशान वाली जीप में बैठकर उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के गांव सनाबाई की गढ़िया में आया. यहां उसे मुसलिम, भजू एवं रचनौस के दो धानुक डाकू मिले, जिन्होंने उसके सामने हथियार डाल दिए. मलखान ने मुसलिम एवं बाकी तीनों को जीप में बैठाकर सिंध नदी पार करा दी तथा खुद पैदल पार गया. इसके बाद जीप मुसलिम को लेकर भिंड चली गई, जहां राजेंद्र चतुर्वेदी के सामने उनका औपचारिक समर्पण हुआ. 24 नवंबर को मैनपुरी के भूरा ने, जो छविराम के बाद उसके गिरोह का सरदार बना था, भिंड जाकर राजेंद्र चतुर्वेदी के सामने समर्पण कर दिया. पुलिस ने उसे शस्त्र अधिनियम के तहत चालान कर जेल भेज दिया. वस्तुत: घनश्याम के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि उसका अपना क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, इसलिए उसे यहीं समर्पण करना है. दूसरी तरफ़ फूलन का कहना है कि जहां बाबा समर्पण करेंगे, वहीं वह भी करेगी. इस समय उसके गिरोह में 17 डाकू हैं तथा घनश्याम के गिरोह में 45. राजेंद्र चतुर्वेदी ने इन दोनों के पास संदेश भिजवाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने छविराम एवं अनार सिंह को समर्पण के बहाने ही बुलाकर मार डाला था. इसलिए उस पर बहुत भरोसा करना उनके लिए हानिकारक होगा.

जारी...

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

लंबित मामले लॉटरी के ज़रिये निपटाए जाएं

समस्या से निपटने के लिए लोकतंत्र के सभी स्तंभों को आपस में समन्वय स्थापित करके काम करना होगा. खास तौर पर कार्यपालिका को अगले कई वर्षों तक संसाधन मुहैया कराने के साथ-साथ लगातार यह मुहिम जारी रखनी होगी, ताकि इस समस्या को नियंत्रित किया जा सके. फ़िलहाल तो जजों की संख्या पांच गुना बढ़ाने की ज़रूरत है, जो समय के साथ क्रमबद्ध तरीके से ही संभव हो सकेगा. इसके लिए विधि की शिक्षा का विस्तार करना होगा, न्याय पालिका की नौकरी को प्रोत्साहन देना होगा और किसी न किसी तरह बकवास मुक़दमे समाप्त करने होंगे. ऐसा भी किया जा सकता है कि जो लोग शिक्षित एवं काबिल हैं, लेकिन वकील नहीं हैं, उन्हें भी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करके जज बनाया जा सकता है.

छह से चौदह माह के तीन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण के ख़िलाफ़ केंद्र और राज्य सरकारों को कार्रवाई का आदेश देने की अपील की है. क्या यह संभव है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन बच्चों से यह कहा जाए कि 3.5 करोड़ मामले पहले से लंबित हैं, इसलिए आप भी कतार में सबसे पीछे लग जाइए? वजह, आम तौर पर सिविल के मुक़दमों का फ़ैसला 20 साल और फौजदारी के मुक़दमों का फ़ैसला 30 साल में आता है. भारतीय लोगों को मुक़दमेबाजी पसंद है. यह जानकर आप हैरान होंगे कि अंग्रेजों द्वारा न्याय व्यवस्था स्थापित करने से पहले 5,000 वर्षों तक भारत के लोगों ने छोटी-छोटी बातों पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाए बिना जीवन गुज़ारा. अगर पांडव अदालत चले गए होते और उन्हें अपने पुरखों की संपत्ति में से न्यायोचित हिस्सा मिल गया होता, तो महाभारत की आवश्यकता ही न पड़ती. लेकिन, उस ज़माने में भी मामलों को निपटाने में आज जैसी ही देरी होती, तो शायद उन्हें अपने जीवनकाल में न्याय न मिल पता. न्याय मांगना बुनियादी मानव अधिकार है, लेकिन अदालतें पीआईएल से भरी पड़ी हैं.

बेशक, अंग्रेज उपनिवेशवादियों की मेहरबानी से हम आज यह दावा कर सकते हैं कि चीन के विपरीत भारत में क़ानून का राज है, लेकिन इसके साथ एक समस्या है. जैसा कि प्रधानमंत्री को कैलिफोर्निया में बताया गया व्यवसायिक मुक़दमों के फ़ैसलों में देरी निवेशकों की नज़र में भारत का नंबर कम कर देती है. यह तो आयकर अधिकारियों के साथ किसी मामले में उलझा कोई करदाता ही इससे जुड़े आतंक की कहानी सुना सकता है. इसके लिए कर-आतंकवाद उचित शब्द होगा. यह कोई ढकी-छिपी बात नहीं है, बल्कि यह एक खुला हुआ स्कैंडल है और जिसमें हर सरकार शामिल रही है. राष्ट्र के तीनों स्तंभ यानी विधायिका, कार्यपालिका एवं न्याय पालिका सभी इसके लिए दोषी हैं. 10 लाख आबादी पर 10.7 जजों की संख्या किसी भी सभ्य देश की न्यूनतम संख्या है. सोने पे सुहागा यह कि हर तीन पदों में से एक पद खाली है. दरअसल, जजों की संख्या घटती जा रही है, लेकिन न्याय पालिका भी राजनीति की तरह पारिवारिक व्यवसाय बनती जा रही है. क्या यह उम्मीद करना अतिशयोक्ति होगा कि देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2027 तक भारत में एक सुचारू न्याय व्यवस्था स्थापित हो जाएगी?

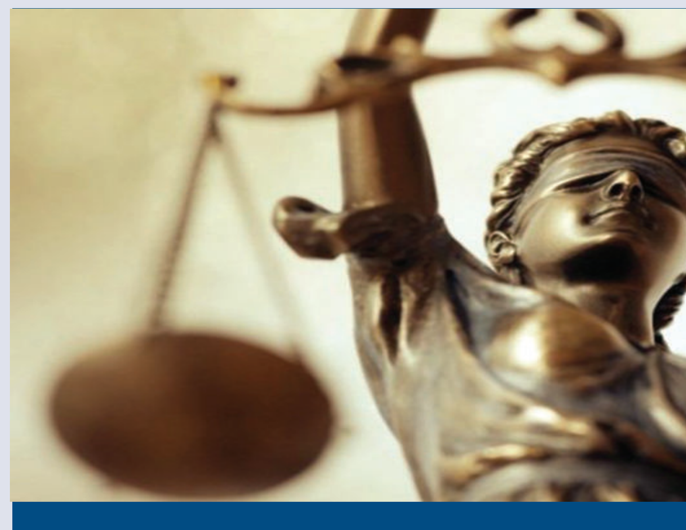

अंग्रेज उपनिवेशवादियों की मेहरबानी से हम आज यह दावा कर सकते हैं कि चीन के विपरीत भारत में क़ानून का राज है, लेकिन इसके साथ एक समस्या है. जैसा कि प्रधानमंत्री को कैलिफोर्निया में बताया गया व्यवसायिक मुक़दमों के फ़ैसलों में देरी निवेशकों की नज़र में भारत का नंबर कम कर देती है.

इस समस्या से निपटने के लिए लोकतंत्र के सभी स्तंभों को आपस में समन्वय स्थापित करके काम करना होगा. खास तौर पर कार्यपालिका को अगले कई वर्षों तक संसाधन मुहैया कराने के साथ-साथ लगातार यह मुहिम जारी रखनी होगी, ताकि इस समस्या को नियंत्रित किया जा सके. फ़िलहाल तो जजों की संख्या पांच गुना बढ़ाने की ज़रूरत है, जो समय के साथ क्रमबद्ध तरीके से ही संभव हो सकेगा. इसके लिए विधि की शिक्षा का विस्तार करना होगा, न्याय पालिका की नौकरी को प्रोत्साहन देना होगा और किसी न किसी तरह बकवास मुक़दमे समाप्त करने होंगे. ऐसा भी किया जा सकता है कि जो लोग शिक्षित एवं काबिल हैं, लेकिन वकील नहीं हैं, उन्हें भी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करके जज बनाया जा सकता है. दरअसल, लंबित पड़े मामले निपटाने के लिए कुछ सशक्त उपाय करने होंगे. न्याय व्यवस्था लाटरी की तरह है, फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि इस में ड्रा के नतीजे कभी-कभी आते हैं. मेरा सुझाव यह है कि जिन लोगों ने पांच वर्ष या अधिक समय तक नतीजे का इंतज़ार किया है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वे अपने मुक़दमे के फ़ैसले के लिए लाटरी ड्रा का नियम मानेंगे? अगर विषम संख्या आई, तो मुद्दालेह (प्रतिवादी) जीत गया और अगर सम संख्या आई, तो मुद्दई (वादी). यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उस व्यवस्था से अजीब नहीं होगा, जो फ़िलहाल हमारे यहां मौजूद है. इसके ज़रिये त्वरित न्याय मुमकिन हो सकेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

अजमोदा के छोटे-छोटे वर्षायु क्षुप अज़वायन की भांति 0.3-2.4 मी ऊंचे होते हैं. इसके पत्ते अनेक भागों में विभक्त और किनारे कटे हुए होते हैं. इसके पुष्प छतरीनुमा पुष्पक्रम में छोटे- छोटे श्वेत रंग के होते हैं, जो पककर अन्त: बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं. धनिया व अज़वायन की भांति इन बीजों को ही अजमोदा कहते हैं. अजमोदा कफवातशामक, पित्तवर्धक, वेदनास्थापक, विदाही, दीपन, वातानुलोमन शूलप्रशमन कृमिघ्न हृदयोत्तेजक, कफघ्न, मूत्रप्रवर्तक, मर्भाशयोत्तेजक और वाजीकारक है.

कई रोगों में लाभदायक है अजमोदा

प्राय: सभी प्राचीन एवं अर्वाचीन आयुर्वेदीय ग्रन्थों में इसका वर्णन पाया जाता है. यूनानियों को अजमोदा का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ था. अजमोदा भारतवर्ष में सर्वत्र, विशेषकर बंगाल में शीत-ऋतु के आंरभ में उगायी जाती है. कई लोग अजमोदा व अजयावन को भ्रम से एक ही पौधा मानते हैं, परन्तु वस्तुत: ये दोनों अलग-अलग हैं.

बाह्यस्वरूप

अजमोदा के छोटे-छोटे वर्षायु क्षुप अज़वायन की भांति 0.3-2.4 मी ऊंचे होते हैं. इसके पत्ते अनेक भागों में विभक्त और किनारे कटे हुए होते हैं. इसके पुष्प छतरीनुमा पुष्पक्रम में छोटे-छोटे श्वेत रंग के होते हैं, जो पककर अन्त: बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं. धनिया व अज़वायन की भांति इन बीजों को ही अजमोदा कहते है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

1. अजमोदा कफवातशामक, पित्तवर्धक, वेदनास्थापक, विदाही, दीपन, वातानुलोमन, शूलप्रशमन, कृमिघ्न हृदयोत्तेजक, कफघ्न, मूत्रप्रवर्तक, मर्भाशयोत्तेजक और वाजीकारक है. यह हिचकी, वमन, मलाशय की पीड़ा तथा खांसी में लाभकारी है. पाचनसंस्थानगत अंगों पर इसका प्रभाव होने से उदर-विकार-नाशक औषधियों में इसे मुख्य स्थान प्राप्त है. यकृत्, प्लीहा और हृदय को लाभ पहुंचाती है. अर्श और पथरी रोग में भी यह लाभकारी है.

2. अजमोदा फल चूर्ण या मूल क्वाथ आमवात, संधिशूल, वातरक्त, कास पित्ताश्मरी तथा वृक्काश्मरी में हितकर है.

3. अजमोदा के बीज उत्तेजक, हृद्य, बलकारक, आर्तवजनन, वातानुलोमक तथा पूयरोधी होते हैं.

4. बीज तैल उद्वेष्टनरोधी, प्रशामक, हृद्य तथा तंत्रिकोत्तेजक होता है.

5. मूल मूत्रल एवं उत्परिवर्तक होता है.

6. पंचाग, मूत्रगत, पूयरोधी तथा आमवातरोधी, उच्चरक्तचाप शामक, रक्त-शर्करा तथा वसा की किन्चित् मात्रा को कम करने वाला, आक्षेपरोधी, आघातरोधी तथा तंत्रिका-संरक्षक होता है.

7. बीजों का एथेनोलिक तथा जलीय-सार चूहों के गर्भाशय में रोपणरोधी क्रिया प्रदर्शित करता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

मुख रोग :

1. दंतशूल- अजमोदा को अग्नि पर हल्का भूनकर-पीसकर धीरे-धीरे मसूढ़ों व दातों पर मलने से दन्तपीड़ा व मुखरोग में तुरंत लाभ होता है.

कण्ठ रोग:

1. वातज- स्वरभेद-यवक्षार तथा अजमोदा के क्वाथ से पकाए हुए घी का सेवन करने से वातज स्वरभेद में लाभ होता है.

2. अजमोदा को 2-3 ग्राम पानी में उबालकर उसमें सेंधानमक डालकर गरारा (गंडूष) करने से स्वरभेद आदि कण्ठ विकारों में लाभ होता है.

वक्ष रोग:

1. शुष्क कास- अजमोदा-युक्त पान-पत्र को चबा कर धीरे-धीरे चूसने से सूखी खांसी में लाभ होता है.

2. श्वास रोग- यह स्नायु शैथिल्यकर होने के कारण सांस की नली की सूजन तथा सांस की बीमारियों में लाभकारी है. इसका चूर्ण करके 2-3 ग्राम की मात्रा में (गर्म जल या शहद के साथ) दिन में 3 बार में प्रयोग करें.

3. हिचकी- भोजनापरांत हिचकियां आती हों, तो अजमोदा के 10-15 दाने मुंह में रखकर चूसने से हिचकी बंद हो जाती है.

उदर रोग:

1. अग्निदीपनार्थ- पिप्पली, अजमोदा आदि दीपनीय महाकषाय की औषधियों से बनाए क्वाथ या चूर्ण का सेवन करने से जठराग्नि का दीपन होता है.

2. गुल्म- शुण्ठी, मरिच, पिप्पली तथा अजमोदा आदि द्रव्यों से बनाए हिंग्वाष्टक चूर्ण का (2-4 ग्राम) सेवन करने से वातजन्य गुल्म में लाभ होता है.

3. शूलयुक्त अतिसार- 50 मिली दूध में 10ग्राम घृत, 5 ग्राम मधु तथा मिश्री, अजमोदा, कटवंग, और मुलेठी के सूक्ष्म चूर्ण को मिलाकर पीने से अतिसार के कारण उत्पन्न वेदना में लाभ होता है.

4. प्रवाहिका- पाठा, अजमोदा , कुटजत्वक, नीलकमल, सोंठ तथा पिप्पली के चूर्ण (2-4 ग्राम) को गुनगुने जल के साथ सेवन करने से प्रवाहिका में लाभ होता है.

5. छर्दि- जन औषधियों का स्वाद अग्राहा होता है, उनके साथ अजमोदा के 2-5 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से उल्टी की आशंका नहीं रहती है.

6. 2-5 ग्राम अजमोदा एवं 2-3 लौंग की कली को पीस कर 1 चम्मच मधु के साथ चाटने से छर्दि में लाभ होता है.

7. आध्मान- 2-4 ग्राम अजमोदा के चूर्ण को 10 ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर गर्म पानी से बार-बार सेवन करने से आध्मान (अफारा) में लाभ होता है.

8. उदरशूल- 1 ग्राम काला नमक के साथ 3 ग्राम अजमोदा का चूर्ण बनाकर प्रात: सायं गर्म जल के साथ सेवन करने से उदरशूल का शमन होता है.

9. अजमोदा तेल की 2-3 बूंदो को 1 ग्राम शुंठी चूर्ण में मिश्रित कर गर्म जल के साथ सेवन करने से उदर की पीड़ा मिटती है.

10. पतले दस्त(अतिसार)- अजमोदा, सोंठ, मोचरस एवं धाय के फूलों को समान मात्रा में चूर्ण कर 3-6 ग्राम की मात्रा में छाछ के साथ दिन में 3-4 बार सेवन करने से पतले दस्त (अतिसार) बंद हो जाते हैं.

गुदा रोग:

1. अर्श- अजमोदा को गर्म कर कपड़े में बांधकर सेंक करने से अर्श (बवासीर की पीड़ा) की वेदना का शमन होता है.

वृक्कवस्ति रोग:

1. मूत्र-विकार-2-3 ग्राम अजमोदा मूल चूर्ण को पानी के साथ सुबह-शाम सेवन करना मूत्र विकारों में लाभकारी है.

2. अश्मरी-2-3 ग्राम अजमोदा चूर्ण में 500 मिग्रा यवक्षार मिलाकर 10 मिली मूली-पत्र रस के साथ, कुछ समय तक नित्य प्रात: व सायंकाल पीने से पथरी गल कर निकल जाती है. मूत्र भी खुलकर होता है.

3. मूत्राशय विकार- मूत्राशय में वायु का प्रकोप होने पर अजमोदा और नमक को स्वच्छ वस्त्र में बांधकर उदर के नीचे भाग में सेंक करने से लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग:

1. गठिया- अजमोदा, वायविडंग, देवदारू, चित्रक, पिप्पली मूल, सौंफ, पिप्पली, काली मिर्च 10-10 ग्राम, हरड़, विधारा 100 ग्राम, शुंठी 100 ग्राम इन सबका महीन चूर्ण कर 6 ग्राम की मात्रा में लेकर पुराना गुड़ मिश्रित कर उष्ण जल के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से शोथ, आमवात, जोड़ों का दर्द, पीठ व जांघ का दर्द व वात रोग नष्ट होते हैं.

त्वचा रोग:

1. कुष्ठ-शीत पित्त और कुष्ठ में अजमोद के 2-5 ग्राम चूर्ण को गुड़ के साथ मिलाकर 7 दिन तक दिन में दो-तीन बार सेवन करना चाहिए और पथ्य पूर्वक रहना चाहिए.

2. व्रण- व्रणों को शीघ्र पकाने के लिए इसे थोड़े गुड़ के साथ पीसकर सरसों के तेल में पकाकर बांधना चाहिए.

3. 1-4 ग्राम अजमोदा फल चूर्ण का सेवन करने से क्षतजन्य रक्तस्राव का स्तम्भन होता है.

सर्वशरीर रोग:

1. सवांग शोथ- सभी वायु विकारों में अजमोदा, छोटी पीपल, गिलोय, रास्ना, सोंठ, अश्वगंधा, शतावरी एवं सौंफ इन आठ पदार्थों को समभाग लेकर चूर्ण कर डेढ़ ग्राम की मात्रा में 10 ग्राम घृत के साथ दिन में दो बार सेवन करना चाहिए.

2. सर्वांग-पीड़ा- सर्वांग पीड़ा हो या पार्श्व पीड़ा (पसलियों का दर्द), अजमोदा को तेल में उबालकर मालिश करनी चाहिए. इसके पत्तों को गर्म करके रोगी के बिस्तर पर बिछा देना चाहिए, ऊपर से रोगी को हल्का कपड़ा ओढ़ा देना चाहिए.

3. शूल-अजमोदा मूल का 10-20 मिली क्वाथ या 2-5 ग्राम चूर्ण का सेवन सर्वांग शोथ और शूल में लाभप्रद होता है.

4. ज्वर- 4 ग्राम अजमोदा को नित्य प्रात: ठंडे पानी के साथ बिना चबाए, निगलने से जीर्ण ज्वर में लाभ होता है.

बाल रोग:

1.कृमि- बच्चों की गुदा में कृमि हो जाने पर अजमोदा को अग्नि पर डालकर धुआं देने से तथा इसको पीसकर लगाने से आराम मिलता है.

प्रयोज्यांग: बीज, मूल, पत्र तथा तैल
मात्रा: क्वाथ 10-20 मिली. चूर्ण 2-5 ग्राम चिकित्सक के परामर्शानुसार

निषेध:

1. अजमोदा विदाही है, अर्थात खाने से पश्चात छाती में जलन पैदा करता है.

2. गर्भशयोत्तेजक है इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

3. मिर्गी के रोगी को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए. ■

आचार्य बालकृष्ण

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

सवाल पूछो, ज़िंदगी बदलो

चौथी दुनिया ने अपने पाठकों एवं आम लोगों तक सूचना का अधिकार क़ानून की जानकारी पहुंचाने के लिए एक नई पहल की है. हम आपको बताएंगे कि कैसे सूचना का अधिकार क़ानून का इस्तेमाल कर आप दिखा सकते हैं घूस को घूंसा.

सूचना कौन देगा: प्रत्येक सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का पद होता है. आपको अपनी अर्जी उसके पास दाख़िल करनी होगी. यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह उस विभाग के विभिन्न भागों से आप द्वारा मांगी गई जानकारी इकट्ठा करे और आपको प्रदान करे.

आरटीआई आवेदन कहां जमा करें: आप अपनी अर्जी-आवेदन पीआईओ या एपीआईओ के पास जमा कर सकते हैं. केंद्र सरकार के विभागों के मामलों में 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है. मतलब यह कि आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई काउंटर पर अपना आरटीआई आवेदन और शुल्क जमा करा सकते हैं. वहां आपको एक रसीद भी मिलेगी. यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वह उसे संबंधित पीआईओ के पास भेजे.

यदि पीआईओ या संबंधित विभाग आरटीआई आवेदन स्वीकार न करे: ऐसी स्थिति में आप अपना आवेदन डाक द्वारा भेज सकते हैं. इसकी औपचारिक शिक़ायत संबंधित सूचना आयोग को भी अनुच्छेद 18 के तहत करें. सूचना आयुक्त को उस अधिकारी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाने का अधिकार है, जिसने आवेदन लेने से मना किया था.

पीआईओ या एपीआईओ का पता न चलने पर यदि पीआईओ या एपीआईओ का पता लगाने में कठिनाई होती है, तो आप आवेदन विभागाध्यक्ष को भेज सकते हैं. विभागाध्यक्ष को वह अर्जी संबंधित पीआईओ के पास भेजनी होगी.

अगर पीआईओ आवेदन न लें: पीआईओ आरटीआई आवेदन लेने से किसी भी परिस्थिति में मना नहीं कर सकता. भले ही वह सूचना उसके विभाग/कार्यक्षेत्र में न आती हो. उसे अर्जी स्वीकार करनी होगी. यदि आवेदन-अर्जी उस पीआईओ से संबंधित न हो तो वह उसे उपायुक्त पीआईओ के पास पांच दिनों के भीतर अनुच्छेद 6(3) के तहत भेज सकता है.

अगर पीआईओ सूचना न दें: एक पीआईओ सूचना देने से मना उन 11 विषयों के लिए कर सकता है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद आठ में दिए गए हैं. इनमें विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना, देश की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों की दृष्टि से हानिकारक सूचना, विधायिका के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाली सूचनाएं आदि. सूचना का अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उन 18 अभिकरणों की सूची दी गई है, जिन पर यह लागू नहीं होता. हालांकि उन्हें भी वे सूचनाएं देनी होंगी, जो भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी हों.

क्या प्रथम/द्वितीय अपील की फीस है: प्रथम अपील/द्वितीय अपील की कोई फीस नहीं है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने फीस का प्रावधान किया है.

क्या फाइल नोटिंग मिलता है: फाइलों की टिप्पणियां (फाइल नोटिंग) सरकारी फाइल का अभिन्न हिस्सा हैं और इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक की जा सकती हैं. केंद्रीय सूचना आयोग ने 31 जनवरी 2006 के अपने एक आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है.

सूचना क्यों चाहिए, क्या उसका कारण बताना होगा: बिल्कुल नहीं. कोई कारण या अन्य सूचना केवल संपर्क विवरण (नाम, पता, फोन नंबर) के अतिरिक्त देने की ज़रूरत नहीं है. सूचना क़ानून स्पष्टत: कहता है कि प्रार्थी से संपर्क विवरण के अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाएगा.■

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है-

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

मर्केल की भारत यात्रा के दौरान जर्मनी का भारत के स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्लीन एनर्जी कॉरीडोर और सोलर योजनाओं के विकास के संबंध में 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का अहम समझौता हुआ है. भारत की पेरिस में होने वाले ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मीट(सीओपी-21) के मद्देनज़र कार्बन उत्सर्जन स्तर कम करने की योजना है. जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र निर्धारित लक्ष्यों को इस तरह के सहयोग के बिना भारत पूरा नहीं कर सकता है. इस समझौते के अंतर्गत जर्मन कंपनियों के लिए लाइसेंस पाने की प्रक्रिया को तेज करना भी शामिल है.

मर्केल की भारत यात्रा

साझा विकास की नई शुरुआत

नवीन चौहान

जर्मनी की चांसलर ऐंजेला मर्केल की तीन दिवसीय भारत यात्रा व्यापक सहयोग के आश्वासन के साथ समाप्त हुई. यदि साझा सहयोग की इस नई राह पर दोनों देश चल सके, तो दोनों देशों के बीच का आर्थिक सहयोग 15 साल के चरम पर पहुंच जाएगा. मर्केल की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 18 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. जिसमें से अधिकांश उन क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिन पर दोनों देश लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनमें सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, निर्माण क्षेत्र में साझेदारी, कौशल निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं. चांसलर ऐंजेला मर्केल भारत में जर्मनी के लिए कारोबार के अवसर बढ़ाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ भारत आई थीं. इसलिए उन्होंने भारत के तकनीक केंद्र बेंगलुरू का दौरा किया. वह अपने इस उद्देश्य में सफल हुईं.

एंजेला मर्केल के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम जर्मनी को भारत के आर्थिक परिवर्तन में अपना स्वाभाविक सहयोगी समझते हैं. जर्मनी की क्षमता और भारत की प्राथमिकताएं एक दूसरे से जुड़ी हैं. यूरोपीय संघ में इस वक्त जर्मनी की हैसियत समूह के स्वाभाविक नेता की है. ऐसे में जर्मनी से कारोबारी संबंध बढ़ने से पूरे यूरोपीय बाजार से भारत की निकटता बढ़ेगी. इससे भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर रुकी हुई बातचीत भी आगे बढ़ेगी. राजनीतिक या कूटनीतिक मोर्चे पर भारत और जर्मनी में नज़दीकी का एक बड़ा कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दोनों देशों का साझा अभियान है. दोनों ही देश सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए जी-4 के मसौदे पर काम करने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं.

दोनों देश आतंकवाद और उग्रवाद के बढ़ते खतरे और इनकी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से सामूहिक सहयोग के लिए सहमत हैं. दोनों देशों ने आतंकवाद निरोधक कार्रवाई पर संयुक्त कार्यसमूह की बैठकें आयोजित करने का फैसला किया है.

मर्केल की भारत यात्रा के दौरान जर्मनी का भारत के स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्लीन एनर्जी कॉरीडोर और सोलर योजनाओं के विकास के संबंध में 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का अहम समझौता हुआ है. भारत की पेरिस में होने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मीट(सीओपी-21) के मद्देनज़र कार्बन उत्सर्जन स्तर कम करने की योजना है. जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र निर्धारित लक्ष्यों को इस तरह के सहयोग के बिना भारत पूरा नहीं कर सकता है. इस समझौते के अंतर्गत जर्मन कंपनियों के लिए लाइसेंस पाने की प्रक्रिया को तेज करना भी शामिल है.

जर्मनी भारत में निवेश करने वाला आठवां सबसे बड़ा देश है. वर्ष 1991 से फरवरी 2015 तक जर्मनी भारत में 8.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुका है, जबकि साल 2014 में भारत में जर्मनी ने 1.15 बिलियन अमेरिका डॉलर का निवेश किया है. वर्तमान में तकरीबन 1600 इंडो-जर्मन कॉलेबोरेशन पर काम चल रहा है, जबकि 600 से ज्यादा साझा संस्थान कार्यरत हैं. इसके साथ-साथ पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी में भारतीय निवेश में भी वृद्धि दर्ज की गई है. भारतीय संस्थानों ने यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं. दोनों देशों की आवश्यकताएं भले ही अलग-अलग हैं, जैसे कि जर्मनी को बड़ी मशीने बनाने में महारथ हासिल है. भारतीय आईटी उद्योग उन मशीनों को आधुनिक तकनीक से चलाने में सहयोग कर रहा है. मर्केल की बेंगलूरू यात्रा भी इस नजरिए से महत्वपूर्ण है. दोनों देश आपसी सहयोग से तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं.

दोनों देशों के बीच साल 2001 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की शुरूआत हुई थी, जो कि इंटर-गवर्नमेंटल कंसल्टेशन(आईजीसी) (अंतर-सरकारी परामर्शों की प्रणाली) के दो दौर की वार्ता के बाद और मजबूत हुई है. मर्केल की इस यात्रा के दौरान आजीसी की तीसरी वार्ता संपन्न हुई, जबकि इससे पहले साल 2011 में आईजीसी वार्ता नई दिल्ली में और साल 2013 में बर्लिन में आयोजित हो चुकी है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता के लिए कई संस्थागत प्रबंध हैं. अंतर-सरकारी परामर्शों की प्रणाली निश्चित तौर पर अनूठी है. और, इससे दोनों देशों के बीच संबंधों का हर तरह से विकास हुआ है. भारत अपने आर्थिक रूपान्तनरण के सपने को पूरा करने में जर्मनी को एक स्वाभाविक सहभागी के रूप में देखता है. इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मन अभियांत्रिकी तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कौशल अगली पीढ़ी के उद्योगों का सृजन कर सकते हैं, जो कि अधिक सक्षम, किफ़ायती तथा पर्यावरण अनुकूल होगा.

कौशल निर्माण, शिक्षा, रक्षा और निर्माण क्षेत्र में इस तरह के सहयोग मोदी सरकार की वरीयता में है. इसकी झलक जर्मनी और भारत के बीच हुए समझौतों में दिखाई दी. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी योजनाओं को लेकर जर्मनी खासा उत्साहित है. इसीलिए चांसलर मर्केल का भी एक डिजिटल एजेंडा है, जिसे वहां 4.0 के नाम से जाना जाता है. उसके तहत जर्मनी डिजिटल तकनीक का अपने कारोबार में विस्तार चाहता है. भारत उसमें सहायक बन सकता है. भारत को आधुनिक तकनीक और निवेश की जरूरत है, जबकि जर्मनी को आईटी में कुशल कर्मियों और बाजार की. यानी जर्मनी और भारत एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए विकास के अपने मकसदों को पाने की स्थिति में हैं. मर्केल की इस यात्रा के दौरान इसी दिशा में समझौतों को अंतिम रूप देने की कोशिश हुई. यह मोदी और मर्केल के बीच बनी केमेस्ट्री का प्रमाण है. मर्केल की यात्रा का मकसद भारत में जर्मन कंपनियों के कारोबार की राह आसान बनाना था. अब उन जर्मन कंपनियों की परियोजनाओं को तेजी से हरी झंडी मिलेगी. इस तरह से वे प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सकारात्मक भूमिका निभा सकेंगी. जर्मन कंपनियों के लिए फास्ट-ट्रैक मंजूरी प्रक्रिया पर समझौते के तहत जर्मन कंपनियों को परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो अप्रूवल दिया जाएगा.

दोनों देश आतंकवाद और उग्रवाद के बढ़ते खतरे और इनकी वैश्विक की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से सामूहिक सहयोग के लिए सहमत हैं. दोनों देशों ने आतंकवाद निरोधक कार्रवाई पर संयुक्त कार्यसमूह की बैठकें आयोजित करने का फैसला किया है. इसके अलावा स्विस कंपनी नेस्ले के उत्पाद मैगी के हालिया विवाद के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के क्षेत्र में सहयोग का निर्णय भी मर्केल-मोदी के बीच की बैठक में लिया गया. जर्मन भाषा को भारत में एक विदेशी भाषा के तौर पर और आधुनिक भारतीय भाषाओं के जर्मनी में प्रचार के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय के बीच एक संयुक्त सहमति घोषणापत्र पर दस्तखत किए गए. इस करार को भारत में जर्मन भाषा विवाद के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है. अप्रैल 2015 में मोदी की जर्मनी यात्रा के बाद स्मार्ट सिटीज़, स्वच्छ गंगा तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जर्मन सहयोग ने एक ठोस आकार ले लिया है. मोदी की जर्मनी यात्रा के तकरीबन छह महीने बाद ही भारत आना मर्केल की प्राथमिकताओं में भारत के बढ़े महत्व को इंगित करता है. मर्केल की यात्रा के बाद यह तय हैं कि इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में और घनिष्ठता आएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

मैटियो मेसिना डेनारो

लगभग दो वर्ष पूर्व इटली पुलिस ने इसी तस्वीर के आधार पर डेनारो की नई तस्वीर जारी की, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं लगा पाया है. स्टाइल का दीवाना इटैलियन माफिया शक्ल से ये जितना शरीफ और स्मार्ट लगता है, उतना ही खूंखार है.

मैटियो मेसिना डेनारो इटली के माफियाओं का नया गॉडफादर है. 47 साल का मैटियो मेसिना डेनारो दुनियाभर में कुख्यात सिसली माफियाओं की दुनिया का नया क्रूर चेहरा है. पोर्श की चमचमाती स्पोर्ट्स कारों रोलैक्स की हीरे जड़ी घड़ियां और महंगे रे बैन के चश्मों का शौकीन डेनारो खतरनाक और क्रूर कातिल है. इटली के माफिया परिवार में पैदा होने वाले डेनारो ने महज 18 साल की उम्र में पहला कत्ल किया था. अब तक ये खुद अपने हाथों से 500 से ज्यादा लोगों को उनकी जिन्दगी से मुक्ति दे चुका है. कई वर्षों से इटली पुलिस का ये सबसे मोस्ट वांटेड चेहरा है. लेकिन इटली पुलिस के पास माफियाओं के इस सरगना की सिर्फ 27 साल पुरानी एक तस्वीर है. लगभग दो वर्ष पूर्व इटली पुलिस ने इसी तस्वीर के आधार पर डेनारो की नई तस्वीर जारी की, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं लगा पाया है. स्टाइल का दीवाना इटैलियन माफिया शक्ल से ये जितना शरीफ और स्मार्ट लगता है, उतना ही खूंखार है. हत्या करना इसके लिए मक्खी मारने के समान है. माफिया जगत में डियाबोलिक नाम से मशहूर डेनारो फर्जी नाम अलेसियो से अपना अवैध धंधा चलाता है. इटली समेत अरब देशों और अमेरिका, ब्रिटेन में भी इसके अवैध कारोबार हैं. डेनारो कोसा नोस्त्रा कैंपेन का अगुवा है. इस कैंपेन के तहत इटली में आतंकियों के ख़िलाफ अभियान को रोकने के लिए माफियाओं ने बड़े-बड़े विस्फोट किए थे. डेनारो की पहचान एक ऐसे अय्याश माफिया की है, जो महिलाओं के अलावा महंगी स्पोर्टस कार, रोलेक्स की घड़ियों, रे बेन के सनग्लासेज और अरमानी के डिजाइनर कपड़ों का शौकीन है. सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि डेनारो को गंभीर मायोपिया (नजर कमजोर) था और उसके लिए बार्सिलोना के एक क्लीनिक में चोरी छिपे इलाज भी कराया. 1962 में एक माफिया परिवार में पैदा हुए डेनारो ने 14 साल में पहली बार बंदूक पकड़ी और 18वें साल में पहली हत्या की. अब तक डेनारो करीब 50 से ज्यादा खून कर चुका है. एक बार डेनारो ने कहा था कि मैं इतने खून करना चाहता हूं कि एक कब्रिस्तान भर जाए. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

क्या लीबिया में बन पाएगी राष्ट्रीय एकता सरकार

महीनों चली जटिल बातचीत के बाद लीबिया में राष्ट्रीय एकता सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है. लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि बर्नार्डिनो लियोन ने मोरक्को में इसका ऐलान करते हुए कहा कि फ़ाएज़ सराज नई सरकार के प्रधानमंत्री होंगे. साल 2014 से ही लीबिया में दो परस्पर विरोधी सरकारें काम कर रही हैं. एक सरकार राजधानी त्रिपोली में है, जो इस्लामियों के समर्थन से चल रही है, दूसरी देश के पूर्वी हिस्से पर काबिज़ है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल है. यह टोबरुक से संचालित है. राष्ट्रीय सरकार में तीन उप-प्रधानमंत्री होंगे जो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण लीबिया का प्रतिनिधित्व करेंगे. एकता सरकार के प्रस्ताव का विरोध अभी से शुरू हो गया है. त्रिपोली स्थित जनरल नेशनल कांग्रेस (जीएनसी) के अब्दुल सलाम बिलाशहीर ने कहा कि हम इस प्रस्तावित सरकार में शामिल नहीं होंगे. हमारे लिए इसका कोई मायने नहीं है और हमसे कोई राय मशविरा नहीं किया गया था. दूसरी ओर, इनके विरोधी टोबरुक स्थित प्रतिनिधि सभा के इब्राहिम अलज़गियात ने कहा कि प्रस्तावित सरकार की वजह से देश का बंटवारा हो जाएगा और यह एक मज़ाक बन कर रह जाएगा. लियोन की पसंद समझदारी भरी नहीं है. ■

रूस ने नहीं दागी मिसाइलें

रूस ने कैस्पियन सागर से सीरिया पर दागी गई मिसाइलों के ईरान में गिरने से इंकार किया है. अज्ञात अमरीकी अधिकारियों ने दावा किया है कि कैस्पियन सागर से दागी गईं चार रूसी मिसाइलें ईरान में गिरी हैं. अधिकारियों ने यह भी कहा कि नुकसान की जानकारी स्पष्ट नहीं है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा है कि कैस्पियन सागर से दागी गई सभी मिसाइलें निशाने पर लगी हैं. रूस ने पहले दावा किया था कि उसने उत्तरी पश्चिमी सीरिया में आईएस के ठिकानों पर 26 मिसाइलें दागीं हैं. सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और रूस के संबंध गहरे बताए जाते हैं. रूस के रक्षा मंत्रालय ने ईरान पर मिसाइल गिरने की रिपोर्टों पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है. इसी बीच नाटो ने सीरिया में रूस के बढ़ते दख़ल के मद्देनज़र अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है. नाटो इलाक़े में तेज़ी से सैन्यबल तैनात करने की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है. पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस अपने हवाई हमलों में मुख्य रूप से राष्ट्रपति बशर अल असद के विद्रोहियों को निशाना बना रहा है. रूस इन आरोपों से इंकार करते हुए कहा है कि उसके निशाने पर इस्लामिक स्टेट और अन्य चरमपंथी समूह हैं. ■

फ़ीफ़ा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव हुए निलंबित

विश्व फुटबॉल को संचालित करने वाली समीति फ़ीफ़ा ने अपने अध्यक्ष सेप ब्लैटर, उपाध्यक्ष माइकल पलातिनी और महासचिव जेरोम वैलके को 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया है. पूर्व फ़ीफ़ा उपाध्यक्ष चुंग मांग-जून पर छह साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और 1,00,000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया गया है. यह सज़ा फ़ीफ़ा की एथिक्स कमेटी ने दी है. कमेटी ब्लैटर, वैलके और यूएफ़ा अध्यक्ष पलातिनी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही थी. इसने एक बयान में कहा, इन फ़ैसलों का आधार वह जांच है, जो एथिक्स कमेटी के जांच प्रकोष्ठ ने की थी. इन तीनों अधिकारियों को अस्थाई रूप से फुटबॉल से जुड़ी गतिविधियों से निलंबित किया गया है. उन्होंने किसी भी ग़लत काम में शामिल होने से इनकार किया है. फ़ीफ़ा की एथिक्स कमेटी ने 79 वर्षीय ब्लैटर के ख़िलाफ़ जांच तब शुरू की थी. जब स्विस अटॉर्नी जनरल ने उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामला शुरू किया. एथिक्स कमेटी ने 60 वर्षीय पलातिनी के ख़िलाफ़ भी 20 लाख यूरो (14.74 करोड़ रुपये से ज़्यादा) के भुगतान की जांच शुरू कर दी. उन्हें यह भुगतान ब्लैटर के लिए परामर्श कार्य करने के नौ साल बाद किया गया था. ■

बेलारूस की स्वेतलाना को नोबेल साहित्य पुरस्कार

इस साल के साहित्य में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है. स्वेतलाना एलेक्सियाविच को यह पुरस्कार महिलाओं के संघर्ष और साहस पर उनके लेखन के लिए दिया गया है. 67 साल की स्वेतलाना राजनीतिक लेखिका के रूप में जानी जाती हैं और पहली पत्रकार भी हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से नवाज़ा गया है. इससे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपविंग, अर्नस्ट हेमिंगवे और पेट्रिक मोडियानो को दिया गया है. इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 80 लाख क्रोनर मिलेंगे. स्वेतलाना एलेक्सियाविच का जन्म 31 मई 1948 में यूक्रेन के इवानो-फ्रेंकिविस्क में हुआ था. बाद में वे अपने परिवार के साथ बेलारूस चली गईं थीं. वे फ़िलहाल बेलारूस में ही रहती हैं. उनकी पहली पुस्तक थी द्वितीय विश्व युद्ध पर जिसका का नाम था द अनवोमनली फ़ेस ऑफ़ द वॉर. इसमें उन्होंने उन हज़ारों रूसी महिलाओं के संघर्ष और पीड़ा का ज़िक्र किया है, जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया. उन्होंने इस किताब के जरिए कहा है कि रूस की जीत का श्रेय उन महिलाओं को नहीं मिल पाया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

सद्गुरु का अर्थ है–एक साकार मानव रूपी शरीर, जिसमें एक महत् ईश्वरीय चेतना निवास कर रही है. वह चेतना–शक्ति चाहे तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को आधार बना सकती है. जैसे कि आदि शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया था.सामान्य आदमी की चेतना शक्ति इतने उच्चतर या सूक्ष्म स्तर तक नहीं पहुंची है कि वह जब चाहे अपनी चेतना–शक्ति को अन्य शरीर में प्रवेश करा सके. वस्तुत: भक्त पहले सद्गुरु के शारीरिक रूप की पूजा करना शुरू करते हैं.

साईं वंदना

भिन्न धर्म-परंपराएं व भिन्न पूजा पद्धतियां

अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए

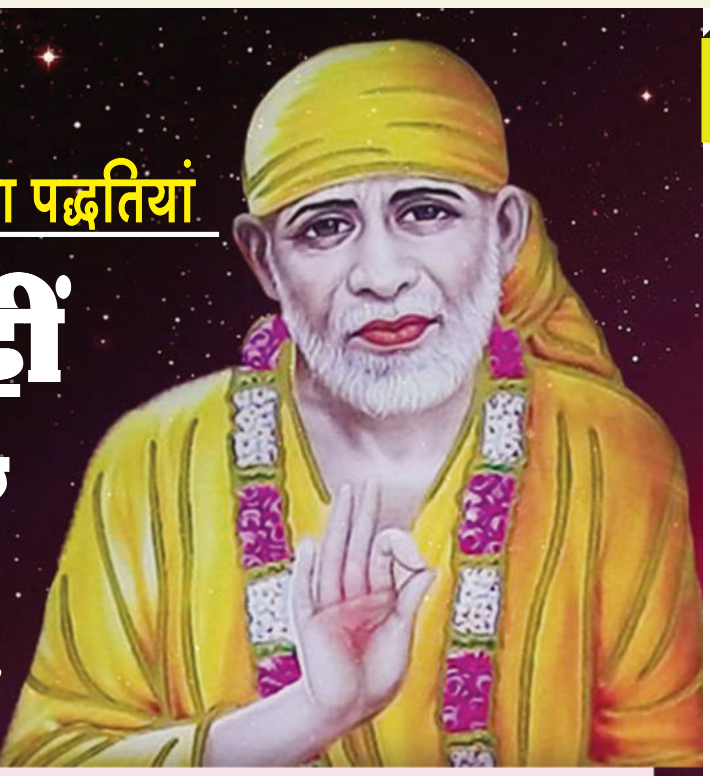

कोई व्यक्ति ईश्वर को किस रूप से पुकारेगा, यह उसके आत्मा और परमात्मा के बीच एक समझौता है, जिसमें और कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

यदि ईश्वर एक है, तो उसकी आराधना–पद्धतियों में इतनी विभिन्नता क्यों है?

आराधना या चिंतन के बारे में ईश्वर ही भिन्न–भिन्न लोगों को या धार्मिक समुदायों को भिन्न–भिन्न मार्ग दिखाते हैं. अपने पूर्व जन्म के संस्कार एवं इस जन्म में प्राप्त धर्म और संस्कृति के अनुसार लोग किसी मार्ग का अनुसरण करते हैं. कोई व्यक्ति ईश्वर को किस रूप से पुकारेगा, यह उसके आत्मा और परमात्मा के बीच एक समझौता है, जिसमें और कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता. दूसरों की आराधना पद्धति या उपासना को गलत साबित करने का प्रयास और अपनी धर्म परंपराओं को श्रेष्ठता देने का प्रयास धर्मों में विभिन्नता की सृष्टि करता है. चूंकि विभिन्न लोगों की विभिन्न परंपराएं होती हैं, इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण ने कहा–

श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्.
स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह:.

(अर्थात–इसलिए उन दोनों(राग–द्वेष) को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण कर, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है. अपने धर्म में मरना भी कल्याणपरक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है.)

श्रीमद्भगवद्गीता,अ.3/35

इसलिए किसी के धर्म को–दूसरा कोई चाहे कितना ही गलत समझे, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा कि श्री साई सच्चरित्र में बाबा ने भी कहा.

प्रतीक पूजा

प्रतीक पूजा का क्या महत्व है?

परमेश्वर, परब्रह्म एवं भगवान की परिकल्पना आध्यात्मिक अनुभूति–प्राप्त संत एवं महात्माओं द्वारा परम व्यापक रूप से की गई है. साथ ही उन्होंने ईश्वरीय सत्ता को सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप में भी अनुभव किया है. जिन्होंने कठिन आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए और गुरु–कृपा द्वारा ईश्वर के चैतन्य रूपी स्वरूप का अनुभव कर लिया, उनके लिए प्रतीक–पूजा की आवश्यकता नहीं है. प्रतीकों की पूजा, जैसे कि मूर्ति, फोटो, चित्र आदि की पूजा, भक्तगण प्रारम्भिक अवस्था में करते हैं. यह इसलिए है कि जो कठिन योग–साधना द्वारा अपने चैतन्य को विश्व–भुवन में व्याप्त करने की क्षमता नहीं रखते हैं, उस व्यापक रूप की एक प्रतीक–रूप में पूजा कर सकते हैं. समष्टि को व्यष्टि रूप से, बृहत् को क्षेत्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए सांकेतिक उपादानों, रूपक आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि साहित्य में होता है. इनके द्वारा उस मूल स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है, पर साकार प्रतीक यानी मूर्ति की पूजा करते–करते निराकार रूप तक पहुंचा जा सकता है.

देवी पूजा

हिंदू धर्म में देवी पूज्य होती हैं, पर अन्य धर्मों में देवी पूजा नहीं होती. क्या आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए देवी–पूजा ही एक मात्र रास्ता है?

पहले तो समझना चाहिए कि हिंदु धर्म में कहलाने वाली देवी वास्तव में क्या हैं? देवी और दैवी आदि दोनों शब्दों का अर्थ लगभग एक ही है. ईश्वर की शक्ति को दैवी शक्ति कहते हैं और उसका नारी रूप प्रतीक है देवी. वास्तव में ब्रह्म न पुरुष है, न नारी– वह निर्गुण है. हिंदु धर्म में श्री दुर्गा के दस हाथ ईश्वर की दस शक्तियों की समष्टि दर्शाते हैं. अत: अगर किसी धर्म में इन प्रतीकों का प्रयोग न भी हो, फिर भी इन्हीं अदृश्य शक्तियों के माध्यम से समस्त जड़ और जीव वस्तुएं नियंत्रित होती हैं.

सद्गुरु–पूजा

सद्गुरु की पूजा को क्या सगुण–साकार पूजा कहेंगे?

जी हां. सद्गुरु का अर्थ है–एक साकार मानव रूपी शरीर, जिसमें एक महत् ईश्वरीय चेतना निवास कर रही है. वह चेतना–शक्ति चाहे तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को आधार बना सकती है. जैसे कि आदि शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया था. सामान्य आदमी की चेतना शक्ति इतने उच्चतर या सूक्ष्म स्तर तक नहीं पहुंची है कि वह जब चाहे अपनी चेतना–शक्ति को अन्य शरीर में प्रवेश करा सके. वस्तुत: भक्त पहले सद्गुरु के शारीरिक रूप की पूजा करना शुरू करते हैं. सद्गुरु की पूजा वे पहले इसलिए करते हैं कि उनकी कृपा, क्षमा, शांति आदि गुणों से भक्त अभिभूत हो जाता है. इसी कारण शरीर–धारण के लिए या एक शरीर में निवास करने के कारण अथवा ये कहें कि शरीर–रूपी एक क्षेत्र में निवास करने के कारण वे साकार होते हैं और ईश्वरीय गुणों से विभूषित होने के कारण श्रीगुरु सगुण–साकार हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

धर्म

महालक्ष्मी करती हैं मुराद पूरी

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

श्री महालक्ष्मी मंदिर भारत के हिंदू धर्म के शक्ति पीठों में से एक है. महालक्ष्मी मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है. महालक्ष्मी मंदिर प्रसिद्ध है, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहां आता है. उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं ने बनवाया था. यह मंदिर 27 हजार वर्गफुट में फैला है. आदि शंकराचार्य ने महालक्ष्मी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी. कोल्हापुर देवी का ऐसा पवित्र स्थान है, जिसे दक्षिण की काशी माना जाता है. आमतौर पर किसी भी तीर्थस्थान को देवी या देवता के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोल्हापुर और करवीर यह राक्षस के नाम पर है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि साल में एक बार सूर्य की किरणें देवी की प्रतिमा पर सीधे पड़ती हैं. मंदिर के बाहर लगे शिलालेख से पता चलता है कि यह 1800 साल पुराना है. मंदिर में श्री महालक्ष्मीजी की मूर्ति तीन फुट ऊंची, चतुर्भुज है. इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा ने तमोगुण से युक्त गय, लवण और कोल्ह ऐसे तीन मानस पुत्रों का निर्माण किया. बड़े पुत्र गय ने ब्रह्मा की उपासना कर वर मांगा कि उसका शरीर देवपितरों तीर्थ से भी अधिक शुद्ध हो और ब्रह्माजी के तथास्तु कहने के साथ गय अपने स्पर्श से पापियों का उद्धार करने लगा. यम की शिकायत पर देवताओं ने बाद में उसका शरीर यज्ञ के लिए मांग लिया था. केशी राक्षस के बेटे कोल्हासुर के अत्याचार से परेशान देवताओं ने देवी से प्रार्थना की. श्री महालक्ष्मी ने दुर्गा का रूप लिया और ब्रह्मास्त्र से उसका सिर काट दिया. मरने से पहले उसने वर मांगा था कि इस इलाके का नाम कोल्हासुर और करवीर बना रहे. समय के साथ कोल्हासुर से कोल्हापुर हुआ, लेकिन करवीर वैसा ही कायम रहा.

अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी कलश स्थापना से उत्सव की तैयारी होती है. पहले दिन बैठी पूजा, दूसरे दिन खड़ी पूजा, त्र्यंबोली पंचमी, छठे दिन हाथी के हौदे पर पूजा, रथ पर पूजा, मयूर पर पूजा और अष्टमी को महिषासुरमर्दिनी सिंहवासिनी के रूपों में देवी का उत्सव दर्शनीय होता है. कोल्हापुर की श्री महालक्ष्मी को करवीर निवासी अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि यहां दीपावली की रात महाआरती में मांगी गई मुराद पूरी हो जाती है. ■

प्रेरक कहानी

विश्वास है, तो प्रगति है

एक बार प्रभु यीशु को साइमन नाम के एक भक्त ने भोज के लिए आमंत्रित किया. प्रभु यीशु जब उस व्यक्ति के घर पहुंचे, तो मैग्दालिन नाम की स्त्री ने उनके पैर पकड़ लिए और पैर धोने लगी. मैग्दालिन एक वेश्या थी. नगर में उसके चर्चे आम थे, इसलिए वह लोग उससे घृणा करते थे. साइमन आश्चर्य चकित था कि प्रभु ईशदूत हैं वह इस मैग्दालिन को दूर हटा देंगे. लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया. उन्होंने मैग्दालिन को पैर धोने दिए. प्रभु यीशु अपने भक्त साइमन के मन की बात समझ गए. उन्होंने उससे कहा, एक बार एक साहूकार को दो लोगों से क्रमश: 500 और 50 पेंस का ऋण वसूल करना था. उनके पास ऋण देने के लिए धन नहीं था. अत: उन्होंने दोनों का ऋण माफ कर दिया. उन्होने पूछा, बताओ दोनों में एक तीसरा व्यक्ति दोनों में से किसे पसंद करेगा? साइमन ने उत्तर दिया जिसने उनका ऋण माफ किया उसे.

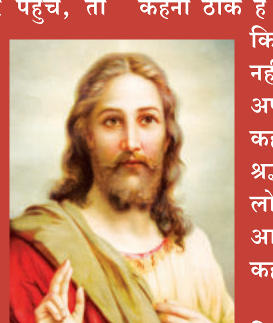

साइमन की बात सुनकर प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है साइमन. जब मैंने तुम्हारे घर में प्रवेश किया, तो तुमने मेरे चरणों के लिए पानी नहीं दिया. इस स्त्री ने मेरे पांव धोए और अपने केशों से पोंछे. मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस स्त्री के अनेक पाप श्रद्धा से धुल गए हैं. तभी वहां उपस्थित लोगों में से किसी ने प्रभु यीशु से पूछा, आपको दूसरों के पाप दूर करने की शक्ति कहां से मिलती है?

प्रभु यीशु ने कहा, मैग्दालिन का यह विश्वास है कि संत की सेवा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसने उसे निष्पाप बना दिया. दुनिया विश्वास पर टिकी है. हमें विश्वास है कि हम यदि भगवान की पूजा करेंगे, तो वो मनोवांछित फल देंगे. हमारे पापों को क्षमा कर पुण्य देंगे. उनपर यही विश्वास हमारा उद्धार करता है. ■

पाठकों की दुनिया

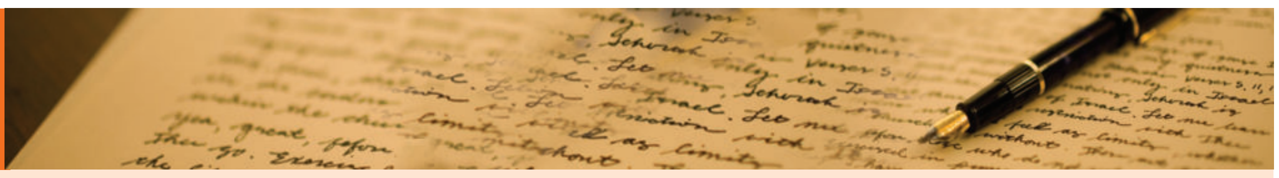

प्रायश्चित करें सांसद

विगत मानसून सत्र के दौरान प्रमुख विपक्षी, राजनीतिक दल कांग्रेस की ओर से जैसा नकारात्मक व्यवहार किया गया, इससे पहले शायद ही किसी ने किया है, इस प्रकरण में कांग्रेस ने न तो राष्ट्रीय हितों की चिंता की और न अपने हितों की. इससे आम जनता के बीच कांग्रेस की छवि एक ऐसे दल की बन गई है, जो जन–हित के विरोध पथ पर चलकर देश की प्रगति को रोककर खड़ी हो, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले स्वयं के जीएसटी विधेयक को ही कांग्रेस ने ही पारित नहीं होने दिया, जिसके दुष्परिणाम पीढ़ियों तक अपना प्रभाव डालते रहेंगे. संसद के कामों में व्यवधान का प्रभाव सांसदों के वेतन भत्तों तथा सुविधाओं पर तो पड़ा नहीं, बल्कि सैकड़ों करोड़ का अपव्यय अवश्य जनता की जेब से हुआ. अत: सभी पक्ष–विपक्ष के सांसद मिलकर मानसून संत्र के व्यवधान के लिए राष्ट्र से क्षमा मांगे तथा व्यर्थ गए दिनों का वेतन भत्ता स्वत: प्रधानमंत्री राहत कोष में जमाकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें.

–सत्य प्रकाश शिक्षक, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

बिना मीटर बिजली देना दंडनीय घोषित हो

मैं इस पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या आप नहीं चाहते कि पावर कॉरपोरेशन घाटे से उबरे और प्रदेश के नागरिकों को 24 घंटे बिजली मिले? यदि आप सूबे की जनता के हितैषी हैं, तो कृपा कर एक आदेश जारी करें कि बिना मीटर लगाए किसी को भी बिजली का कनेक्शन न दिया जाए. बिना मीटर बिजली देकर और फैक्ट्रियों के मीटर उल्टा घूमाकर(पूराने मीटर) विभाग के विभीषणों ने ही पावर कॉरपोरेशन का भट्ठा बैठाया है. विकास का पहिए चलता रहे, इसके लिए ऊर्जा चाहिए. सरकार हर छह माह के बाद एक विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना करे.

–राज किशोर पाण्डेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

विश्वसनीय समाचार पत्र

हिन्दी पत्रकारिता को नया आयाम देने वाला साप्ताहिक अख़बार चौथी दुनिया का नाम सर्वाधिक लोकप्रिय है. खोजपूर्ण खबरों को नए तरीके से प्रस्तुत करने का श्रेय यदि किसी अख़बार को जाता है, तो वह है-चौथी दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र. अपनी विशेष शैली, आम भाषा, तेज–तर्रार सम्पादकीय लेखों तथा विशेष प्रस्तुतीकरण ने इसे न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का लोकप्रिय साप्ताहिक अख़बार बना दिया है. चौथी दुनिया की सफलता का कारण इस पत्र का जनता से जुड़ा होना है. किसी भी विषय पर सम्पूर्ण और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराने के पथ से यह कभी नहीं डिगा. चौथी दुनिया अख़बार पाठकों का ख़बरों के जरिए मार्गदर्शन करता आया है. किसी भी तरह की खबर हो. चाहे भारतीय सेना में फर्जी तरीके से नेपाली नक्सलियों की भर्ती का मामला हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े सटीक लेख हों. सच को उजागर करने में चौथी दुनिया अख़बार पूरी तरह से निष्पक्ष भूमिका निभाता आ रहा है. चौथी दुनिया अपने पाठकों को सियासी दुनिया से लेकर संपादकीय पेज, विविध दुनिया, बाकी दुनिया, साई की महिमा, साहित्य दुनिया, एवं जगमग दुनिया की हर खबरों से रूबरू कराता है. हर सप्ताह चौथी दुनिया अख़बार कोई न कोई संस्करण में विशेष सामग्री लेकर आता है. चौथी दुनिया साप्ताहिक अखबार पूर्ण रुप से पाठकों के लिए एक विश्वसनीय सूत्र है.

–रितु मल्होत्रा, *द्वारका, नईदिल्ली.*

किसानों को मजबूत बनाओ

आपके लेखक विशाल जी ने अच्छा लेख लिखा है. उन्होंने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को खतरा बताया है. वह बहुत ही सोचनीय है और हमको अपनी अर्थव्यवस्था के आधार को मजबूत बनाना पड़ेगा. जैसे छोटे–छोटे धंधे और अपने देश के किसान को मजबूत बनाना पड़ेगा. वरना वह दिन दूर नहीं जो सोने की चिड़िया का सपना देखने वाले हमारे हाथ में कटोरा थमा दें

–शशिकांत पचौरी, *ई–मेल के द्वारा.*

प्रशंसनीय आलेख

तिलिस्म के ऊपर लिखा गया लेख जो विशाल जी ने लिखा है. प्रशंसनीय है, उनके इस लेख को सभी निवेशकों तथा सरकारी तंत्र को पहुंचाना चाहिए. इस लेख से साफ़–साफ़ दिखता है किस तरह हमारा देश भी उसी राह पर जा रहा है जिस राह पर चीन चला है.

–गजेन्द्र सिंह, *ई–मेल के द्वारा.*

राजनीतिक दलों की चुनौती

कवर स्टोरी–बिहार विधानसभा चुनाव, राजनीति दलों के लिए चुनौती है(05 अक्टूबर–11 अक्टूबर, 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. मैं मनीष कुमार से सहमत हूं कि भारतीय राजनीति में बिहार का चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव पहले के चुनावों से कुछ अलग है. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू यादव का भविष्य टिका हुआ है. अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है, तो नीतीश कुमार मजबूत होंगे और भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के गैर भाजपा और गैरकांग्रस दलों के सबसे मजबूत नेता होंगे. लालू यादव और कांग्रेस को बिहार चुनाव में जीत से संजीवनी मिल जाएगी. इस बार बिहार विधानसभा में यह तय कर पाना मुश्किल है कि जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता, विकास किस पर जनता वोट करेगी या मतों का ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए जातिवाद से लेकर ध्रुवीकरण तक के सभी दांव आजमा रही हैं. बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है. सच कहें तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौती है.

–नवल किशोर उपाध्याय, *बक्सर, बिहार.*

अभिव्यक्ति की आज़ादी की राजनीति

अनंत विजय

कन्नड़ के साहित्यकार प्रोफेसर कालबुर्गी की हत्या के बाद दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक में साहित्यिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है. हिंदी जगत में भी जादुई यथार्थवादी कथाकार उदय प्रकाश ने भी इसे एक अवसर की तरह देखते हुए अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान करके गर्माने की कोशिश की. साहित्य से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि गर्माने की नहीं, भुनाने की कोशिश की. इसी तरह से जनवादी लेखक संघ और चंद लेखकों ने भी इस पर एतराज जताते हुए आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन खास विचारधारा के इन लेखकों की साख इतनी नहीं है कि हिंदी जगत आंदोलित हो सके. खैर, यह मुद्दा नहीं है. मुद्दा यह है कि कालबुर्गी की हत्या के बाद कर्नाटक के जो तमाम छुटभैये संगठन हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्होंने भी इसे एक अवसर की तरह देखा और प्रचार पिपासा ने उन्हें आक्रामक कर दिया. ताजा मामला है, कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े एक कार्यकर्ता द्वारा दी गई धमकी. बजरंग दल से जुड़े होने का दावा करने वाले एक शख्स ने कर्नाटक के रैशनलिस्ट माने जाने वाले लेखक केएस भगवान को जान से मारने की धमकी देते हुए एक ट्वीट किया है. ख़बर के आम होने के बाद पुलिस ने केएस भगवान को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी. हिंदी जगत के कई उत्साही लेखकों ने इसे फासीवाद के आसन्न ख़तरे की तरह देखा और केंद्र सरकार से जोड़कर छाती कूटने लगे. फासीवाद का राग बहुत लंबे समय से भारत में बजाया जा रहा है, लेकिन अब तक फासीवाद आ नहीं पाया है. दरअसल, फासीवाद-फासीवाद चिल्लाने वाले लोगों को भारतीय लोकतंत्र में आस्था और उसकी ताकत में भरोसा नहीं है. भारतीय लोकतंत्र अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसे किसी भी तरह से भटकाना या भरमाना बहुत मुश्किल है. इंदिरा गांधी ने 1975 में एक कोशिश की थी, लेकिन देश की जनता ने दो साल में ही उन्हें सबक सिखा दिया था. अब शायद ही कोई ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाए.

कर्नाटक अथवा यह कहें कि पूरे दक्षिण भारत में साहित्यिक कृतियों के ख़िलाफ़ इस तरह की घटनाएं पहले भी घटती रही हैं, धमकियां आदि भी दी जाती रही हैं, लेकिन प्रोफेसर कालबुर्गी की हत्या के बाद ख़तरा अवश्य बढ़ गया है. एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहां हर किसी को अपनी बात कहने का जितना हक़ है, उतना ही उस पर विरोध जताने का हक़ भी है, लेकिन हत्या करना या क़ानून को अपने हाथ में लेना बेहद आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है. अब अगर हम दक्षिण भारत में इस तरह की बढ़ती घटनाओं की वजहों की तह में जाएं, तो लगता है कि इसके लिए वहां की सामाजिक संरचना और कुरीतियां बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं. वहां के कई लेखकों ने सामाजिक विषमता के मद्देनज़र अपनी लेखनी से उस पर ज़ोरदार प्रहार किया. लेखकों ने समाज में व्याप्त विसंगतियों के लिए धर्म को ज़िम्मेदार मानते हुए विरोध की ध्वजा थामी. संभव है कि उन्हें यह बेहतर आधार लगा हो. धर्म के इस विरोध में कई बार तो लेखन की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार हो गई. जैसे अगर हम केएस भगवान की ही बात करें, तो उन्होंने 1985 में एक किताब लिखी थी, शंकराचार्य एंड रिएक्शनरी फिलॉसफी. इस किताब में उन्होंने शंकराचार्य को जातिवाद की वकालत करने वाला साबित करने की कोशिश की थी. संस्कृत के श्लोकों के आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया था कि शंकराचार्य दलितों और स्त्रियों के ख़िलाफ़ थे. केएस भगवान का कहना था कि शंकराचार्य दलितों और स्त्रियों की शिक्षा के ख़िलाफ़ थे. उस वक्त जब उनकी किताब आई थी, तब भी उनका विरोध हुआ था, धरने-प्रदर्शन हुए थे. उसके बाद भी प्रोफेसर भगवान अपने स्टैंड पर कायम रहे थे और यह सही भी था. उन्होंने फरवरी में एक सेमिनार में कहा कि भगवद् गीता के नवें अध्याय को जला दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें स्त्री, वैश्य और शूद्र को पापी कहा गया है.

आरोप है कि अभी सितंबर में एक सेमिनार में प्रोफेसर भगवान ने कथित तौर पर कहा कि भगवद् गीता पढ़ने वाला आतंकवादी बन सकता है. उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा करने वालों का इल्जाम है कि एक सेमिनार में उन्होंने राम और कृष्ण के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि वे अपने जैविक पिता की संतान नहीं थे. इस तरह के वक्तव्य के बाद उनका विरोध हुआ और उनके ख़िलाफ़ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुक़दमा भी दर्ज किया गया. भारत के संविधान में हर किसी को अपनी बात कहने का हक़ हासिल है, लेकिन उसी संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा भी तय की गई है. दोनों के बीच एक बहुत बारीक-सी रेखा है, जिसे बहुधा जोश में लोग लांघ जाते हैं. परिणाम यह होता है कि परिधि पर बैठे लोगों को केंद्र में आने का मौक़ा मिल जाता है और वे उग्र-हिंसक होने लगते हैं, जो क़ानून सम्मत नहीं है तथा जिसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है. विचारों की लड़ाई विचार से लड़ी जा सकती है, बंदूक से नहीं. बंदूक से विचार को मानने के लिए बाध्य करने का सोवियत रूस और चीन का लंबा इतिहास रहा है, जो कि भारत के लिए मुफीद नहीं है. भारत की जनता बार-बार इसे ठुकरा भी चुकी है.

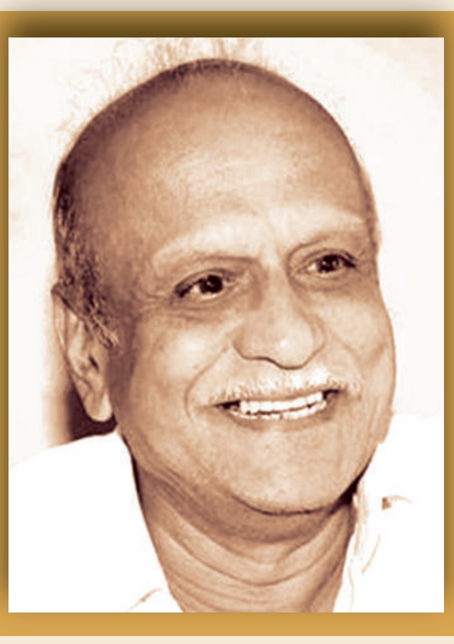

आज जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरने की कोशिश करते हैं और आज़ादी के लिए ख़तरा बताते हैं, उन्हें एक और संदर्भ याद रखना चाहिए. संविधान में पहले संशोधन को लेकर बहुत ज़ोरदार बहस हो रही थी. मसला कुछ मौलिक अधिकारों को लेकर संशोधन का था. कई मसलों के अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान है, उस पर कुछ अंकुश लगाए जाने की बात हो रही थी. जवाहर लाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी एवं अंबेडकर समेत कई नेता इस पक्ष में थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पूर्ण नहीं होनी चाहिए. बहस के दौरान जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि आज़ाद प्रेस युवाओं के दिमाग में ज़हर भर रहा है.

विचारों की लड़ाई का एक उदाहरण गांधी जी के हवाले से समझा जा सकता है. 1927 में एक अमेरिकी लेखिका कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें भारत के बारे में बहुत ही ग़लत बातें लिखी गई थीं. उस किताब के प्रकाशन के बाद विंस्टन चर्चिल बेहद खुश हुए थे और उन्होंने अपनी खुशी का सार्वजनिक इजहार भी किया था. तब महात्मा गांधी ने उस किताब की समीक्षा लिखकर अपना तगड़ा एतराज जताया था. महात्मा गांधी ने तब लिखा था, अगर मिस मेयो भारत में सिर्फ़ यहां की खुली नालियां और गंदगी देखने के नज़रिये से आई थीं, तो उनकी इस किताब के बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ होगा. पर अगर वह अपने घृणित और बेहद आपत्तिजनक ग़लत निष्कर्षों को अपनी जीत और महान खोज की तरह देखती हैं, तो लेखिका की मंशा जानने के बाद कुछ कहने को शेष नहीं रहता. इस तरह से उन्होंने उस किताब को दो-तीन वाक्यों में खारिज कर दिया था और विंस्टन चर्चिल को भी जवाब दे दिया था. विचारों से लड़ने का यह तरीका ही सबसे अच्छा है. तर्कों को तर्कों से काटा जाए, तर्कों को अपने विचारों से खारिज किया जाए.

आज जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरने की कोशिश करते हैं और आज़ादी के लिए ख़तरा बताते हैं, उन्हें एक और संदर्भ याद रखना चाहिए. संविधान में पहले संशोधन को लेकर बहुत ज़ोरदार बहस हो रही थी. मसला कुछ मौलिक अधिकारों को लेकर संशोधन का था. कई मसलों के अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान है, उस पर कुछ अंकुश लगाए जाने की बात हो रही थी. जवाहर लाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी एवं अंबेडकर समेत कई नेता इस पक्ष में थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पूर्ण नहीं होनी चाहिए. बहस के दौरान जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि आज़ाद प्रेस युवाओं के दिमाग में ज़हर भर रहा है. तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले ऐसे शख्स थे, जिन्होंने यह लड़ाई लड़ी थी और कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी भी तरह का अंकुश जायज नहीं होगा. कालांतर में यह तथ्य बेहद चालाकी से दबा दिया गया. दरअसल, इसके पीछे की पृष्ठभूमि यह थी कि 1950 में क्रास रोड नामक पत्रिका में नेहरू की नीतियों की जमकर आलोचना हुई थी और नेहरू उससे खफा होकर प्रेस पर अंकुश लगाना चाहते थे. तत्कालीन मद्रास सरकार ने क्रास रोड पर पाबंदी लगाई थी. आज़ाद भारत में यह पहली पाबंदी थी. क्रास रोड उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोमेश थापर का केस अब भी कई मामलों में नजीर बनता है. अब वक्त आ गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी बहस हो, जिसमें तथ्यों को समग्रता में रखकर देखा जाए और देश किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे, तभी विचारों की लड़ाई में खून खराबा नहीं होगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

साहित्यकार

इंदिरा रायसम गोस्वामी

इंदिरा गोस्वामी असमिया साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर थीं. ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती गोस्वामी ने असम के चरमपंथी संगठन उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) और भारत सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की राजनीतिक पहल करने में अहम भूमिका निभाई. गुवाहाटी विश्वविद्यालय से असमिया में एमए करने के बाद माधव कांदले एवं गोस्वामी तुलसीदास की रामायण का तुलनात्मक अध्ययन पर पीएचडी हासिल की. गोस्वामी को उनके मौलिक लेखन के लिए जाना जाता है. उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के ख़िलाफ़ काफी लिखा और भारत

जन्म: 14 नवंबर 1943, गुवाहाटी, असम, भारत.
निधन: 29 नवंबर 2011.
वर्ष 2000 में ज्ञानपीठ से सम्मानित

में महिला सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया. वर्ष 1983 में उनके उपन्यास मामारे धारा तारवल के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला. 1988 में उनकी आत्मकथा अधलिखा दस्तावेज़ प्रकाशित हुई. वह दिल्ली विश्वविद्यालय में असमिया भाषा विभाग की विभागाध्यक्ष भी रहीं. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मानद प्रोफेसर का दर्जा प्रदान किया. उन्हें डच सरकार का प्रिंसिपल प्रिंस क्लाउस लाउरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वर्ष 2000 में उन्हें साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला. रामायण साहित्य में विशेषज्ञता के लिए 1999 में इंदिरा गोस्वामी को मियामी के फ्लोरिडा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया. ■

स्मृति शेष

आप हमेशा याद आएंगे वीरेन दा

महेंद्र अवधेश

भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद कानपुर में स्वतंत्र भारत हिंदी दैनिक की नौकरी चल रही थी और साथ ही यत्र-तत्र स्वतंत्र लेखन भी. अमर उजाला के लिए लिखने की बेहद चाह थी, जिसकी राह प्रशस्त की थी वीरेन दा यानी वीरेन डंगवाल ने. उस समय वह अमर उजाला कानपुर के स्थानीय संपादक थे. शुरुआत इस तरह हुई कि मैं एक दिन अमर उजाला के कालपी रोड स्थित कार्यालय में जा पहुंचा. नीचे रिसेप्शन पर नवीन जी की ड्यूटी हुआ करती थी. मैंने नवीन जी से कहा कि मेरा नाम महेंद्र है, संपादक जी से मिलना है. जितने उत्साह के साथ मैंने अपना नाम बताया, उतनी ही तत्परता के साथ नवीन जी ने संपादक जी को इंटरकॉम पर यह सूचना दे दी. उसके बाद मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा गया. रिसेप्शन रूम में सोफे थे, कुर्सियां थीं, अख़बार-पत्रिकाएं थीं, चाय-पानी की भी व्यवस्था थी. मुझ जैसे नए-नए पत्रकार के लिए यह एक अलग अनुभव था.

खैर, पंद्रह मिनट के बाद नवीन जी ने मुझसे कहा, संपादक जी आपको याद कर रहे हैं. सेकेंड फ्लोर पर चले जाइए. मैं पहली बार अमर उजाला गया था. सो, मेरा संकोच देखकर नवीन जी ने एक चपरासी को मेरे साथ भेज दिया. संपादक जी के केबिन के पास पहुंच कर चपरासी बोला, अंदर चले जाइए. मैंने केबिन का दरवाजा धीरे से अंदर की ओर करते हुए सिर झुकाकर अभिवादन किया. जवाब में एक मधुर आवाज़ कानों में गूंजी, आओ-आओ महेंद्र, बैठो. तब तक चपरासी पानी के दो गिलास लेकर आ चुका था. एक गिलास उसने पहले संपादक जी को थमाया और बाद में दूसरा मुझे. डंगवाल सर ने उसे चाय लाने को कहकर विदा किया और मुझसे बोले, बताओ क्या और कैसा चल रहा है? मैं हतप्रभ था. इतनी आत्मीयता! वह भी एक नितांत अपरिचित युवक के साथ! मैं कुछ बोलता, उससे पहले वह खुद बोले, लिखने-पढ़ने का शौक है? मैंने सिर हिलाया और फिर हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैं स्वतंत्र भारत में हूं, उप संपादक के पद पर. लिख तो 1992-93 से रहा हूं. अमर उजाला के लिए लिखना चाहता हूं, जुड़ना चाहता हूं.

तब तक चाय आ चुकी थी. चपरासी ने हम दोनों के आगे चाय के प्याले रखे और फिर वह चला गया. डंगवाल सर बोले, महेंद्र, चाय पियो. हाथ में चाय का प्याला था और मन में उथल-पुथल कि क्या जवाब मिलेगा डंगवाल सर की ओर से. क्या सोच रहे हो महेंद्र? तब तक डंगवाल सर ने खुद सवाल उछाल दिया और फिर बोले, लिखो विविध पेज के लिए. मेहनत से लिखना. छपेगा. मन में एक संतोष का भाव जगा कि चलो मुलाकात सार्थक हो गई. उसके बाद अमर उजाला कानपुर के विविध पेज के लिए लिखना शुरू हो गया. विविध पेज नियमित था, जिसमें मुझ जैसे नए लोगों के आलेखों-फीचरों, वरिष्ठों के स्तंभ और लंबी प्रतिक्रियाओं का प्रकाशन होता था. डंगवाल सर ने मेरे कई आलेख-फीचर विविध पेज पर छापे और मानदेय भी भिजवाया. बीच-बीच में उनसे मुलाकात भी हो जाती थी. दरअसल, डंगवाल सर के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह मिलते सबसे थे, चाहे छोटा हो बड़ा. हां, कभी-कभी इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन वह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रिसेप्शन रूम में मौजूद सुविधाओं और नवीन जी के सद् व्यवहार के चलते वहां कोई बोर नहीं होता था.

अमर उजाला कानपुर का वह विविध पेज हम जैसे नए लोगों के लिए लेखन का एक बड़ा सहारा था. एक बार उसमें मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र शर्मा की पहली कविता छपी, तो उनकी खुशी का पारावार न रहा. मैंने ही उन्हें वीरेन सर का हवाला देकर अपनी कविता भेजने को कहा था, पूरे भरोसे के साथ. वीरेन सर का कनिष्ठों-नवांकुरों के प्रति स्नेह उस भरोसे का आधार था. और, अंतत: मेरा भरोसा जीता भी. पिछले काफी समय से बीमार चल रहे वीरेन सर के बारे में सोशल साइट्स पर साहित्यिक मित्रों के माध्यम से अक्सर ख़बरें मिल जाती थीं. इधर कुछ दिनों से व्यक्तिगत व्यस्तता और उलझनों के चलते उनकी कोई ख़बर मुझ तक नहीं पहुंच सकी. खैर, विधि के विधान के आगे किसकी चली है? जो आया है, उसका इस नश्वर संसार से जाना तय है. वीरेन सर हम जैसों के लिए प्रेरक थे, मार्गदर्शक थे और सबसे बड़ी बात यह कि वह इससे कहीं ज़्यादा अभिभावक थे. सबके लिए सुलभ थे. विशाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी वीरेन सर हमेशा याद आएंगे. हिंदी साहित्य के साथ-साथ हिंदी पत्रकारिता जगत भी उन्हें कभी भुला न सकेगा. ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

भोजपुरी कविता

कौनों ठगवा...

कौनों ठगवा वोटवा लूटे ना,
कौनों ठगवा वोटवा लूटे ना.

कारखाना घराना से पैइसा उगाहे,
चंदा के ना उ स्रोत बतावे,
धोखा से कोई जुटे ना.
कौनों ठगवा...

जात-धरम के उ भेद बढ़ावे,
भारत के भारत से लड़ावे,
प्रेमवां के डोर भाई टूटे ना.
कौनों ठगवा...

लॉलीपॉप लालच उ देखावे,
पैइसा आउर दारू बटवावे,
ईमान-धरम भाई छूटे ना.
कौनों ठगवा वोटवा लूटे ना.

-ग़ुलाम कुंदनम

इस आधुनिक युग में भी परेव के पीतल के बर्तनों की चमक कम नहीं हुई है. फूल, पीतल, जर्मन सिलवर के सुनहरे बर्तन बाजार की शोभा बढ़ाते हैं. यहां की फूल की थाली, लोटा, कटोरा एवं ग्लास इत्यादि की मांग बहुत है. स्थानीय बाजार के अलावा भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और दूसरे राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद व मिर्जापुर में भी इनकी मांग है.

कला-संस्कृति

दिल्ली में दिखी रंगीलो राजस्थान की झलक

आदित्य नारायण पाण्डेय

रंगीलो राजस्थान के विभिन्न रंग एक ही जगह पर दिख जाएं तो फिर क्या कहना. राजस्थान की ऐसी ही कुछ रंग-बिरंगी तस्वीर पिछले दिनों त्रिवेणी कला केंद्र में देखने को मिली. नई दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला केंद्र में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कलाप्रेमियों और शहरवासी आए. जहां प्रदेश की संस्कृति की सुगंध से मदन मीणा की पेंटिंग्स ने कलाप्रेमियों को सराबोर कर दिया. कोटा-बूंदी अपनी पांरपरिक स्टाइल की पेंटिंग्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पर आजकल जिस तरह की पांरपरिक पेंटिंग्स बन रही है. उनमें कुछ नयापन नहीं है. अभी भी कई कलाकार पुरानी शैली में ही पेंटिंग्स बना रहे हैं. मदन मीणा ने पेंटिंग्स में एक नया प्रयोग करते हुए कोटा-बूंदी के संस्कृति, परपंरा और पर्यावरण की खूबसूरती को दर्शाया है. मदन मीणा ने पेंटिंग्स में रणथम्भौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जीवों को दिखाया है. पेंटिग में कई तरह की पक्षियां है, जो विभिन्न मौसम में दिखाई देती है. मदन मीणा ने उन्हें भी अपने पेंटिंग्स में खूबसूरती से चित्रित किया है. इस पेंटिंग्स को बारहमासा नाम दिया है. गुलाब माचीस पेंटिंग्स, जो किसी समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी. उससे प्रेरित होकर मदन मीणा ने कांटा लगा पेंटिंग बनाई हैं. इस पेंटिंग में गुलाब के फुलों से घीरी महिला है. जिसके पांव में कांटा लगा हुआ है. इस पेंटिंग को वहां मौजूद कलाप्रेमियों ने काफी सराहा. तीसरी पेंटिंग जो काफी आर्कषित कर रही थी, उसमें एक विष कन्या को दिखाया गया है. कन्या के हाथ में एक सांप है, जो उसके जीभ पर डस रहा है. इस पेंटिंग को विष कन्या का नाम दिया है. यह सारी पेंटिंग्स मदन मीणा के रिर्सच और यात्रा पर आधारित हैं. मदन मीणा चित्रकार और शोधकर्ता हैं. राजस्थान के विभिन्न आंचलिक समुदायों के साथ उन्होंने काम किया है. मीणा जाति की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले मांडना चित्रकारी पर उन्होंने गहन शोध किया है. इस विषय पर डॉक्टरेट की थीसीस लिखने के साथ ही उन्होंने इस विषय पर किताबें भी प्रकाशित की हैं- तेजा जी की गाथा, जॉय ऑफ क्रिएटिविटी इत्यादि. एक चित्रकार के रूप में उन्होंने देश भर में अपना काम प्रदर्शित किया है. ■

मीणा जाति की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले मांडना चित्रकारी पर उन्होंने गहन शोध किया है. इस विषय पर डॉक्टरेट की थीसीस लिखने के साथ ही उन्होंने इस विषय पर किताबें भी प्रकाशित की हैं

feedback@chauthiduniya.com

फैशन

पेरिस फैशन वीक के दौरान बौनी महिलाओं ने कैटवॉक किया. हालांकि यह कैटवॉक पेरिस फैशन वीक का हिस्सा नहीं होता, लेकिन यह मॉडल इंडस्ट्री के खुद की उत्कृष्टता व पूर्वाग्रह के खिलाफ आयोजित होता है.

खाना पीना

प्रसिद्ध मिठाई मैसूर पाक

मैसूर पाक कर्नाटक में बनाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध मिठाई है. यह सबसे पहले मैसूर पैलेस में बनाई गई थी, जो वहां के राजसी लोगों को परोसी जाती थी. तब से यह एक राजसी मिठाई के रूप में मैसूर पाक के नाम से मशहूर हो गई. इसे बनाने के लिए घी, मक्खन और बेसन का प्रयोग किया जाता है. यह खाने में इतनी मुलायम होती है कि मुंह में रखते ही घुल जाती है. आप चाहें, तो इसे अपने घर पर ही बना सकते हैं, इसको बनाना बहुत ही असान है.

सामग्री- 1 कप बेसन, 1 कप चीनी, 1/2 कप घी, 1 कप पानी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर.

बनाने की विधि-

एक कड़ाही में शक्कर और 1/2 कटोरी पानी डालकर गाढ़ी चाशनी बनाएं. दूसरी ओर घी में बेसन डालकर भूनें. अब चाशनी को धीरे-धीरे सिंके हुए बेसन में डालें व बराबर हिलाते रहे. दूसरे हाथ से गरम घी 1-1 चम्मच करके बेसन पर डालती रहें. बेसन जब भूरा होने लगे, तो उसमें इलायची भुराभुरा कर घी लगी थाली में फैला दें. यह जल्दी ही जम जाता है, अतः जमने की प्रक्रिया शुरू होते ही चाकू की सहायता से मनचाहे आकार में काट लें. तैयार है लजीज रसभरा मैसूर पाक. यह बहुत सारे घी, बेसन, मेवा व शक्कर से निर्मित कर्नाटक का मीठा व्यंजन है. ■

सैमसंग का गैलेक्सी जे1एस स्मार्टफोन लॉन्च

सैमसंग ने मीडिल रेंज में गैलेक्सी जे1 एस स्मार्टफोन को बाजार में उतार दिया है. फिलहाल कंपनी ने इस स्मार्टफोन को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट किया है. जिसकी कीमत भारतीय बाजार में 6300 रुपये तय की गई है. इस स्मार्टफोन में 4.5 इंच का स्क्रीन लगा है, जिसका रेजोल्यूशन 480 गुणा 800 पिक्सल में बेहतरीन कवालिटी देता है. इसके स्क्रीन में सुपर एमोलेड टेकनोलॉजी का प्रयोग किया गया है.

फीचर्स

इस स्मार्टफोन में दो जीएसएम सिम कार्ड का प्रोयोग सकते है. साथ ही इसमें 1.3 गीगाहट्र्ज डुअलकोर प्रोसेसर दिया गया है, जो की 512 एमबी रैम के साथ आता है. इस फोन में 4जीबी की इंटरनल मेमोरी है और इसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. सैमसंग गैलेक्सी जे1 एस में ऑटो फोकस फीचर के साथ 5-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है. कैमरे के साथ फ्लैश उपलब्ध है. वहीं वीडियो कॉलिंग व सेल्फी के लिए 2-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. ■

पीतल नगरी है भोजपुर ज़िले का परेव गांव

भोजपुर जिले की सीमा रेखा बनकर बहती सोन नदी के पूर्वी तट पर एक गांव बसा है परेव. कोईलवर पुल के पूर्वी छोर के पास आबाद बस्ती परेव पीतल के बर्तन उद्योग और हर हाथ को काम देने के लिए विख्यात है. शताब्दी पूर्व से परेव में पीतल के बर्तनों का निर्माण होता आया है. सोन नदी के किनारे की लसदार मिट्टी प्रारंभ में बर्तनों के सांचा निर्माण में मददगार रही. इसी ने कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया. कसेरा जाति के लोगों ने कुटीर उद्योग के रूप में अपनाकर इसे लघु उद्योग तक पहुंचाया. मशीनीकरण से पूर्व हर हाथ को यहां काम हुआ करता था. आज भी अधिकतर लोग इस रोजगार पर आश्रित हैं. आधा दर्जन बेलन मशीन और तीस-चालीस भट्ठियों की स्थापना तक मामला पहुंचा है. स्थानीय लोगों के अलावा कई मिर्जापुर आदि के कारीगर-मजदूर भी यहां काम करते हैं. धनतेरस के मौके पर यहां निर्मित बर्तनों की मांग बढ़ जाती है. इस आधुनिक युग में भी परेव के पीतल के बर्तनों की चमक कम नहीं हुई है. फूल, पीतल, जर्मन सिलवर के सुनहरे बर्तन बाजार की शोभा बढ़ाते हैं. यहां की फूल की थाली, लोटा, कटोरा एवं ग्लास इत्यादि की मांग बहुत है. स्थानीय बाजार के अलावा भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और दूसरे राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद व मिर्जापुर में भी इनकी मांग है. नेपाल तक यहां का निर्मित सामान जाता है. इस उद्योग व्यवसाय से जुड़े कई लोगों का कहना है कि यदि सरकार व प्रशासन का समुचित सहयोग मिले, तो परेव पीतल के बर्तन उद्योग में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और मुरादाबाद को पीछे छोड़ देगा. परेव जैसी छोटी बस्ती में बर्तन उद्योग के कारण चार-पांच दशक पूर्व एक राष्ट्रीयकृत केनरा बैंक स्थापित किया गया है. अब यहां के लोग उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं. रेल से माल लाने व ले जाने के लिए दानापुर मंडल के कोईलवर स्टेशन का सहारा लेना पड़ता है, जो महज एक मील की दूरी पर है. व्यवसायी दशकों से इसके विकास और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की मांग करते रह हैं. लेकिन कुछ वर्षों पहले परेव से पूरब एक मील की दूरी पर एक पाली हाल्ट अस्तित्व में आया. लेकिन इससे भी बर्तन उद्योग का मामला हल नहीं हुआ. ■

विशुद्ध मनोरंजक फिल्म है

होगया दिमाग़ का दही

ओमपुरी

प्रचार की बदौलत फिल्म होगया दिमाग़ का दही की चर्चा हर ज़ुबान पर है, हर किसी को बेसब्री से 16 अक्टूबर का इंतजार है जब फिल्म रिलीज होगी.

सुषमा गुप्ता

हिंदी फिल्मों के बेहतरीन कलाकार ओमपुरी अपनी फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** के प्रमोशन के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, तो यहीं के होकर रह गए. तबीयत खराब होने के बावजूद ओमपुरी यहां दो दिन रुके और जबरदस्त तरीके से फिल्म का प्रचार किया. इस दौरान पूरा शहर उनका दीवाना हो गया. उनसे मिलने, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग जगह-जगह पहुंचे. लोगों से मिलने का उनका तरीका इतना सामान्य था कि वे शहर की मशहूर पान-दुकान बनारसी पान भंडार गए और वहां पान का मज़ा लेते हुए लोगों के साथ फिल्मों और थियेटर के बारे में चर्चा की.

रायपुर में उनके प्रचार की बदौलत फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** की चर्चा हर ज़ुबान पर है, हर किसी को बेसब्री से 16 अक्टूबर को फिल्म के रिलीज होने का इंतजार था. ओमपुरी ने फिल्म को लेकर रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोगों को फिल्म और अपने रोल के बारे में बताया. उन्होंने अपनी पहली ही लाइन से यह साफ कर दिया कि फिल्म विशुद्ध रुप से मनोरंजक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है. इस फिल्म में कोई संदेश नहीं है न ही द्वि-अर्थी संवाद हैं. लेकिन फिल्म दर्शकों को हंसा-हंसाकर और गुदगुदाकर उनकी सेहत जरूर सुधारेगी. ओमपुरी ने बताया कि यह फिल्म हेराफेरी, मालामाल वीकली जैसी उत्कृष्ठ श्रेणी की कॉमेडी फिल्मों की श्रृंखला की अगली फिल्म है. उन्होंने बताया कि यह एक साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म है. उन्होंने बताया कि फिल्म की निर्देशक फ़ौज़िया अर्शी मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं. कॉमेडी का तड़का पूरी फिल्म में देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को पूरे समय गुदगुदाता रहेगा. उन्होंने बताया कि फिल्म के निर्माता संतोष भारतीय हैं जो कि एक पत्रकार और पूर्व सांसद हैं. ओमपुरी ने लोगों को फिल्म की बिगड़ी हुई शायरी सुनाई तो सभी हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. उन्होंने ***होगया दिमाग़ का दही*** में गालिब के शेर के साथ किए अटपटे प्रयोग को सुनाया तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. ***हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, मेले से आकर देखा तो दो बच्चे कम निकले.***

ओमपुरी ने बताया कि यह फिल्म हेराफेरी, मालामाल वीकली जैसी उत्कृष्ठ श्रेणी की कॉमेडी फिल्मों की श्रृंखला की अगली फिल्म है. उन्होंने बताया कि यह एक साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म है. फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. कॉमेडी का तड़का पूरी फिल्म में देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को पूरे समय गुदगुदाता रहेगा.

इस फिल्म में ओमपुरी मिर्ज़ा किशन सिंह जोसेफ की भूमिका में हैं. फिल्म में वह एक ऐसे व्यक्ति का किरदार अदा कर रहे हैं जो चार धर्मों को मानता है. उनका नाम भी चार धर्मों के अनुसार मिर्ज़ा किशन सिंह जोसेफ है. फिल्म के उनके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म में उनकी वेशभूषा भी बेहद अनोखी है. चार दशक लंबे अपने फिल्मी करियर में वह पहली बार किसी गेटअप में नज़र आए हैं. फिल्म के ट्रेलर और गानों को

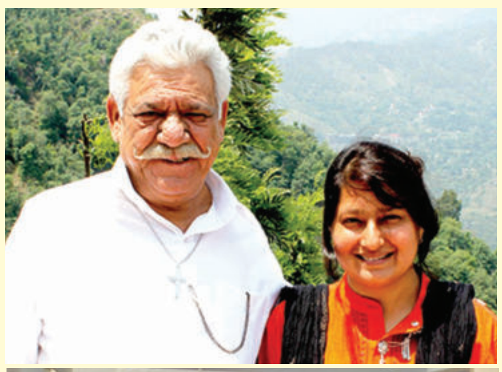

यू-ट्यूब में अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं. ओमपुरी खुद भी फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** को लेकर काफी उत्साहित हैं. वह अपने इस अनोखे किरदार को मज़ेदार बताते हैं. उन्होंने पत्रकारों से बताया कि उन्हें मिर्ज़ा किशन सिंह जोसेफ का किरदार अदा करते हुए काफी मजा आया.

ओमपुरी रायपुर में सिर्फ मीडिया से ही मुख़ातिब नहीं हुए, बल्कि रात को कुछ पत्रकारों और रंग-कर्मियों के साथ शहर के बीचों-बीच स्थित बनारसी पान दुकान पहुंचे. वहां उन्होंने पान का मजा लिया और प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया. पान की दुकान पर अपने बीच प्रसिद्ध अभिनेता को खड़ा देख प्रशंसक फूले नहीं समा रहे थे. कुछ लोग उन्हें निहार रहे थे तो कुछ उनके साथ सेल्फी ले रहे थे. यहां उन्होंने पत्रकारों और रंगकर्मियों से सिनेमा और थिएटर पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने थियेटर की बदहाली पर चिंता जाहिर की. मीडिया से मुखातिब होते हुए ओमपुरी ने अपनी निजी जिन्दगी से लेकर हर विषय पर बात की. फिल्म जगत के बारे में बात करते हुए उन्होंने स्टार पुत्रों के बारे में भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि जैसे गुब्बारे वाला गुब्बारे को दुकान में सजाता है, उसी तरह एक्टर्स ने बॉलीवुड में अपने बच्चों की दुकानें लगा रखी हैं. सभी आजकल दुकान लगा रहे हैं. लेकिन बिना प्रतिभा के कोई एक्टर चलेगा नहीं. इरफान ख़ान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एनएसडी से निकले बच्चों से उन्हें काफी उम्मीदें हैं.

ओमपुरी ने अपने बचपन में चाय बेची है. जब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समानता पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी मुझसे अमीर थे. वह चाय की दुकान के मालिक थे. मैं तो चाय की दुकान में गिलास और कप धोता था. सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वह संघर्ष नहीं था, वह एक दौर था. बहरहाल ओमपुरी दो दिन रायपुर में गुजारकर काफी खुश दिखे और सभी को फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** देखने का सबको न्योता दिया.■

feedback@chauthiduniya.com

बहुआयामी है होगया दिमाग़ का दही का संगीत

एक तरफ जहां कव्वाली आपको रूहानी अहसास देती है तो दूसरी तरफ फिल्म का गीत कभी तो सुन गौर से आपके दिल को छूता है और आपको आपके प्रेमी / प्रेमिका की याद दिलाता है. फ़ौजिया अर्शी ने इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है. गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि आप हसीन वादियों में अपने साथी के साथ हैं. समीक्षकों के अनुसार पिछले एक दशक में ऐसा मैलोडियस गीत नहीं आया है.

फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** एक कॉमेडी ड्रामा है. हिंदी सिनेमा में गिनी-चुनी कॉमेडी फिल्में ही हैं जिन्हें उनके बेहतरीन संगीत और गीतों के लिए याद किया जाता है. ***होगया दिमाग़ का दही*** उसी श्रेणी की शैली के हैं.

सबसे पहले फिल्म की कव्वाली ***मौला मेरे मौला*** को लें. तो यह फिल्म का सबसे बेहतरीन गीत है. यह गीत इस फिल्म की आत्मा की तरह है, जिसे कैलाश खेर ने फ़ौजिया अर्शी के साथ रूहानी अंदाज में गाया है. हिंदी संगीत इतिहास में यह पहला मौक़ा है जब किसी रूहानी कव्वाली में किसी गायिका ने अपनी आवाज दी है. अमूमन ऐसा नहीं होता है. इसके अलावा भी और भी कारण हैं जिसके लिए इस कव्वाली को लंबे समय तक याद किया जाएगा. इसके बोल बेहतरीन हैं, जिसमें अल्लामा इक़बाल, अमीर खुसरो और कृष्ण बिहारी नूर जैसे नामी शायरों की नज़्मों के हिस्से शामिल हैं. कैलाश खेर की आवाज और गीत के बोल का ऐसा संगम होता है कि आप किसी रुहानी माहौल में पहुंच जाते हैं. फ़ौज़िया अर्शी फिल्म की निर्देशक होने के साथ-साथ फिल्म की संगीतकार भी हैं इस कव्वाली को उनकी गायकी चार चांद लगा देती है.

फिल्म है. कुछ लोग गीतों को एक ही दायरे में देखते हैं जबकि वो फिल्म का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं. यह किसी भी फिल्म के गीतों की फिल्म को देखे बगैर समीक्षा करने का त्रुटिपूर्ण तरीका है. यदि फिल्म पूर्ण है तो गीतों को उसके भाग के रूप में लिया जाना चाहिये, न कि उनकी एक अलग वातावरण में समीक्षा की जानी चाहिए. यदि फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** की निर्देशक की बात को सही मानें तो इस फिल्म के गीत फिल्म की कहानी के अनुरूप हैं और फिल्म का अभिन्न हिस्सा हैं. इस फिल्म में चार गीत हैं और सभी गीत अपने आप में अलग

मीका सिंह को जिस ऊर्जा और अंदाज के लिए जाना जाता है, वह फिल्म के *गीत बाप होना पाप* में पूरी तरह दिखाई देता है. देश की युवा पीढ़ी जिस तरह के गाने और संगीत को पसंद करती है, यह गीत उसी श्रेणी का है. गायकी के साथ-साथ यह गीत अपने पिक्चराईजेशन के लिए बहुत चर्चा में है.

एक तरफ जहां कव्वाली आपको रूहानी अहसास देती है तो दूसरी तरफ फिल्म का गीत ***कभी तो सुन गौर से*** आपके दिल को छूता है और आपको आपके प्रेमी/प्रेमिका की याद दिलाता है. फ़ौजिया अर्शी ने इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है. गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि आप हसीन वादियों में अपने साथी के साथ हैं. समीक्षकों के अनुसार पिछले एक दशक में ऐसा मैलोडियस गीत नहीं आया है. ऐसे भी हिंदी सिनेमा से मेलोडियस गीत धीरे-धीरे गायब ही होते जा रहे हैं, ऐसे में यह गीत नये अंदाज में मैलोडी के दौर में वापसी का इशारा करता है.

मीका सिंह को जिस ऊर्जा और अंदाज के लिए जाना जाता है वह फिल्म के गीत ***बाप होना पाप में पूरी तरह*** दिखाई देता है. देश की युवा पीढ़ी जिस तरह के गाने और संगीत को पसंद करती है यह गीत उसी श्रेणी का है. गायकी के साथ-साथ यह गीत अपने पिक्चराईजेशन के लिए बहुत चर्चा में है. फिल्म में इस गीत को गायक मीका सिंह के कैरिकेचर के साथ फिल्माया गया है. यह पहला मौका है जब किसी भारतीय गायक का कैरिकेचर फिल्म के गीत में नज़र आएगा. फिल्म की निर्देशक होने का फायदा बतौर संगीतकार फ़ौज़िया अर्शी को मिला है, वह इस बात से भली भांति वाकिफ थीं कि कैसा संगीत फिल्म की कहानी को सूट करता है, इसलिये उन्होंने कई विधा के गीतों को फिल्म में जगह दी है. इन गीतों से फौजिया अर्शी की बतौर संगीतकार परिपक्वता का आकलन भी हुआ है. इसलिए उन्होंने फिल्म के टाइटल ट्रैक ***दिमाग का दही को*** जगह दी है. इस गीत में कुनाल गांजावाला और ऋतु पाठक ने समा बांध दिया है.■

होगया दिमाग़ का दही के हिट डायलॉग्स

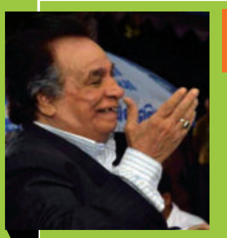

कादर खान

मतलब तू मेरे कपड़े उतार के ..मुम्बई के चोर बज़ार में... उनकी दुकान लगाएगा...

रज्जाक खान

जब तक मेरी चाय चलेगी, तब तक तेरा नाच चलेगा...

ओम पुरी

तू है कौन कमीने... जब देखो फ़ोन करता रहता है ...कब ले जाएंगे ...कब ले जाएंगे...

- भूसे के ढेर पर बैठकर बीड़ी मत पी, ख़ाक हो जाएगा...
- अरे माकड़े तेरी मां का, तेरे बाप से, तलाक कराएंगे...

संजय मिश्रा

मेरा नाम आशिक अली है...एडवोकेट डाइवोर्स स्पेशिलिस्ट एल एल बी फ्रॉम माशलआर्ट

राजपाल यादव

- भईया मेरा नाम हैं मसाला ... लहसुन, प्याज, धनिया मिर्ची, गरम मसाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची...
- साले, ढाई सौ साल की सजा करवाउंगा

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

बेहतरीन आवाज़...
बेहतरीन गीत...

लोग ग़ौर से सुन रहे हैं गायिका फ़ौज़िया अर्शी की आवाज़

फ़ौज़िया अर्शी ने जब इस गीत को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर किया तो उनकी बॉल पर गाने की तारीफ में कमेंट्स की बाढ़ आ गई. गाने की तारीफ में मोहम्मद फराज़

हुसैन लिखते हैं, बेहतरीन आवाज़...बेहतरीन गीत. वहीं आगा अब्दुल अलीम खान लिखते हैं, मैलोडियस वॉइस...कीप इट अप. समीक्षकों की नज़र में बहुत दिनों बाद इस तरह का कोई मैलोडियस गीत आया है. इसी वजह से लोग इस गीत की सराहना कर रहे हैं. रितेश शर्मा कहते हैं कि यह बेहतरीन गीतों की श्रेणी में लंबे समय तक याद किया जाने वाला गीत साबित होगा. आपकी आवाज़ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कॉमेडी फिल्म होगया दिमाग़ का दही से फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक पदार्पण करने वाली फ़ौज़िया अर्शी कई विधाओं में माहिर हैं. उन्होंने फिल्म होगया दिमाग़ का दही में तिहरी भूमिका अदा की हैं. फिल्म की निर्देशक होने के साथ-साथ वह संगीतकार और गायिका भी हैं. उन्होंने अपनी फिल्म में दो गीतों को अपनी आवाज भी दी है. ***मौला मेरे मौला*** कव्वाली में उन्होंने कैलाश खेर के साथ सुर मिलाये हैं, वहीं फिल्म का एक अन्य गीत ***कभी तो सुन गौर से*** में अपनी आवाज दी है. उनका गाया गीत कभी तो सुन गौर से फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सुर्खियां बटोर चुका है, श्रोता उनके इस गीत की खुलेदिल से तारीफ कर रहे हैं.

फौजिया अर्शी ने जब इस गीत को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर किया तो उनकी बॉल पर गाने की तारीफ में आ रहे कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई. गाने की तारीफ में मोहम्मद फराज़ हुसैन लिखते हैं बेहतरीन आवाज़...बेहतरीन गीत. वहीं आगा अब्दुल अलीम खान लिखते हैं मैलोडियस वॉइस...कीप इट अप. समीक्षकों की नज़र बहुत दिनों बाद इस तरह का कोई मैलोडियस गीत आया है. इसी वजह से लोग इस गीत की सराहना कर रहे हैं. रितेश शर्मा कहते हैं कि यह बेहतरीन गीतों की श्रेणी में लंबे समय तक याद किया जाने वाला गीत साबित होगा. आपकी आवाज़ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा. फिल्म मेकर के बाद आप एक संगीतकार के रूप में बेहद सफल हो सकती हैं. इस मधुर गीत के लिए आपको बधाई. फौजिया अर्शी मूल रूप से भोपाल की रहने वाली हैं. भोपाल के रहने वाले रफात अली का कहना है कि यह गाना उन्हें बहुत पंसद आया. यह बेहतरीन गीत है. बेहतरीन नज्म, एक भोपाली ही इतने बेहतरीन तरीके से गा सकता है. आपकी फिल्म के लिए शुभकामनायें, मैं सपरिवार यह फिल्म देखने जाउंगा. वहीं हेमंत कुमार पाठक लिखते हैं सरगम का एक और उभरता सितारा. बिजेंद्र दुबे गीत की तारीफ में कहते हैं सुभान अल्लाह... बहुत मस्त, जबरजस्त. वहीं सलीम रज़ा खान कहते हैं गौर से सुना, अर्शी जी वेरी नाइस. स्वीट वॉइस. इस गीत की तारीफ में अफशीन अहमद ने कहा कि माशा अल्लाह फौज़िया आपकी आवाज बहुत अच्छी है.

बतौर निर्देशक फौजिया का इंम्तिहान में पास होना अभी बाकी है लेकिन बतौर संगीतकार और गायिका वह प्रशंसकों की नज़र में पास हो गई हैं.■

होगया दिमाग़ का दही को लेकर उत्साहित हैं ओमपुरी

फिल्म होगया दिमाग़ का दही के प्रमोशन के दौरान अभिनेता ओमपुरी एक अलग ही अंदाज में नज़र आये. वह अपनी नई फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं. जब वह 16 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म के प्रमोशन के लिए देश के विभिन्न शहरों में गए. उस दौरान कई मज़ेदार वाकये घटित हुए. जब वह प्रमोशन के लिए राजधानी दिल्ली में थे. तब उनकी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रूकी तो, एक प्रशंसक ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा, उस दौरान उन्होंने उसे बताया कि 16 अक्टूबर को उनकी नई फिल्म रिलीज हो रही है, उसे जरूर देखें. ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ की

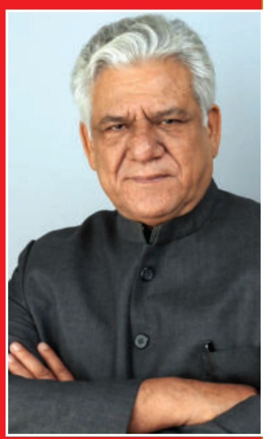

राजधानी रायपुर में भी हुई. उन्होंने वहां कार पर चलते-चलते प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाते हुए उनसे अपनी आने वाली नई कॉमेडी फिल्म होगया दिमाग़ का दही देखने का अनुरोध किया. उन्होंने उनसे कहा कि इस फिल्म के डायलॉग ऐसे हैं कि आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जायेंगे. ऐसा ही उन्होंने भोपाल में भी किया. उन्होंने वहां पत्रकारों से कहा कि वे उनकी कॉमिक टाइमिंग पर संदेह न करें ,यदि उन्हें कोई संदेह है तो वे होगया दिमाग़ का दही जरूर देखें. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म की निर्देशक फ़ौज़िया अर्शी की भी खुलकर तारीफ की.■

मौला मेरे मौला गीत ने बनारस में फैले उन्माद को शांत कर दिया

बनारस के आम-खास सभी तरह के लोगों की मौला मेरे मौला गीत के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आईं. लोगों ने खुले दिल से इस गीत की तारीफ करते हुए कहा कि जब तक देश में इस तरह के गीत बनते रहेंगे, देश के लोगों के बीच भाईचारा बना रहेगा. क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो लोगों को उनके जमीर की आवाज़ सुनने के लिए मजबूर कर देता है.

कहते हैं संगीत में बहुत असर होता है, यह पत्थर को मोम कर सकता है, बुझे हुए दिये को रौशन कर सकता है, बिना बादल के बारिश करवा सकता है. सूफियों और संतो ने संगीत को खुदा या परमात्मा से मिलन का जरिया माना. संगीत का कमाल यह है कि भले ही इसकी तकनीकी बारीरियां श्रोता को समझ में न आयें, लेकिन इसका असर अपने दिलो-दिमाग़ पर जरूर महसूस करता है. संगीत के इसी असर की एक मिसाल हाल ही में देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले बनारस में देखने को मिली. बनारस में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से और लोगों के बीच के भाईचारे को बनाये रखने के लिए पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा. ऐसे में लोगों के पास खबरे जानने के लिए एफम और टीवी चैनल ही अहम जरिया थे. इन्हीं की मदद से शहर के माहौल को शांत किया जा सकता था और लोगों को शहर के हालात के बारे में सही जानकारी दी जा सकती थी. ऐसे में बनारस में एफएम मन्त्रा ने अपने तय कार्यक्रमों में बदलाव करके सूफी संगीत और शांति का संदेश देने वाले गीतों का कार्यक्रम चलाया. इस दौरान 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म होगया दिमाग़ का दही के गीत मौला मेरे मौला को कई बार प्रसारित किया गया.

रेडियो मन्त्रा के नेशनल प्रोग्रामिंग हेड अली ज़हीर ने बताया के एक रेडियो स्टेशन होने के नाते, हमारा दायित्व लोगों का मनोरंजन के साथ-साथ उन्हें जोड़ कर रखने और सामाजिक चेतना जगाने का भी है. जब कभी किसी शहर में इस तरह के हादसे होते हैं, रेडियो के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं. बनारस में कर्फ्यू वाले दिन पूरी रात रेडियो मन्त्रा के आर जे लाइव थे, ताकि लोगों को पल-पल की जानकारियां और अपडेट्स दिये जा सकें! संगीत की ऐसे समय में काफी अहम योगदान होता है, इसलिए हमने कर्फ्यू वाली रात रेडियो मन्त्रा का म्यूज़िक मेलो कार्यक्रम डाऊन कर दिया, और सूफ़ी और सॉफ्ट गाने चलाने लगे.

हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म होगया दिमाग़ का दही की गीत मौला मेरे मौला जिसे कैलाश खेर और फ़ौज़िया अर्शी ने गाया है, हमारी प्लेलिस्ट में था. इस गाने ने लोगों को बांधकर रखने में बड़ी भूमिका निभाई, मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी बॉलीवुड में ऐसे अच्छे गाने बनते रहेंगे...जो लोगों को एक अच्छे संदेश के साथ, उन्हें को जोड़े रखने और उनके बीच भाईचारा बनाए रखने में सहायता करंगे! चौथी दुनिया से बात करते हुए रेडियो मंत्रा के अधिकारी ने बताया कि उनके पास बनारस के आम-खास सभी तरह के लोगों की मौला मेरे मौला गीत के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आईं. लोगों ने खुलेदिल से इस गीत की तारीफ करते हुए कहा कि जब तक देश में इस तरह के गीत बनते रहेंगे. देश के लोगों के बीच भाईचारा बना रहेगा. क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो लोगों को उनके जमीर की आवाज सुनने के लिए मजबूर कर देता है. ■

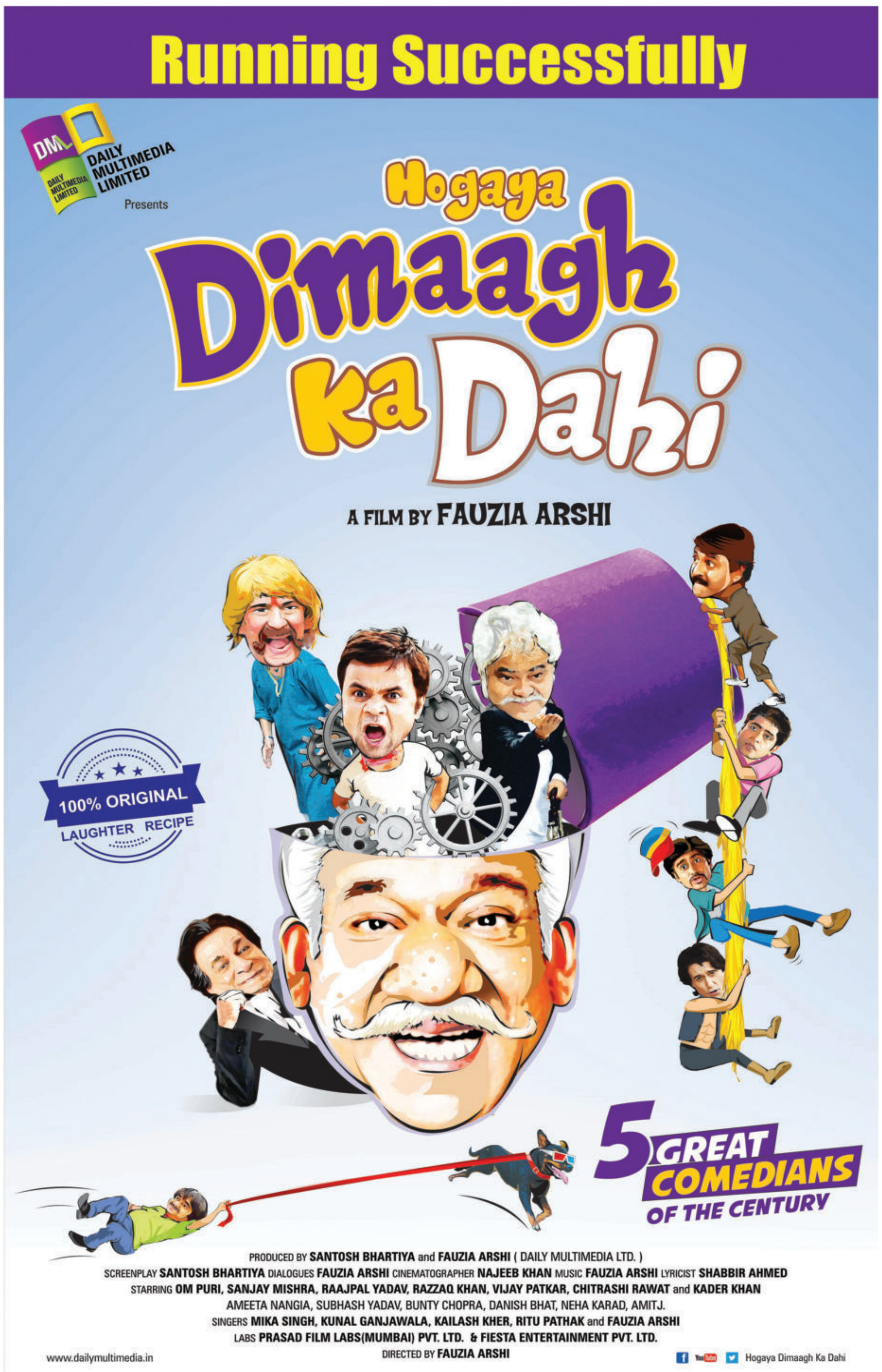

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
बिहार-झारखंड
19 अक्टूबर-25 अक्टूबर, 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHI/2009/30467

ज्योतिषीय विश्लेषण

भाजपा व राजद की बल्ले-बल्ले

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ग्रहदशा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि राहू की महादशा का आगमन और शनि की प्रतिकूल स्थिति से उनके राजनितिक भविष्य में ग्रहण लग रहा है. दूसरी ओर भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 दिन 11 बजकर 40 मिनट में हुई है इस लिहाज से वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में, शनि की अंतरदशा है. सूर्य कर्म स्थान में, बृहस्पति के ग्रह में स्थित है. शनि सिंह राशि में परस्पर शत्रु भाव में है. लेकिन तीसरे स्थान में शनि होने के कारण शत्रुहंता योग बनाकर बैठा है, जिससे तीसरे स्थान का शनि अच्छी मति एवं विक्रमवान बनाता है.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है. चौक-चौराहे से लेकर गांवों की चौपालों में हार-जीत का गणित समझने में लोग लगे हैं. हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है और जनता को यह संदेश दे रहा है जैसे कि हमारी सरकार तो अब बन ही गई है. लेकिन राजनीतिक पंडितों और कार्यकर्ताओं के आंकलन से कुछ अलग ज्योतिष ज्ञान रखने वाले कुछ जानकारों से चौथी दुनिया ने यह समझने की कोशिश की कि पार्टी और नेताओं की कुंडली को यदि आधार बनाया जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में कौन, किससे कितना आगे है.

पंडित प्रेमसागर पांडेय कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ग्रहदशा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि राहू की महादशा का आगमन और शनि की प्रतिकूल स्थिति से उनके राजनितिक भविष्य में ग्रहण लग रहा है. दूसरी ओर भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 दिन 11 बजकर 40 मिनट में हुआ है इस लिहाज से वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में, शनि की अंतरदशा है. सूर्य कर्म स्थान में, बृहस्पति के ग्रह में स्थित है. शनि सिंह राशि में परस्पर शत्रु भाव में है. लेकिन तीसरे स्थान में शनि होने केकारण शत्रुहंता योग बनाकर बैठा है, जिससे तीसरे स्थान का शनि अच्छी मति एवं विक्रमवान बनाता है. पर शनि सूर्य ग्रह में है जिसके कारण भाजपा, विरोधी पार्टी को विशेष नुकसान करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है. पंडित प्रेमसागर पांडेय की गणना बतलाती है कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को अपने प्रत्याशी के अनुसार भले ही मजबूती दिखाई दे, लेकिन भाजपा की सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा के कारण सक्रिय समय बनता है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे. सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा 13 मार्च 2015 से 25 फरवरी 2016 तक है. यह अवधि भाजपा के लिए फलदायक है और ज्योतिष गणना के अनुसार पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती है.

पंडित प्रेमसागर पांडेय राजद के ज्योतिषीय विश्लेषण में बताते हैं कि राजद की स्थापना 5 जुलाई, 1997 मध्य दिवस में हुई है. जिसके अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है. शनि सप्तम स्थान में है, एवं शुक्र आय स्थान में चन्द्र ग्रह में सम शत्रु भाव से स्थित है. प्रथम रूप से शनि सप्तम स्थान में है और शुक्र आय स्थान सम-शत्रु भाव में बैठा है. किन्तु शनि एवं शुक्र के संयोग के कारण बहु-प्रतीक्षित अभिलाषाओं की सम्पूर्ति होगी. पार्टी की क्रियाशीलता और वृद्धि चार्तुय ऐसा क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करेगा जो सफलता से नजदीकी दिलाने में सक्षम सिद्ध होगा, यानि पूर्व की तुलना में अच्छी सफलता राजद को प्राप्त हो सकती है. गौरतलब है कि 2010 के चुनाव में राजद को केवल 22 सीटें ही मिली थीं.

जदयू के ज्योतिषीय विश्लेषण में प्रेमसागर जी का मानना है कि जदयू की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को दिन में हई थी. वर्तमान समय में शुक्र की महादशा में केतु की अंतरदशा है. शुक्र आय स्थान में और केतु कर्म स्थान में है. यह गणना जदयू के लिहाज से ठीक है लेकिन राजद व कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की स्थिति में इसका पूरा फायदा जदयू को नहीं मिल रहा है. इसलिए ज्योतिष गणना के ठीक होने के बावजूद जदयू को साझा कार्य में नुक़सान उठाना पड़ सकता है. वहीं नीतीश कुमार का राहू गोचर के अनुसार लग्न में है, जो व्यर्थ के विचार और कार्य आदि कराने में सक्षम है. ऐसे संयोग में सफलता के लिए अथक प्रयास करने होंगे और यह ध्यान रखना होगा कि प्रयास ऐसा हो कि व्यर्थ न जाए.

पंडित सुबोध मिश्रा के अनुसार नीतीश कुमार अभी राहू की दशा में चल रहे हैं. राहू की दशा आरंभ होने के एक माह के बाद भाजपा से वर्षों पुराना नाता उन्होंने तोड़ लिया. इसी के कुप्रभाव के कारण लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और जीतनराम मांझी को गद्दी सौंपी. राहू के प्रभाव ने लालू प्रसाद से महा-गठबंधन में हाथ मिलाने को विवश कर दिया. जिस बिहार की जनता ने लालू प्रसाद के खिलाफ में नीतीश पर भरोसा किया था उन आम जनों की भावना को आहत करते हुए फिर उसी प्रतिद्वंदी के साथ हो गए. वहीं दूसरी ओर भाजपा वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा में है. यह स्थिति पार्टी के लिए अच्छे परिणाम देने वाली हो सकती है. भाजपा अपने 2010 के प्रदर्शन में सुधार कर सकती है.■

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहू ग्रह के प्रारंभिक दौर से गुजर रहे हैं. इस अवधि में मानहानि, धनहानि की प्रबल संभावना बनती है. यदि उनकी प्राप्त जन्मतिथि सत्य है तो वर्तमान विधानसभा चुनाव में वह बिहार के नायक नहीं बनेंगे. इस तरह भाजपा के सुशील मोदी की प्राप्त जन्मतिथि से स्पष्ट होता है कि ये भी राहू में मंगल के अंतर से गुजर रहे हैं, जो कि 2017 तक चलेगा. इनकी राहू की दशा समाप्ति की ओर है इसलिए उम्मीद बरकरार है.

feedback@chauthiduniya.com

पंडित प्रेमसागर पांडेय के अनुसार नीतीश कुमार की जन्म तिथि 01 मार्च 1951 समय दिन 1 बजकर 20 मिनट पर बख्तियारपुर (पटना) है. वर्तमान समय में राहू की महादशा में गुरु की अंतरदशा है. राहू भाग्येश शनि गृह में एवं गुरु भी यहीं पर स्थित है. इस कारण समाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा तो प्राप्त होगी लेकिन, कर्मस्थान में परिवर्तन होगा. इसके उपरांत आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि होगी. वर्तमान समय में शनि भी वृश्चिक राशि में है जिसके कारण विचारों एवं कार्य क्षेत्र में उथल-पुथल की स्थिति बनेगी. सुशील मोदी का जन्म 4 जनवरी 1952 समय 12 बजे दिन में पटना में हुआ है. वर्तमान समय में सुशील मोदी की कुंडली में राहू में चन्द्र की महादशा है. इस अवधि में कोई न कोई विरोधी उत्पन्न होते रहेंगे, जिसके कारण राजकाज में अनेक समस्या एवं अग्रणी बनने में बाधायें उत्पन्न हो सकती हैं. शांत वातावरण किसी प्रकार का चमत्कार कर सकता है. रविशंकर प्रसाद की जन्म तिथि 30 अगस्त 1954 है. वर्तमान में शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है. शनि व्यय स्थान में मित्र भाव में बैठा है. इसके साथ ही शुक्र आय स्थान में मित्र भाव से है. जिसके कारण सम्मान यश एवं पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शांत विचार बनने एवं सहयोगियों को अपने पक्ष में करने में समर्थ हो सकते हैं. नंद किशोर यादव के लिए वर्तमान समय में राहू लग्न के कारण अनेक प्रकार की समस्यायें बनती रहेंगी.

रामकृपाल यादव की प्रश्न कुंडली के अनुसार शनि दूसरे स्थान एवं बुध राहू व्यय स्थान में है, जिसका राजनीतिक लाभ प्राप्त होगा, मान-सम्मान भी प्राप्त होगा. राधामोहन सिंह की प्रश्न कुंडली के अनुसार शनि धनु स्थान एवं व्यय स्थान का बुध राहू राजनीति में एक अच्छा समय रहेगा. पंडित सुबोध मिश्रा ने बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहू ग्रह के प्रारंभिक दौर से गुजर रहे हैं. इस अवधि में मानहानि, धनहानि की प्रबल संभावना बनती है. उनकी प्राप्त जन्मतिथि सत्य है तो वर्तमान विधानसभा चुनाव में वह बिहार के नायक नहीं बनेंगे. इस तरह भाजपा के सुशील मोदी की प्राप्त जन्मतिथि से स्पष्ट होता है कि ये भी राहू में मंगल के अंतर से गुजर रहे हैं जो कि 2017 तक चलेगा. इनकी राहू की दशा समाप्ति की ओर है इसलिए उम्मीद बरकरार है. सुबोध मिश्रा के अनुसार कोई चौंकाने वाला चेहरा भी बिहार का नायक बन सकता है.■

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

एक नज़र

चुनावी हलचल

अमरेन्द्र लगे स्वजातीय वोट जुटाने में

रालोसपा नेता अमरेन्द्र सिंह इन दिनों एनडीए के प्रचार-प्रसार में जोरों से लगे हुए हैं, इसी क्रम में अमरेन्द्र से बात हुई तो उन्होंने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद व अन्य पार्टियों में की गयी युवा वर्ग की अनदेखी से आक्रोशित दिखे. उन्होंने कहा कि युवा वर्ग ही इस देश और राज्य की दशा-दिशा को बदल सकता है. साहेबगंज एवं अन्य 23 सीटों पर रालोसपा के नेताओं को विधायक बनाने में कार्यरत अमरेन्द्र ने बताया कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण मुख्य आधार है स्वजातीय वोटों को एकजुट करना, फिलहाल यही मेरा मुख्य प्रयास है. अमरेन्द्र ने बताया कि अन्य पार्टीयों के मामले में रालोसपा ने युवा वर्ग को तरजीह दी है तथा ज्यादा से ज्यादा युवा विधायक इस बार जीत कर आएंगे.

वैशाली में चुनाव प्रचार जोरों पर

बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प सीट वैशाली जिले की राघोपुर व महुआ हैं, जहां से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को उतारा है. वहीं एनडीए गठबंधन से दोनों को रोकने के लिए लालू के घोर विरोधी और वर्तमान विधायक सतीश यादव को मैदान में उतारा है. बताया जाता है कि एनडीए ने अंतिम समय में जदयू से आए सतीश यादव को टिकट दे दिया और जदयू समर्थकों का बहुत बड़ा खेमा जो लालू विरोधी रहा है सतीश के समर्थन में आ गया. और अब वह एनडीए गठबंधन के साथ है. उनके नामांकन में भारी भीड़ उमड़ी थी. सतीश यादव ने अपने उत्साही समर्थकों से कहा कि आपका यही प्यार व आर्शीवाद मुझे दोबारा विधानसभा भेजेगा. तेजस्वी यादव जहां अपने पिता के साथ प्रचार में लगे हैं वहीं सतीश यादव हर एक दरवाजे पर पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं. वहीं महुआ में तेजप्रताप के खिलाफ एनडीए के वर्तमान विधायक रवीन्द्र राय, जनाधिकार पार्टी से जगेश्वर राय, ने प्रचार कार्य किया. महुआ में ही भाजपा के टिकट से वंचित रहे हिन्दू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक विनोद यादव ने ताल ठोंक दी है. वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक अनु शुक्ला ने यह सीट अपने पति विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को सौंप दी है जो सजा से दोषमुक्त होने के बाद स्वयं चुनाव लड़ने को तैयार हुए. वहीं उनके मुक़ाबले में एनडीए प्रत्याशी लोजपा के राजकुमार साह ने अपना नामांकन दाखिल किया है वहीं पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता भी समाजवादी पार्टी से चुनाव प्रसार में लगे हुए हैं. –नसीम रब्बानी

डायबिटीज जांच शिविर का आयोजन

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लॉयन्स क्लब सीतामढ़ी वेस्ट के तत्वावधान में डायबिटिज जांच शिविर का आयोजन किया गया. नगर उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब की अध्यक्ष सविता हिसारिया ने की. शिविर में भारी संख्या में लोगों ने खून जांच कराकर लाभ उठाया. जांच डॉ विश्वनाथ बाजोरिया व डॉ जगदीश कर रहे थे. उनके सहयोग में दीप्ती सरकार व प्रो ज्योति सुंदरका कर रही थीं. मौके पर डॉ बैद्यनाथ, निर्मला मिश्रा, सीमा गुप्ता, सविता व्यास, माया भवसिंका, आशा प्रभात, बिंदू चौधरी, डॉ केएन गुप्ता, सविता अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, सज्जन हिसारिया, दीपक मस्करा समेत उपस्थित थे.■

–विम्मी कुमारी

फीवर को ना करें इग्नोर
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
आज कल फीवर अर्थात बुखार का दौर चल पड़ा है, इस सम्बन्ध में इस बार कटिहार सोनैली के चिकित्सक डॉ. मो. शाहनवाज से बात हुई डॉ. शाहनवाज से बातचीत के क्रम में मैने पूछा कि जो डॉक्टर एम.डी. लिखते […]
Dr. Md. SHAHNAWAZ (MD)
SONAILI (KATIHAR)
Carbo - XT Drops
A Colic Drops
Siliplex Syp.
Oflogyl-OZ Susp.
Acoba Syp.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.

चंपारण

बागियों ने बदला चुनावी गणित

इस चुनाव में सबसे गंभीर मुद्रा में मतदाता नज़र आ रहे हैं. मतदाता किसी के पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं. सच तो यह है कि नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से जनता परेशान है. कुछ लोग नेताओं को देखने, कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने और कुछ उम्मीदवारों के दबाव और प्रलोभन में फंसकर नेताओं केभाषण सुनने जा रहे हैं, लेकिन आम जनता नेताओं के अनर्गल प्रलाप से परेशान है. नेताओं के बड़बोलेपन के कारण समाज में विद्धेष की स्थिति बनती जा रही है. चुनाव में दो ही समीकरण काम करते नज़र आ रहे हैं. एक जातीय ध्रुवीकरण और दूसरा विकास का मुद्दा. विकास के मुद्दे पर पढ़ा-लिखा वर्ग चर्चा तो कर रहा है लेकिन वहां भी जातीय समीकरण हावी होता दिख रहा है.

डॉ शमीम अहमद | नीता शर्मा केशरिया | पवन पासवान | राजेन्द्र गुप्ता | रामपुकार सिन्हा

राकेश कुमार feedback@chauthiduniya.com

पूर्वी चंपारण की बारह विधानसभा सीटों के लिए 1 नवम्बर को मतदान होना है. सात अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. राजग गठबंधन, महा-गठबंधन के साथ ही तीसरा मोर्चा, बसपा के उम्मीदवारों के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है. निर्दलीय प्रत्याशियों में से कई को डमी उम्मीदवार भी बताया जा रहा है, जबकि कुछ ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने दलीय उम्मीदवारों की नींद उड़ी दी है. बागियों के कारण भाजपा, राजद और जदयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इतना हीं नहीं बागियों द्वारा सीटें झटक लेने की बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. दलीय उम्मीदवारों को जनता में अपनी पैठ के अलावा पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे के बाद हवा का रुख अपने ओर होने की उम्मीद है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों को अपनी छवि और जनता के बीच रहने का लाभ मिलने की आशा है. दलीय उम्मीदवारों द्वारा बड़े नेताओं को क्षेत्र में बुलाने की होड़ लगी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर सुशील मोदी तक का दौरा होना है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी दौरा होना तय है. वहीं लालू प्रसाद […]

[…] होते नज़र आ रहे हैं. जिले का महत्वपूर्ण क्षेत्र है ढाका. विगत चुनाव में वहां से निर्दलीय उम्मीदवार पवन जायसवाल चुनाव जीते थे, जिन्होंने अगस्त में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली. 2010 के चुनाव में उन्होंने जदयू के फैसर रहमान को मात्र 1649 मतों से हराया था. इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार होने के बाद उनकी जीत पर कोइ संदेह नहीं था लेकिन रालोसपा के बागी उम्मीदवार रामपुकार सिन्हा ने पूरे समीकरण को ही ध्वस्त कर […]

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर सुशील मोदी तक का दौरा होना है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी दौरा होना तय है. वहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का तूफानी दौरा होना है. तीसरा मोर्चा के नेताओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को बुलाने का भी दावा किया जा रहा है. वहीं पप्पू यादव, नागमणी तथा तारिक अनवर का भी दौरा होना है.बागी उम्मीदवार भी कई स्तर पर सियासी दलों को हानि पहुंचाने में जुटे हैं.

दिया. फैसल रहमान पुनः चुनाव मैदान में हैं. महा-गठबंधन के राजद से वे चुनाव मैदान में हैं. फैसल की मुस्लिम वोटरों पर मजबूत पकड़ है. इधर बागी रामपुकार सिन्हा क्षेत्र की कुशवाहा जाति का समर्थन प्राप्त है, क्षेत्र में मुस्लिमों के बाद सबसे ज्यादा कुशवाहा मतदाताओं की संख्या है. पूर्व में कुशवाहा मतों का एक बड़ा हिस्सा पवन जायसवाल के साथ हुआ करता था. रामपुकार […]

[…] दिया. कभी यह क्षेत्र कम्यूनिस्टों का गढ़ माना जाता था. कम्युनिस्ट आंदोलन से किसान परेशान थे. ऐसे में भारतीय कृषक संघ के नेता राय हरिशंकर शर्मा ने कृषकों के हक की मज़बूत लड़ाई लड़ी थी. साल 1980 और 1985 में हरिशंकर शर्मा चुनाव जीते थे और किसानों को बड़ी राहत मिली थी. उन्होने क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य किए. उनके बाद राय शिवारंजन शर्मा भाजपा की राजनीति में आए परंतु उनकी हत्या हो गई. स्वसुर राय हरिशंकर शर्मा और पति शिव रंजन शर्मा के बाद नीता शर्मा भाजपा की राजनीति में आईं. अब चुनावी मैदान में उतरने के बाद नीता शर्मा को स्वसुर राय हरिशंकर शर्मा के कार्यों और कृषक नेता के व्यक्तित्व का लाभ मिल रहा है. अपनी व्यवहार कुशलता के साथ कृषक नेता की पुत्रवधु होने के कारण उनके समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. भूमिहार के सीट केबदलने के कारण जहां भूमिहारों में आक्रोष है, वहीं किसी उच्च वर्ग के नेता को किसी भी दल द्वारा प्रत्याषी नहीं बनाने को लेकर भी सभी में नाखुशी है. ऐसे में नीता शर्मा चुनाव मैदान में उतरकर भाजपा और राजद के चुनावी समीकरण को ध्वस्त करती नज़र आ रही हैं. नीता शर्मा रंजन गैस एजेन्सी की प्रोपराइटर भी हैं. इस वजह से भी वह लोगों के लगातार संपर्क में रही हैं. संग्रामपुर से जिला पार्षद रह चुकी नीता को महिला होने का लाभ भी मिल रहा है. महिलाओं का उनसे भावनात्मक लगाव उन्हें सशक्त बनाता जा रहा है. बकौल नीता शर्मा स्वसुर द्वारा क्षेत्र की सेवा और उनके पति का बलिदान क्षेत्र की जनता को याद है. उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन […]

[…] की स्थिति बनती जा रही है. चुनाव में दो ही समीकरण काम करते नज़र आ रहे हैं. एक जातीय ध्रुवीकरण और दूसरा विकास का मुद्दा. विकास के मुद्दे पर पढ़ा-लिखा वर्ग चर्चा तो कर रहा है लेकिन वहां भी जातीय समीकरण हावी होता दिख रहा है. इसी जातीय समीकरण के कारण कई सीटों पर बागी उम्मीदवार मजबूत […] बागी नीता शर्मा को राजनीतिक परिवार से आने का लाभ भी मिल रहा है. वहीं केसरिया विधानसभा क्षेत्र को भूमिहारों और राजपूतों की सीट माना जाता रहा है. 2010 के चुनाव में यहां से भाजपा के भूमिहार नेता सच्चिनद्र प्रसाद सिंह जीते थे. बावजूद इसके किसी भी दल ने इस क्षेत्र से उच्च वर्ग का प्रत्याशी नहीं […] होगा.बहरहाल बागियों के कारण राजग गठबंधन और महा-गठबंधन की कई सीटों का समीकरण बिगड़ता नज़र आ रहा है. साथ ही दलीय प्रत्याषियों की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं. ऐसे में यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी सीट झटक ले, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.■

बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र

विकास के लिए नेताओं को घेरेगी जनता

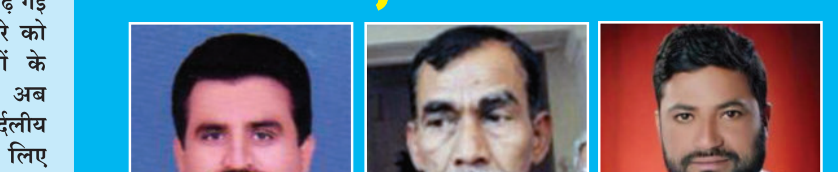

शम्भु प्रसाद अभय

बड़हरिया विधान सभा क्षेत्र की राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है. पहले तो टिकट बांटवारे को लेकर काफी समय तक सभी दलों के संभावित उम्मीदवारों में असंतोष रहा, अब स्थिति सामान्य हुई तो सभी दलीय व निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी-चोटी एक किए हैं. महा-गठबंधन की ओर से जदयू के निर्वतमान विधायक श्याम बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. एक दशक पूर्व इस विधानसभा क्षेत्र का गठन परिसीमन के बाद किया गया था. तब से इस सीट पर जदयू के श्याम बहादुर सिंह का ही […]

भी बसपा के टिकट पर चुनावी दंगल में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इसके अतिरिक्त […]

ग्रामीण ईलाकों में दिन में दो घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है. सिंचाई के लिए तो […]

[…] हावी है, मतदाताओं व समाजिक लोगों का कहना है कि अब तक बड़हरिया में विकास को गति क्यों नहीं दी गई. बड़हरिया-मीरगंज मुख्य मार्ग में छक्का टोला के समीप लगभग तीन किलोमीटर तक सड़क एक दशक से गढ़े में तब्दील है. यातायात बंद है. उसे क्यों नहीं बनवाया गया, लोगों का कहना है कि वोट मांगने आने वाले नेताओं से इस विषय पर सवाल किए जायेंगे. जनता की इस सोच से नेताओं के माथे पर शिकन पड़ने लगी हैं. उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को क्या जवाब दिया जाए और कैसे उनसे वोट मांगा जाए.

बड़हरिया विधान सभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 1.72 लाख हैं जिसमें […]

feedback@chauthiduniya.com

हथुआ विधानसभा क्षेत्र

मतदाता खामोश, नेता परेशान

अखिलेश मिश्र

बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान 1 नवंबर को होना है. गोपालगंज जिले की कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी हलचल शुरू हो गई है. इस बीच टिकट बंटवारे को लेकर संबंधित दलीय कार्यकर्ता अपना विरोध भी जता रहे हैं. जहां तक उम्मीदवार की बात है, तो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए प्रत्याशियों को जनता नकारेगी या स्वीकारेगी यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही मालूम होगा. गोपालगंज के हथुआ विधानसभा क्षेत्र से महा-गठबंधन ने स्थानीय जदयू विधायक रामसेवक सिंह को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा के सहयोगी दल हम ने […]

महाचंदर सिंह | राजेश सिंह | रामसेवक सिंह

[…] मील यहां शुरू हुई थी. लेकिन धीरे-धीरे एक-एक करके ये उद्योग बंद होते चले गए. साल 2005 केविधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी सभा में बंद चीनी मील को चालू करने कि घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि एनडीए केसरकार बनते […]

[…] जुड़े लोगों की माली हालत खराब हो गई.

वर्तमान विधायक रामसेवक सिंह अपने क्षेत्र के विकास और नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए विकास के साथ-साथ नौजवानों को मिले रोजगार की बिनाह पर वोट मांग रहे हैं. इनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार के बनते ही बंद पड़ी हथुआ चीनी मील को फिर से चालू करने की दिशा में कारगर पहल की गई. इस […]

हथुआ विधानसभा क्षेत्र में कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन यहां सबसे अहम मुददा सालों से बंद पड़ी हथुआ चीनी मिल को चालू करने का है. साल 1985 में बंद हुई हथुआ चीनी मील को दोबारा शुरू करने की मांग सालों से उठ रही है. पिछले कई वर्षो से इसके लिए यहां आंदोलन भी हुए हैं. आजादी केबाद यहां शराब मील और चीनी मील यहां शुरू हुई थी.

संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई बार उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी हुईं. सरकार ने किसानों के बकाये का भुगतान […]

[…] अपना और अपने परिवार का विकास किया है. इस बार उनसे क्षेत्र की जनता हिसाब हिसाब मांगेगी. हम से महाचंद प्रसाद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. उनका कहना है कि देश में जिस तरह नरेंद्र मोदी की हवा चली उसी प्रकार बिहार में एनडीए की हवा चल रही है, और इस हवा में हथुआ ही नहीं बल्कि बिहार के दूसरे सभी दल उड़ जाएंगे. उनका भी यह मानना है कि जदयू विधायक ने इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की. आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र की आधी आबादी पलायन करने के लिए मजबूर है.

अगर मतदाताओं की बात की जाए तो गृहणी पूनम देवी कहती हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल जनता पर अपने उम्मीदवार थोपती हैं. उम्मीदवार का फैसला ईमानदारी व कर्मठता को देखकर नहीं बल्कि उनके रसूख और धन-दौलत को देखकर होता है. ऐसे प्रत्याशी जीतकर जनता का क्या भला करेंगे. शिक्षक भावना कुमारी का कहना है कि महिलाओं के मुद्दों पर कोई भी सरकार सकारात्मक पहल नहीं कर रही है. आधी-आबादी का दर्जा तो महिलाओं को दे दिया गया, लेकिन हकीकत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ. युवा मतदाता कुमार सत्यम कहते हैं कि चुनावी महापर्व है, मतदान तो करना ही है. किन्तु राजनीति की जो स्थिति हो चली है. उससे मतदाताओं का दिग्भ्रमित हो जाने में कोई आश्चर्य नहीं है. जो कलतक एक-दूसरे के दुश्मन थे, आज गले मिलकर एक-दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं. प्रतिभा उपाध्याय कहती हैं कि पंचायत में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया. किन्तु विधानसभा के स्तर पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने में काई भी दल रुचि नहीं ले रहा है और न ही इसके लिए तैयार है. अभी भी महिलाओं को राजनीतिक रूप से कमजोर समझा जा रहा है.

[…] चीनी मील को दोबारा शुरू करने की मांग सालों से उठ रही है. पिछले कई वर्षो से इसके लिए यहां आंदोलन भी हुए हैं. आजादी केबाद यहां शराब मील और चीनी […] के किसान नगदी फसल के रूप में गन्ने की खेती करते थे, लेकिन मिल के बंद होने से किसानों की माली हालत बिगड़ने लगी और किसान इस नगदी फसल छोड़कर, वापस पारंपरिक खेती करने लगे. जिससे मील से […] नाराज राजेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. राजेश कुमार का कहना है कि हथुआ की जनता से कोरे वादे करके वे चुनाव जीतते रहे हैं. विधायक ने विकास का कोई काम नहीं किया है. उन्होंने […] किसके पक्ष में आती है. लेकिन हथुआ विधानसभा क्षेत्र में किसकी दीवाली मानेगी और किसका दीवाला निकलेगा यह कहना बेहद कठिन है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

चुनावी हलचल

सेवा निवृत प्रधान शिक्षक को विदाई

सीतामढ़ी के पुरानी बाजार स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया. मौके पर उत्साह पूर्ण माहौल में विद्यालय के प्रधान शिक्षक विद्याभूषण मिश्र को सेवा निवृति के उपलक्ष्य में अंग वस्त्र व पाठय सामग्री देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में बच्चों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सम्मानित प्रधानाध्यापक विधाभूषण मिश्र ने कहा कि भारत की परंपरा रही है कि गुरू को सर्वोच्च माना गया है. वर्तमान परिवेश में शिक्षकों को शिक्षा के विकास के प्रति सजग रहने की जरूरत है. जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है. मिश्र ने बच्चों को शिक्षा के प्रति सजग रहने की नसीहत दी. कार्यक्रम में पूर्व प्रधानाध्यापक आनंद कुमार, विनोद प्रसाद सिंह, मो. अली आजम, डॉ इंद्रा कुमारी, विद्यानंद सिंह, अभय कुमार, बेबी कुमारी, रामरस कुमारी, नीलम गुप्ता, पूर्णिमा गुप्ता समेत अन्य थे. – ब्रजेश कुमार

जयंती पर याद किये गये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बक्सर जिले में अलग-अलग स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय डुमराव में स्वच्छता अभियान कैलाशपुरी के टीम लीडर गगन प्रसाद के नेतृत्व में चंडीधाम कैलाशपुरी में गांधी जयंती सह वरीय नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. मौके पर सफाई अभियान में सक्रिय सहयोग करने वाले कुशेवर प्रसाद सिंह, नंदलाल ठाकुर, सकलदेव झा, नथुनी मंडल, सदाशिव झा, श्यामनंदन झा व रंवीद्र भूषण वर्मा को सक्रिय योगदान के लिए गांधी टोपी से सम्मानित किया गया. जबकि वरीय नागरिक राम किंकर सिंह, कृष्णकांत शर्मा, राम कुमार मंडल, अक्षेवर राय, उपेंद्र राय, राम सेवक राय, अरिमर्दन सिंह, एसएन राय व सतीश प्रसाद को माला पहनाकर सम्मानित किया गया. मौके पर कार्यक्रम के आयोजक गगन प्रसाद ने कहा कि पिछले एक साल में सफाई अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में सफलता मिली है. इस कार्य में टीम के सभी सदस्यों के अलावा स्थानीय लोगों का भी सराहनीय सहयोग रहा है. कार्यक्रम में देवेंद्र झा, एबी लाल, अधिवक्ता विनय कुमार झा, महाशंकर प्रसाद, व डीएन झा समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे. –विकास कुमार

वरीय स्वतंत्र पत्रकार को श्रद्धांजली

सीतामढ़ी जिले के वरीय स्वतंत्र पत्रकार अजय विद्रोही की गत 29 सितंबर की रात कुछ अपराधियों ने गोली मार हत्या कर दी. घटना के बाद जिले के पत्रकारिता से लेकर सामाजिक क्षेत्र में शोक व्याप्त हो गया. समाज के सभी तबके के लोगों ने दिवंगत पत्रकार को जिले के लिए अपूरणीय क्षति बताया. चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष कैलाश हिसारिया, उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, सचिव राजेश कुमार सुंदरका, कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद, रामजी शर्मा, सज्जन हिसारिया, पवन हिसारिया, अनूप हिसारिया, नरोत्तम व्यास, नगर विधायक सुनील कुमार पिंटू, रून्नी-सैदपुर विधायक गुड्डी देवी, पूर्व विधायक नगीना देवी, वरीय नेता राजेश चौधरी, डॉ राजेश कुमार सिंह, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष विभा रानी, अध्यक्ष अमिताभ कुमार, महासचिव केशव आनंद, वरीय पत्रकार प्रो श्याम किशोर सिंह, रामा शंकर शास्त्री, शिव कुमार, मीडिया फॉर बॉर्डर हारमोनी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष अवध बिहारी उपाध्याय, कार्यक्रम प्रभारी, सर्वधीर मिश्र, डुमरा संयोजक त्रिपुरारी शरण, अनुनय कश्यप व ब्रजेश कुमार सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति केलिए प्रार्थना की.■ –वाल्मीकि

सीतामढ़ी-शिवहर

चुनावी महासंग्राम की तैयारी में जुटे सूरमा

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे दौर का मतदान हो चुका है. सीतामढ़ी जिले की 8 और शिवहर के एक विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों ने चुनावी महासंग्राम की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एनडीए, महा-गठबंधन व तीसरे मोर्चे के आलावा स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी अबकी बार आमने-सामने की लड़ाई में दो-दो हाथ करने का मन बना लिया है. मतदाता जाति व पार्टी के साथ ही धनबल व बाहूबल के स्वामियों की खातिरदारी के लिए तैयार हैं. इस चुनाव को लेकर तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार भी गरमाने लगा है. कहीं जातीय उन्माद, तो कहीं पैसे का खेल, तो कहीं हमदर्दी का मरहम भी बंटना शुरू हो गया है. बावजूद इसके यह कहना मुश्किल है कि अबकी बार बाजी किसके हाथ लगेगी.

वाल्मीकि कुमार feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी व शिवहर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक उफान नज़र आने लगा है. टिकट की चाह में […]

[…] का विधायक चुने जाने का कोई तुक नहीं है. गठबंधन की राजनीति के कारण कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर चुनावी समीकरणों की जोड़तोड़ का खेल शुरू हो गया है. यदि चुनावी चर्चाओं पर यकीन करें तो यदि जातीय राजनीतिक रंग […]

लवली आनंद | डॉ रंजु गुप्ता | गायत्री यादव | गुड्डी देवी | नगीना देवी | रेखा गुप्ता | सरिता यादव

डॉ रामचंद्र पुर्वे | मो. शम्स शहनवाज | मोतीलाल प्रसाद | पंकज कुमार मिश्रा | शाहिद अली खान | सुनील कुमार पिंटु | ठाकुर रत्नाकर राना

[…] का सामना करना पड़ सकता है. इसका कारण यह कि […] परिहार विधानसभा सीट भी इस चुनाव में अहम […] मौका दिया है. इस सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भी […]

विधानसभा चुनाव जिला गोपालगंज

नेताओं का शह-मात का खेल जारी

चुनावी समर में इस बार नया चेहरा हथुआ विधान सभा सीट से हम के उम्मीदवार महाचंन्द्र सिंह हैं, वहीं पूर्व सांसद काली प्रसाद पाडेय कुचायकोट से लोजपा के उम्मीदवार बनाये गये हैं. भाजपा ने मिथलेश तिवारी को बैकुण्ठपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है. इस बार भाजपा और जदयू ने अपने पुराने विधायकों को फिर से प्रत्याशी बनाया है. कुचायकोट विधान सभा क्षेत्र की बात करे तो यहां इस बार दो बाहुबलियों केबीच टक्कर है. क्छायकोट विधान सभा सीट पर कुख्यात बाहुबली सतीश पाडेय केभाई जदयू विधायक अमरेन्द्र कुमार पाडेय उर्फ पप्पू पाडेय का पिछले दो चुनाव से क़ब्जा है. इस बार लोजपा ने पूर्व में बाहुबली रहे, पूर्व सांसद कालीप्रसाद पाडेय को अपना उम्मीदवार बनाया है. साल 2010 के चुनाव केआंकड़ों पर नज़र डाली जाये तो जदयू से चुनाव लड़े अमरेन्द्र पाडेय ने राजद के आदित्य नारायण पाडेय को 19 हजार 518 मतों के अंतर से हराया था.

अखिलेश मिश्र

गोपालगंज जिले की 6 विधान सभा सीटों के लिए चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं. राजनीतिक दलों के योद्धा चुनावी समर में कूद पड़े हैं. इस बार चुनाव में परिवेश कुछ बदला-बदला सा नजर आ रहा हैं, कल तक जो विपक्ष थे आज वे पक्ष में हैं. पक्ष में थे वे आज विपक्ष में है. ऐसी स्थिति में मतदाता भी उहापोह की स्थिति में हैं. साल 2010 के विधान सभा चुनाव में भाजपा और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, राजद विपक्ष में था. इस बार महा-गठबंधन में जदयू, राजद और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनावी समर में उतरे हैं. वर्तमान में गोपालगंज जिले की 6 विधान सभा सीटों में से तीन पर भाजपा का कब्जा है तो तीन पर सत्तारूढ़ जदयू का. इस बार भाजपा जिले की चार सीटों(गोपालगंज, बरौली, भोरे (सुरक्षित) और बैकुंठपुर) पर चुनाव लड़ रही है, वहीं लोजपा(कुचायकोट) और हम(हथुआ) एक-एक सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं. वहीं महागठबंधन से जदयू तीन, राजद दो और कांग्रेस एक सीट पर चुनाव लड़ रही है. लालूप्रसाद यादव का गृह जिला होने के कारण उनकी नजरें गोपालगंज के चुनाव पर टिकी हैं. इन छह विधान सभा क्षेत्रों पर जहां एनडीए कि नज़र है, वहीं महा-गंठबधन भी अपनी जीत के लिए कोई कोर कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. चुनावी समर में इस बार नया चेहरा हथुआ विधान सभा सीट से हम के उम्मीदवार महाचंन्द्र सिंह हैं, वहीं पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय कुचायकोट से लोजपा के उम्मीदवार बनाये गये हैं. भाजपा ने मिथलेश तिवारी को बैकुन्टपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है. इस बार भाजपा और जदयू ने अपने पुराने विधायकों को फिर से प्रत्याशी बनाया है.

कुचायकोट विधान सभा क्षेत्र की बात करे तो यहां इस बार दो बाहुबलियों केबीच टक्कर है. कुचायकोट विधान सभा सीट पर कुख्यात बाहुबली सतीश पांडेय के भाई जदयू विधायक अमरेन्द्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय का पिछले दो चुनाव से क़ब्जा है. इस बार लोजपा ने पूर्व में बाहुबली रहे, पूर्व सांसद कालीप्रसाद पांडेय को अपना उम्मीदवार बनाया है. साल 2010 के चुनाव के आंकड़ों पर नज़र डाली जाये तो जदयू से चुनाव लड़े अमरेन्द्र पांडेय ने राजद के आदित्य नारायण पांडेय को 19 हजार 518 मतों के अंतर से हराया था. 2010 केचुनाव में अपने भाई आदित्य नारायण पांडेय को जिताने के लिए काली प्रसाद ने किसी भी तरह की कोर-कसर नहीं छोड़ी थी. फिर भी वे अपने भाई को जीत नहीं दिला सके. इस बार वे खुद चुनाव मैदान में हैं. दोनों बाहुबलियों के चुनाव मैदान में आ जाने से चुनावी दंगल का स्वरूप ही बदल गया है. दोनों एक दूसरे को मात देने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं दोनों ही चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं. परिसीमन के बाद कुचायकोट विधान सभा ब्राम्हण बहुल्य क्षेत्र बन गया है, जहां ब्राम्हणों की संख्या अन्य समुदायों से ज्यादा है. 2010 में जदयू और भाजपा गठबंधन केकारण जदयू केखाते में जाने से भाजपा नेता उमेश प्रधान ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिन्हें 15 हजार 615

साधु यादव

मंजीत कुमार सिंह

काली पाण्डेय

महाचंद्र सिंह

मिथिलेश तिवारी

मिथिलेश तिवारी

पप्पु पाण्डेय

सुभाष सिंह

ओमप्रकाश सिंह

भोरे

वोट मिले. इस बार भी भाजपा के सहयोगी दल लोजपा केखाते में कुचायकोट सीट चली गई है. फिर इस बार उमेश प्रधान भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ने का मन बनाया है. कुचायकोट विधान सभा सीट पर एक दर्जन नेताओं का नजर है, और वे टिकट के लिए पटना से दिल्ली तक एक किए हुए हैं. वैसे तो गोपालगंज में चौथे चरण में चुनाव होने हैं. नामांकन के बाद ही स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी. किस दल से कौन प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहा है.

2005 से गोपालगंज विधान सभा क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा रहा है. राजद लगातार भाजपा से हारती रही है. इस बार भी भाजपा पुराने योद्वा सुभाष सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है. वहीं राजद ने अपने पुराने साथी रेयाज-उल-हक़ राजू को चुनावी मैदान में उतारा है. 2010 का चुनावी आंकड़ा देखा जाए तो भाजपा के सुभाष सिंह ने 15 हजार 893 मतों से राजद केरेयाज़-इल-हक़ राजू को हराया था. साधु यादव को 8 हजार 488 मत मिले थे. इस बार चुनाव में इन दोनों केअलावा गरीब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु यादव और जिला पार्षद ओमप्रकाश सिंह ने भी चुनाव मैदान में उतरे का ऐलान किया है. इस वजह से चुनाव रोचक मोड़ में आ गया है. जैसे-जैसे मतदान की तारीख करीब आती जायेगी, वैसे-वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जायेगी.

2015 का चुनाव हथुआ विधान सभा के लिए दिलचस्प नजारा होगा. एनडीए के सहयोगी हम पार्टी के खाते में हथुआ सीट जाने राजद को छोड़ भाजपा के दामन थामे राजेश कुमार सिंह अब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेगें. भाजपा के बगावत के बाद भी राजेश कुमार सिंह के पक्ष में भाजपा नेता धनंजय राय, जितेन्द्र सिंह सहित दर्जनों लोग खुलकर मैदान में उतर गए हैं. जिसे एनडीए गठबंधन को खतरा दिख रहा है. 2005 से जदयू के रामसेवक सिंह का कब्जा है. 2010 के चुनाव में राजद के राजेश कुमार को 22 हजार 847 मतों से रामसेवक सिंह ने पराजित किया था. कांग्रेस के बाबुदीन खां को 7 हजार 929 मत मिले थे. इस बार हम पार्टी से महाचन्द्र सिंह, जदयू से रामसेवक सिंह चुनाव मैदान में हैं. निर्दलीय राजेश कुमार सिंह के चुनाव मैदान में आने से यहां की चुनावी तस्वीर बदल गई है.

बरौली विधानसभा क्षेत्र में इस बार उहापोह की स्थिति है यहां कन्फ्यूजन के हालात हैं. अंदरूनी सियासी घमासान तेज है. इस बार महा-गठबंधन से चुनाव कौन लड़ेगा, यह पार्टी स्तर पर तो साफ नहीं है, न चेहरे अभी स्पष्ट हो रहे हैं. राजद और कांग्रेस का इस सीट पर कई बार कब्जा रहा है. वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों कि एक लंबी कतार है, जिनका इस चुनाव में उतरने का मन है, ये उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों के जीत-हार के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं. राजद और कांग्रेस केसंभावित उम्मीदवार टिकट पाने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं.

1980 से बैकुंठपुर विधान सभा चुनाव का परिमाण देखा जाय तो राजपूत और यादव के बीच लड़ाई रही है. लेकिन इसबार यहां का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है. बैकुंठपुर विधान सभा सीट पर जदयू के विधायक मंजीत कुमार सिंह का कब्जा है. इस बार भी जदयू ने उन्हें अपना उमीदवार बनाया है. उनकी लड़ाई हमेशा राजद के साथ रही, इन्हीं दोनों के बीच हार-जीत निर्धारित होती रही है. इस बार सवाल यह है कि बैकुंठपुर क्षेत्र के यादव मतदाता इसबार किसके साथ होंगे. इसका लाभ लेने के लिए गरीब जनता दल के साधु यादव ने बैकुंठपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनावी बिगुल फूंक दिया है. भाजपा ने यहां से मिथलेश तिवारी को अपना उमीदवार बनाया है. फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के चुनाव में राजद के देवदत्त राय ने अपनी सीट को सुरक्षित रखा. 2010 के चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े मंजीत कुमार सिंह ने 33581 मतों से देवदत्त राय को हराया. देवदत्त राय के निधन के बाद राजद छोड़ उनके पुत्र भाजपा में शामिल हुए. टिकट की उम्मीद में रहे देवदत्त राय के पुत्र के हाथ निराशा लगी इसके बाद उन्होंने अपनी मां को निर्दलीय प्रत्याशी बनाने का मन बनाया है.

बरौली विधानसभा क्षेत्र में इस बार उहापोह की स्थिति है यहां कन्फ्यूजन के हालात हैं. अंदरूनी सियासी घमासान तेज है. इस बार महा-गठबंधन से चुनाव कौन लड़ेगा, यह पार्टी स्तर पर तो साफ नहीं है, न चेहरे अभी स्पष्ट हो रहे हैं. राजद और कांग्रेस का इस सीट पर कई बार कब्जा रहा है. वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों कि एक लंबी कतार है, जिनका इस चुनाव में उतरने का मन है, ये उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों के जीत-हार के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं. राजद और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार टिकट पाने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. दरअसल, इस बार के विधानसभा चुनाव में एक पक्ष भाजपा के नेतृत्व वाला राजग गठबंधन है, तो दूसरा नीतीश के नेतृत्व में राजद-जदयू व कांग्रेस का महागठबंधन. बरौली सीट से राजग गठबंधन इस लिए सहज है कि इस सीट पर भाजपा का कब्जा है. यहां से विधायक हैं रामप्रवेश सिंह. बरौली की सीट भाजपा के पास है, इसलिये यहां गठबंधन में शामिल अन्य दलों से कोई विवाद नहीं है. राजद के संभावित उम्मीदवारों का सीवान जेल में बंद राजद नेता महमद सहाबुद्दीन के पास आने-जाने का सिलसिला लगा हुआ है. खबर लिखे जाने तक महा-गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, यह तय नहीं हो पाया है. महा-गठबंधन के नेता के आने के बाद ही स्थिति साफ हो पायेगी. इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण की हवा निकलती नज़र आ रही है.

भोरे (सुरक्षित) विधानसभा सीट से राजद और भाजपा के टिकट से कई बार विधायक चुने गए इन्द्रदेव मांझी को भाजपा ने एक बार फिर अपना उमीदवार बनाया है. 2010 के चुनाव में भाजपा के इन्द्रदेव मांझी ने राजद के बच्चन दास को 43 हजार 570 मतों से हराया था. साल 1977 में यहां से कांग्रेस के अलगू राम जीते थे. जनता पार्टी के जमुना राम 1980 में यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए थे. राजद के अनिल कुमार ने 2005 में भाजपा के इन्द्रदेव मांझी को हराया था. भोरे क्षेत्र कांग्रेस के खाते में गया है, जिसपर कई नेताओं कि नजरें हैं. लेकिन खबर लिखे जाने तक यहां से कांग्रेस का कौन उमीदवार होगा यह तय नहीं हो पाया है. प्रत्याशी के नाम पर अंतिम निर्णय होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

दिग्गजों की विरासत पर दिखेंगे नए चेहरे

सासाराम

दिनारा की लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी. बिहार की राजनीति में अचानक अवतरित हुए भाजपा के राजेंद्र सिंह और सरकार के सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह के बीच जंग होगी. बीच में भाजपा उम्मीदवार जवाहर यादव और पूर्व विधायक सीता सुंदरी कोण बनाने का प्रयास जरूर करेंगे. नोखा की लड़ाई लगभग पुरानी है. इस बार राजद के पूर्व मंत्री आनंद मोहन सिंह के निधन बाद सहानुभूति लहर के सहारे उनकी पत्नी अनीता चौधरी की चुनावी नैया को जदयू पार लगाना चाहती है. जबकि नाराज मतदाताओं को गोलबंद करने में भाजपा के रामेश्वर चौरसिया लगातार लगे हुए हैं.

वशिष्ठ सिंह

रामेश्वर चौरसिया

इलियाश हसन

जय कुमार सिंह

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार विधानसभा चुनाव इस बार नए जागीरदारों को सामने लाने वाले हैं. ऐसा पहली बार हुआ है जब रामगढ़ विधानसभा सीट पर कई दशकों से कब्जा जमाए बैठे जगदानंद सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है. दिनारा सीट पर हाथ मार रहे तपेश्वर सिंह के छोटे बेटे रंजीत सिंह को टिकट मिलते-मिलते रह गया. उसी परिवार की सांसद मीना सिंह के बेटे विशाल सिंह जदयू का टिकट पाने में असमर्थ रहे और छेदी पासवान अपने दल भाजपा से बेटे रवि पासवान को टिकट दिलाने में असफल साबित हुए. इसके अलावा भभुआ सीट पर लालमुनी चौबे के बेटे को टिकट मिलने की उम्मीदें भी समाप्त हो गईं. ऐसे कितने दिग्गज राजनीतिक खिलाड़ी इस बार हाशिये पर चले गए. यहां तक कि जदयू के गढ़ करगहर में स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह को जदयू से टिकट नहीं मिला जो कि उनके लिए बहुत बड़ा झटका है. पार्टी ने उनकी जगह एक नौजवान उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसकी जीत की संभावनाएं प्रबल हैं. पूर्व मंत्री डॉ. श्रीमती कांति सिंह की चर्चा किए बगैर चुनावी विश्लेषण पूरा नहीं हो सकता, जो काराकाट सीट के लिए राजद का टिकट लगभग ले चुकी थीं, परंतु ऐन वक्त पर उनके हाथों से टिकट उड़कर पार्टी के नवोदित संजय कुमार यादव के हाथों में जा गिरा. पूर्व विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह भी जदयू का टिकट पाने की पुरजोर कोशिश की लेकिन अंत में जब निराशा हाथ लगी तो उन्होंने सासाराम से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया. भाजपा का टिकट नहीं मिलने के बाद छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान ने तीसरे मोर्चे का हाथ थाम लिया, जबकि रामधनी सिंह भी तीसरे मोर्चे की शरण में जाकर अब चुनावी मैदान में हैं. जिन दिग्गजों के परिजनों को टिकट नहीं मिला वे वाच एंड वेट की मुद्रा में आ गए हैं. लेकिन इनमें से कुछ चुनावी मैदान में उतरे बगैर नहीं रह पाये. देखना यह है कि इस चुनाव में उन्हें सफलता मिलती या फिर जनता उन्हें नकार देगी. यह तो समय आने पर ही पता चलेगा, परंतु यह बात चर्चा में है कि पार्टियों द्वारा टिकट नहीं मिलने से उनकी लोकप्रियता में भारी कमी आई है. यदि यह कमी मत में परिवर्तित हो गई तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी शिकस्त होगी.

भाजपा का टिकट नहीं मिलने के बाद छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान ने तीसरे मोर्चे का हाथ थाम लिया, जबकि रामधनी सिंह भी तीसरे मोर्चे की शरण में जाकर अब चुनावी मैदान में हैं. जिन दिग्गजों के परिजनों को टिकट नहीं मिला वे वाच एंड वेट की मुद्रा में आ गए हैं. लेकिन इनमें से कुछ चुनावी मैदान में उतरे बगैर नहीं रह पाये. देखना यह है कि इस चुनाव में उन्हें सफलता मिलती या फिर जनता उन्हें नकार देगी.

रोहतास की सात विधान सभा सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है. जिसमें चेनारी सुरक्षित विधान सभा में खूब चर्चा पाने के बाद मीरा कुमार के नजदीकी कहे जाने वाले मुरारी गौतम को पार्टी ने बेटिकट कर मंगल राम को उम्मीदवार बनाया है. जो रालोसपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक ललन पासवान के सामने होंगे. रालोसपा ने डेहरी सीट पर फतेहबहादुर के नाम की चर्चा होने के बाद भी भाजपा से आए रिंकू सोनी को टिकट दिया गया. जिनका मुक़ाबला पूर्व निर्दलीय विधायक प्रदीप जोशी और मोहम्मद इलियास हुसैन से है. काराकाट में लड़ाई पुरानी होगी. सिर्फ राजद उम्मीदवार मुन्ना राय की जगह संजय कुमार यादव को पार्टी ने टिकट दिया है. जिनके सामने भाजपा के राजेश्वर राज और माले के पूर्व विधायक अरूण कुमार जैसे दिग्गज खड़े हैं. दिनारा की लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी. बिहार की राजनीति में अचानक अवतरित हुए भाजपा के राजेंद्र सिंह और सरकार के सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह के बीच जंग होगी. बीच में भाजपा उम्मीदवार जवाहर यादव और पूर्व विधायक सीता सुंदरी कोण बनाने का प्रयास जरूर करेंगे. नोखा की लड़ाई लगभग पुरानी है. इस बार राजद के पूर्व मंत्री आनंद मोहन सिंह के निधन बाद सहानुभूति लहर के सहारे उनकी पत्नी अनीता चौधरी की चुनावी नैया को जदयू पार लगाना चाहती है. जबकि नाराज मतदाताओं को गोलबंद करने में भाजपा के रामेश्वर चौरसिया लगातार लगे हुए हैं. सासाराम सीट पर दो पुराने प्रतिद्वंदी भाजपा के जवाहर प्रसाद और राजद के डॉ अशोक कुमार आमने-सामने हैं. जिनके बीच से जदयू के बागी श्री कृष्ण सिंह और तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार सत्येंद्र साह जीत हासिल करना चाहेंगे. एक दिलचस्प मुक़ाबला करगहर में भी होगा. जहां कई दिग्गज एक साथ दंभ भर रहे हैं. जदयू ने युवा राजनीतिज्ञ वशिष्ठ चौधरी को उम्मीवार बनाया है. बेटिकट हुए स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने नाराज होकर तीसरे मोर्चे का दामन थाम लिया. और जदयू के निर्णय को गलत साबित करने के लिए चुनाव मैदान में हैं. कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी आलोक सिंह इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत पाने का हर संभव प्रयास करेंगे. रालोसपा उम्मीदवार के रूप में कैमूर के पार्टी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा के आने से लड़ाई को अलग कोण मिला है. जिन्हें कुशवाहा मतों को पाने के लिए ही लोजपा के बागी शिवशंकर कुशवाहा के भितरघात से निबटने के बाद ही लड़ाई में जगह मिल सकती है. इस बार जिले के सभी विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है. चाहे वह नोखा में भाजपा के रामेश्वर चौरसिया हों. सासाराम में भाजपा के जवाहर प्रसाद, करगहर में रामधनी सिंह, दिनारा में जय कुमार सिंह, काराकाट में राजेश्वर राज, डेहरी में विधायक ज्योति रश्मि जोशी के पति प्रदीप जोशी, चेनारी में जदयू द्वारा छोड़ी गई सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मंगल राम हों. सबके लिए सीट बचाने की कठिनाई सामने है. सभी दलों के बागी उम्मीदवार कठिनाई पेश कर सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

ललन पासवान

राजेन्द्र सिंह

राजेश्वर राज

रामधनी सिंह

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

19 अक्टूबर-25 अक्टूबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

सारी पार्टियां सेंक रही रोटी, अखिलेश संजीदगी पर, तो आजम राष्ट्र विरोध पर उतरे

दादरी से खेल रहे सियासत के पादरी

अखिलेश ने कहा कि साम्प्रदायिकता से विकास प्रभावित होता है और आम आदमी को नुकसान पहुंचता है. कुछ ताकतें साम्प्रदायिकता फैलाने की साजिश कर रही हैं, जिनसे सावधान रहना होगा. साम्प्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने वाली ताकतें, देश व प्रदेश को पिछड़ेपन की दिशा में ले जाना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बदनाम करने की भी साजिशें चल रही हैं.

प्रभात रंजन दीन

गोमांस के नाम पर दादरी में हुई हत्या अब राष्ट्र-द्रोह और राष्ट्र-प्रेम साबित करने की होड़ पर केंद्रित हो गई है. शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने सपा नेता आजम खान को राष्ट्र विरोधी करार दिया और उन पर राष्ट्र-द्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की. शिवसेना ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर प्रहार किया. इस पर सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव भी मैदान में उतर पड़े और मुलायम की राष्ट्रभक्ति के हवाले से शिवसेना पर तीखा हमला बोला. इसके बाद मुलायम ने भी मुंह खोला और बोले कि भले ही सपा की सरकार चली जाए, लेकिन दादरी मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उधर, नोएडा के दादरी इलाके के बिसाहड़ा गांव में गोमांस खाने के नाम पर जिस व्यक्ति को मारा गया उसी के समुदाय के लोग कहते हैं कि सियासत के पादरी दादरी से खेलना बंद करें तब तो अमन और सौहार्द पर यहां के लोग सोचें या पहल करें! गोमांस पकाने या खाने के नाम पर पिछले दिनों अधेड़ उम्र के अखलाक मार डाले गए और उनका बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. हिंसा पर उतारू लोगों के झुंड ने गो-हत्या रोकने के नाम पर सरेआम एक व्यक्ति की हत्या कर दी, लेकिन सियासतदानों को राजनीति की गंदी रोटी सेंकने के सिवा कुछ नहीं सूझता. तमाम सियासी दलों के नेता नौटंकी का मंच समझ कर उदासी और गंभीरता का भौंडा चेहरा बनाए दादरी गांव पहुंचे और किसी ने मरहूम अखलाक के घर से तो किसी ने हत्यारोपियों के घर के मुंडेर से निकृष्ट कोटि की राजनीति की पतंगें उड़ाईं. न किसी नेता को अखलाक के बर्बरता पूर्वक मारे जाने का कोई दर्द है और न ही किसी नेता में गोहत्या रोकने के लिए खुद शहादत देने का कोई जज्बा है. सब धंधेबाज हैं. मांस के लिए गौ वंशीय पशुओं की तस्करी के दस्तावेज खंगालें तो पाएंगे कि तमाम ऐसे नेता जो हिंदूवाद का झंडा फहराते घूमते हैं, अपने संरक्षण में गौ-वंशीय पशुओं की तस्करी कराते हैं और जेबें भरते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी है, जिससे अखलाक के बेटे का अच्छे से इलाज हो सके. लेकिन समाजवादी पार्टी का ही दो चेहरा सामने आया. एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संजीदगी और सदाशयता का रुख दिखाते हुए संकट के समय में पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए आगे आते हैं और इस घटना को तवे की तरह इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य आजम खान ओछा रवैया दिखाने से बाज नहीं आते. यह भी हो सकता है कि ओछी हरकतों पर उतरे कुछ भाजपाइयों का उसी स्तर से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने आजम खान को मैदान में उतारा हो. मरहूम अखलाक का फौजी बेटा मोहम्मद सरताज नेताओं से अच्छा और बुद्धिमान साबित हुआ, जिसने ऐसे संवेनदशील मामले में राजनीति न करने की सीख दी और लोगों से प्रेमभाव बनाए रखने की अपील की.

बहरहाल, बिसाहड़ा गांव की उस घटना का कुछ उल्लेख करते चलें. पिछले दिनों दादरी के बिसाहड़ा गांव में गोमांस खाने और रखने की अफवाह को लेकर मोहम्मद अखलाक को पीट-पीट कर मार डालने और उनके बेटे दानिश को गंभीर रूप से जख्मी करने की घटना हुई, उसमें शामिल युवकों में पढ़े-लिखे और तकनीकी योग्यता रखने वाले युवक तक शामिल थे. पुलिस ने इस मामले में अभी जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें कई आरोपी गौतमबुद्धनगर के भाजपा नेता संजय राणा के परिवार से सम्बन्धित हैं. इन आरोपियों में राणा का 20 साल का बेटा विशाल भी शामिल है. गिरफ्तार एक आरोपी होमगार्ड कॉन्स्टेबल है. वह भी संजय राणा के परिवार से ताल्लुक रखता है. कुछ फरार आरोपी भी राणा के ही पड़ोसी हैं. घटना में बुरी तरह जख्मी हुआ 22 साल का दानिश स्थानीय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है. उसकी दो-दो ब्रेन सर्जरी की गई है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तनावग्रस्त घटनास्थल पर जाने के बजाय पीड़ित परिवार को ही लखनऊ बुलवा लिया और उन्हें आर्थिक मदद और सांत्वना दी. मुख्यमंत्री से मिलने वाले परिजनों में मरहूम अखलाक की मां, भाई, बेटी और दामाद शामिल थे. मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 45 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने जख्मी दानिश का इलाज सरकारी खर्चे पर कराने की घोषणा की और कहा कि उसके बेहतर इलाज के लिए अगर किसी अन्य अस्पताल में उसे भर्ती कराने की आवश्यकता हुई, तो यह कदम भी उठाया जाएगा.

इसके पहले अखिलेश ने कहा कि साम्प्रदायिकता से विकास प्रभावित होता है और आम आदमी को नुकसान पहुंचता है. कुछ ताकतें साम्प्रदायिकता फैलाने की साजिश कर रही हैं, जिनसे सावधान रहना होगा. साम्प्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने वाली ताकतें, देश व प्रदेश को पिछड़ेपन की दिशा में ले जाना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बदनाम करने की भी साजिशें चल रही हैं. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया खासतौर से फेसबुक, ट्विटर तथा व्हाट्सएप पर बेजा पोस्ट भेजकर साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए. दादरी घटना के बाद कुछ लोगों ने ट्विटर के जरिए साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर फौरन कानूनी कार्रवाई की गई. शासन की तरफ से व्हाट्सएप मोबाइल नम्बर (9454401002) भी जारी किया गया, जिससे सोशल मीडिया पर यदि आपत्तिजनक सामग्री डाली जाती है, तो उस पर तत्काल रोक लगाई जा सके.

लेकिन मुख्यमंत्री साम्प्रदायिक सौहार्द की यह सीख अपने ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आजम खान को नहीं दे पाए. आजम खान ने वह सब कुछ किया, जो धार्मिक उन्माद की किसी घटना को भड़काने का काम कुछ भाजपाई करते हैं. दादरी कांड पर आजम खान ने सीधे संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया और कहने लग गए कि हिन्दुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का कुचक्र हो रहा है. इसके खिलाफ वे संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करने के लिए कहेंगे. जानकार बताते हैं कि आजम देश के पहले ऐसे सियासतदां हैं, जो देश में रहते हुए कश्मीरी अलगाववादियों की तरह यूएन का राग अलाप रहे हैं, जबकि ऐसे मौके पर उन्हें अत्यंत संवेदनशील बयान देना चाहिए था. आजम खान गोमांस को लेकर भी विवादास्पद बयान जारी कर चुके हैं. आजम ने बयान दिया था कि गोभक्तों में यदि हिम्मत है, तो वे गोमांस परोसने वाले होटलों को वैसे ही तोड़ दें जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ी थी. आजम ने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है और मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है. आजम खान ने कहा कि दादरी मामले में सरकार की भूमिका नकारात्मक है. लेकिन उन्होंने इसमें केंद्र जोड़ कर खुद को भी बचाया. मुजफ्फरनगर दंगों के एक आरोपी भाजपा विधायक संगीत सोम, बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने दादरी घटना को लेकर भड़काऊ बयान दिए. जबकि घटना में मारे गए मोहम्मद अखलाक के बेटे वायुसैनिक कारपोरल मोहम्मद सरताज ने सामाजिक एकता और धार्मिक सद्भाव पर

(शेष पृष्ठ 18 पर)

राष्ट्र विरोधी बयान के लिए आजम को बर्खास्त करें

भाजपा सांसद महंत आदित्यनाथ ने दादरी घटना को लेकर संयुक्त राष्ट्र जाने की धमकी देने वाले आजम खान को उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किए जाने की मांग की है. आदित्यनाथ ने कहा कि आजम खान का बयान राष्ट्र विरोधी है, लिहाजा उन पर राष्ट्र विरोध का मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. आदित्यनाथ ने दादरी घटना में मारे गए मोहम्मद अखलाक की संदेहास्पद गतिविधियों की तरफ इशारा करते हुए अखलाक के कुछ दिनों पूर्व पाकिस्तान जाने की खबरों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने पूछा कि सरकार ने कभी यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि वह पाकिस्तान क्यों गया था. महंत आदित्यनाथ ने यूपी सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह यूपी सरकार काम कर रही है, उसे भी फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए. साम्प्रदायिक विद्वेष से अम्बेडकर नगर, बरेली, मुरादाबाद व कई अन्य जगहों पर हत्याएं हुईं, उन मामलों में मुख्यमंत्री ने सरकारी कोष से आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी? इन सवालों पर उन्हें जल्दी ही जनता के बीच में आना होगा. दादरी घटना में मारे गए मोहम्मद अखलाख के फौजी बेटे सरताज ने महंत आदित्यनाथ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है और उनके पिता पिछले साल पाकिस्तान नहीं गए थे. ■

आजम के बयान को ओवैसी ने ख़तरनाक बताया

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के उस बयान की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने दादरी घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाने की बात कही है. ओवैसी ने आजम के बयान को अत्यंत खतरनाक बयान बताया और कहा कि यह घटना अपने घर का मामला है, उसे अंतरराष्ट्रीय फोरम पर उठाना सरासर गलत है. ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आम लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है, इसीलिए सपा के नेता ऐसे बयान देकर अपनी झेंप मिटा रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दादरी हो या मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है. आजम खान सपा का मुस्लिम चेहरा हैं, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए. उनकी जिम्मेदारी है कि वे मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा मुहैया कराएं. जबकि मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ितों को भी अभी तक न्याय नहीं मिल सका है. यूपी सरकार को अपनी शासन व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए ताकि राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो. ■

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

दो अक्टूबर को गांधीमय हो गया बाराबंकी

समाजवादी और राष्ट्रवादी में कोई बड़ा फ़र्क नहीं : टंडन

पाटेश्वरी प्रसाद

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बाराबंकी हर साल गांधीमय हो जाता है. इस साल भी सबेरे से ही बापू की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम हुए, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक हस्तियों का सम्मान किया गया, गांधी-दर्शन पर वैचारिक हुई तो देर रात तक कवि सम्मेलन और मुशायरा चलता रहा. बाराबंकी में गांधी जयंती पर पूरे दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत 1978 से ही हुई, जो अब तक जारी है. स्थानीय नगर पालिका मैदान में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय कार्यक्रम में पूरा शहर सक्रिय रहता है. ऐसे आयोजन दुर्लभ ही होते हैं, जब विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मंच साझा करते हों. इस बार भी दुर्लभ मौका था जब सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के कद्दावर नेता गांधी के विचारों को आत्मसात करने एक साथ एक मंच पर मौजूद थे.

गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट द्वारा आयोजित गांधी जयंती समारोह के मौके पर नगर पालिका प्रांगण में मुख्य अतिथि प्रदेश के सहकारिता, राजस्व एवं लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि गांधी जी ने सत्य अहिंसा को आज़ादी की लड़ाई का हथियार बनाया. जिसकी आज देश को बेहद आवश्यकता है. इसी रास्ते पर चलकर विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है. उन्होंने कहा कि गांधी जी की परम्परा, उनके विचार, एवं लेख को समझने व पढ़ने की जरूरत है. इसी क्रम में उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया का नाम लिया और कहा कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा का अधिकार मिलना चाहिए. इस आंदोलन को आगे बढ़ाने और प्रदेश में विकास के लिए शिवपाल ने मशहूर गांधीवादी-समाजवादी पंडित राजनाथ शर्मा के प्रति आभार जताया.

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री लालजी टंडन ने कहा कि महापुरुषों के नाम पर बौद्धिक कार्यक्रमों का स्वरूप कम हुआ है. इस आयोजन में जिन व्यक्तियों के नाम से पुरस्कार दिए गए हैं, उन्होंने वास्तव में इतिहास बनाया है. श्री टंडन ने डॉ राम मनोहर लोहिया व पं. दीनदयाल उपाध्याय तथा जयप्रकाश नारायण एवं नानाजी देशमुख को याद करते हुए कहा कि आज राजनीति का चेहरा काफी बदल गया है. उन्होंने कहा कि पहले विचारों के विरोध होता था. लेकिन आपस में सब में स्नेह बना रहता था. सही मायने में समाजवादी व राष्ट्रवादी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का दर्शन आपसी सामंजस्य में है.

इस मौके पर गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट द्वारा आयोजित [illegible] में शिवपाल सिंह यादव, ग्राम्य विकास मंत्री अरविन्द सिंह गोप, पूर्व मंत्री लालजी टंडन, बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी, सदर विधायक सुरेश यादव, [illegible] सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया. जिसके उपरांत 38वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा आयोजित हुआ.

कई हस्तियों को मिला सामाजिक सहभागिता सम्मान

गांधी जयंती के अवसर पर सामाजिक सहभागिता सम्मान के अन्तर्गत डॉ लोहिया सम क्रांति पुरस्कार शिवपाल सिंह यादव, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि रे को दिया गया, [illegible]

अहिंसा का पुजारी जिस जगह पैदा हुआ, उस जगह के रहनुमा अब आडवाणी हो गए

गांधी जयंती के अवसर पर 38वां कवि सम्मेलन एवं मुशायरा गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट द्वारा नगर पालिका प्रांगण में सम्पन्न हुआ. जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद डा पीएल पुनिया ने की. [illegible] वो अहिंसा का पुजारी जिस जगह पैदा हुआ. उस जगह के रहनुमा अब आडवाणी हो गए. [illegible]

feedback@chauthiduniya.com

सारी पार्टियां सेंक रही रोटी, अखिलेश संजीदगी पर, तो आजम राष्ट्र विरोध पर उतरे

दादरी से खेल रहे सियासत के पादरी

पृष्ठ 17 का शेष

जोर दिया और कहा कि वह ऐसा कतई नहीं मानते कि सारे लोग बुरे हैं.

वहीं, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) ने आरोप लगाया कि दादरी में सपा सरकार की मदद से भाजपाई गुंडागर्दी कर रहे हैं. आइपीएफ ने पार्टी के प्रवक्ता अजीत सिंह यादव को बंधक बनाए जाने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और उत्तर प्रदेश में कानून का राज बहाल करने की मांग की. आइपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व आइपीएस एसआर दारापुरी ने कहा कि मृतक अखलाक के परिजनों से संवेदना जताने गए आइपीएफ के प्रवक्ता अजीत सिंह यादव को भाजपाइयों द्वारा बंधक बना लिया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही. अजीत यादव को बिसाहड़ा से आधा किलोमीटर पहले ही टिकटिकिया गांव में उन्मादी भीड़ ने रोक लिया और कई घंटे बंधक बनाए रखा. उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया और सभी डाटा नष्ट कर दिए गए. वहां मौजूद पुलिस ने आइपीएफ नेता की कोई मदद नहीं की. दारापुरी ने कहा कि सपा सरकार की निष्क्रियता दादरी में एक बड़े साम्प्रदायिक दंगे की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है. इसलिए सरकार को चाहिए कि वह तत्काल हस्तक्षेप कर कानून व्यवस्था बहाल करे. प्रदेश सरकार भाजपा और संघ की गुंडागर्दी पर रोक लगाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी करे.

उधर, समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ विपक्ष निराधार आरोप लगाने में व्यस्त है. सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बयान जारी किया कि कांग्रेस और बसपा समेत सम्पूर्ण विपक्ष के सुर बेसुरे हो गए हैं. भाजपा का एक सूत्री कार्यक्रम साम्प्रदायिकता और विद्वेष फैलाना है. उनकी हरकतों का यह सिलसिला साढ़े तीन साल से चल रहा है. सामाजिक सौहार्द और परस्पर सद्भाव को बिगाड़ना ही उनका नीति-कार्यक्रम है. चौधरी ने कहा कि भाजपाई साधु और साध्वियों का आचरण भी संयमित न होकर भड़काऊ है, जबकि संत समाज को साम्प्रदायिक तत्वों के बहकावे में नही आना चाहिए. सपा ने इस बात पर गहरा क्षोभ जताया कि एक बुजुर्ग की बर्बरतापूर्वक पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उस पर संवेदना जताने के बजाय भाजपाई मंत्री इसे हादसा बताने पर आमादा था. बसपा अध्यक्ष मायावती द्वारा समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराए जाने पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति में विरोध की यह घटिया मानसिकता बहुत खतरनाक है और उसकी जितनी निन्दा की जाए वह कम है.

नोएडा पुलिस ने केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, भाजपा विधायक संगीत सोम और बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू किए जाने की सिफारिश की है. गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी एनपी सिंह के पास भेजी गई रिपोर्ट में इन तीनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है. एसपी (ग्रामीण) संजय कुमार यादव ने कहा कि तीनों नेताओं ने निषेधाज्ञा के बावजूद ग्रामीणों को संबोधित किया, जबकि नेताओं को सिर्फ पीड़ित परिवार से मुलाकात की अनुमति दी गई थी. रिपोर्ट में बताया गया है कि दादरी जाने वालों में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माकपा पॉलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात, ऑल इंडिया मजलिस इत्तहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में गोमांस के कारण हुए विवाद का जिक्र नहीं किया है. दादरी के बिसाहड़ा कांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, लेकिन उसमें गोमांस खाने या अफवाह के कारण हुई हत्या की जिक्र स्पष्ट नहीं किया गया है. राज्य सरकार की रिपोर्ट में अखलाक और दानिश पर हमले की घटना के बारे में तो बताया गया है, लेकिन अखलाक की मौत के बाद मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी की कार्रवाई किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है. केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट में नोएडा के एसएसपी के हवाले से गृह विभाग ने इतना ही लिखा है कि जख्मी अखलाक की अस्पताल में मौत हो गई. गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की इस रिपोर्ट को अधूरा और अपुष्ट बताया है.

दादरी कांड में अखलाक के परिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 45 लाख का मुआवजा दिए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने वर्ष 2013 में प्रतापगढ़ के कुंडा हत्याकांड के बाद जिया उल हक के परिवार को 50 लाख और मृतक प्रधान के परिवार को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हत्या के मामलों में मुआवजा के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति बनाए जाने हेतु जनहित याचिका दाखिल की थी. इसपर हाईकोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में अपनी नीति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे. पूर्व प्रमुख सचिव (गृह) आरएम श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया था कि सरकार ने पहले से ही नीतियां बना रखी हैं, जिसमें विशेष जोखिम वाले कार्यों में सरकारी सेवक की मृत्यु के मामलों में 15 लाख की अनुग्रह राशि का प्रावधान है और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से निर्धन परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत पर अधिकतम पांच लाख सहायता देने की व्यवस्था है, पर मुख्यमंत्री विवेकानुसार इससे अधिक धनराशि दे सकते हैं. हलफनामे के अनुसार सरकार ने जिया उल हक को अनुग्रह धनराशि और मुख्यमंत्री के विवेक से और प्रधान परिवार को विवेकाधीन कोष से पैसे दिए थे.

डॉ ठाकुर ने अपनी ताजा याचिका में कोर्ट के सामने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस याचिका के बाद भी सरकार उसी प्रकार मनमाने तरीके से मुआवजा दे रही है, जैसा जागेन्द्र सिंह और अखलाक कांड में देखा गया, अतः कोर्ट इस मामले में शीघ्र सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री के स्तर पर हो रहे, इस मनमानेपन पर अंकुश लगाए. ■

मुलायम के बचाव में उतरे शिवपाल

शिवसेना के मुलायम पर दिए गए बयान की तीखी आलोचना करते हुए वरिष्ठ सपा नेता एवं सपा के प्रमुख प्रवक्ता शिवपाल सिंह यादव ने कहा सन् बयालीस की क्रांति के नायक राममनोहर लोहिया के शिष्य मुलायम सिंह की देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव में गहरी आस्था खुली किताब की तरह है. जब-जब देश में लोकतंत्र और एकता पर हमला हुआ है, मुलायम सिंह ने अगली कतार में आकर अपने जीवन और राजनीतिक भविष्य का संकट मोल लेकर भी देशद्रोही और साम्प्रदायिक ताकतों से आर-पार की लड़ाई लड़ी है. मुलायम की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले लोग जानबूझ कर देश के वर्तमान और इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. आपात काल के दौरान मुलायम ने युवा अवस्था के सुनहरे दिन जेल में बिताए. उस समय ठाकरे परिवार कहां था. बतौर रक्षा मंत्री नेता जी ने देश की सीमाओं पर जाकर चीन और पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी थी. संसद की प्राचीरें गवाह हैं कि चीन की उपनिवेशवादी नीति के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी है. सेना के सिपाही से लेकर गांव के किसान तक मुलायम सिंह के देशभक्ति के कायल हैं. शिवसेना देशभक्ति का मतलब नहीं जानती या उसे मुलायम सिंह का इतिहास नहीं पता हैं. दोष शिवसेना का नहीं अपितु आरएसएस, भाजपा, बजरंगदल की उस विचारधारा का है, जिसका पूरा आधार ही अंग्रेजों की तरह फूट डालो-राज करो की सोच पर आधारित है. उनका बस चले, तो गैर हिन्दू होने के कारण अशफाक उल्ला खां और भगत सिंह को देशद्रोही बता दें. शिवपाल ने साधु-संतों के साथ की गई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि हिन्दू धर्म, जीयो और जीने दो की बात करता है. वसुधैव कुटुम्बकम का नारा भारत और वास्तविक हिन्दुत्व का मूल मंत्र है. उदारता और सहअस्तित्व भारतीयता और हिन्दु धर्म का आभूषण है, शिवसेना, आरएसएस और उसके सहयोगी इसे तार-तार करने में लगे हुए हैं. उनकी हरकतों से देश का सिर शर्म से झुक गया है.

शिवपाल ने कहा कि चुनाव के समय साम्प्रदायिक ताकतें कम्युनल कार्ड खेलती हैं. हम समाजवादी देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच आने नहीं देंगे. देश, विशेष कर उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब नेताजी मुलायम सिंह यादव के सामने मुख्यमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी और सामाजिक सद्भाव में से एक को चुनने का समय आया था, तो उन्होंने सामाजिक सद्भाव व हिन्दू-मुस्लिम एकता को चुना था. स्वयं केन्द्र सरकार की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जब से देश में यह सरकार आयी है तब से साम्प्रदायिक दंगे बढ़े हैं. उन्होंने दादरी मुद्दे पर कुछ भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को भड़काऊ बताते हुए कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें रोकने के लिए कोई कदम न उठाना, इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं बड़ा षडयंत्र चल रहा है. यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनकी मांग के बाद केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा बर्खास्त कर देते, तो हालात इतने न बिगड़ते. सपा सरकार मुजफ्फरनगर-2 नहीं होने देगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ पूरी जांच कर कठोर कार्रवाई करेगी. ■

भले सरकार चली जाए, पर सख्त कार्रवाई करेंगे: मुलायम

दादरी घटना पर देर तक चुप्पी साधे रखने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आठ अक्टूबर को मुंह खोला. उन्होंने कहा कि भले ही उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन वे दादरी केस में कड़ी कार्रवाई जरूर कराएंगे. मुलायम ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि इस मामले में एक पार्टी विशेष के तीन नेताओं ने मिलकर साजिश रची. यही लोग मुजफ्फरनगर दंगों में भी शामिल थे. हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे, भले ही हमें अपनी सरकार की कुर्बानी देनी पड़े. मुलायम ने कहा कि यह अत्यंत दुख की बात है कि एक जवान वायुसेना की कहीं दूरस्थ इकाई में तैनात हो और उसके पिता की उसके गांव में हत्या कर दी जाए. कुछ लोग साजिश रचकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं. उन्होंने दोहराया कि कुछ लोग साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे. दादरी की घटना में शामिल लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उल्लेखनीय है कि दादरी घटना के बाद वहां जाकर भड़काऊ भाषण देने में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, भाजपा विधायक संगीत सोम और बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी खरीद केंद्र बेईमानी, कम क़ीमत पर बिचौलिए खरीद रहे धान

धान के घमासान में किसान

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर में घोषणा की थी कि एक अक्टूबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीद के लिए सरकारी धान क्रय केन्द्रों की स्थापना हो जाएगी. लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी धान क्रय केंद्र स्थापित नहीं हुआ और एक अक्टूबर भी कब का गुजर चुका.

उत्तर प्रदेश में धान खरीद की सरकारी कीमत तय कर दिए जाने के बावजूद धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकी है. किसान फिर से अपनी फसल खुले बाजार में औने-पौने भाव में बेचने पर मजबूर हो रहा है. मंडियों में व्यापारी और बिचौलिए किसानों को लूटने में लगे हैं. सूखे के कारण किसान इस बार बड़ी मुश्किल से धान पैदा कर सका है, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों को मदद करने के बजाय उसकी तरफ आंखें बंद किए हुई है. धान की खरीद के मौसम में पहले के खरीद घोटाले सामने आ रहे हैं. फिर भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है. मंडियों का चक्कर लगाने वाले किसान तो कहते हैं कि खरीद घोटालों में सरकार के लोग ही लिप्त रहते हैं, तो सरकार क्या बोलेगी. सूखे से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने और गन्ना किसानों का बकाया दिलाने की मांगें उत्तर प्रदेश में बेअसर हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर में घोषणा की थी कि एक अक्टूबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीद के लिए सरकारी धान क्रय केन्द्रों की स्थापना हो जाएगी. लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी धान क्रय केंद्र स्थापित नहीं हुआ और एक अक्टूबर भी कब का गुजर चुका. सरकारी खरीद के अभाव में किसान धान को मंडी में ले जा कर बिचौलियों की तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हैं. मंडियों में किसान लूटे जा रहे हैं. सरकार ने धान का क्रय मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, लेकिन मंडियों में व्यापारी उसे 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं. यह खुलेआम हो रहा है. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) ने इस खरीद-अराजकता के खिलाफ प्रदेश में किसानों का आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है और सरकार से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एसआर दारापुरी ने इस मामले में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है.

इस बार बारिश कम होने के कारण धान और गन्ने की फसल का बहुत नुकसान हुआ है. लेकिन किसानों को उसकी भरपाई करने के बजाय उनकी लुटाई हो रही है. विडंबना यह है कि धान की कमजोर फसल के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल के लिए 42 लाख टन की सरकारी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन यह लक्ष्य-निर्धारण भी महज धोखा ही साबित हो रहा है. धान की सरकारी खरीद में खाद्य एवं रसद विभाग के अलावा 10 अन्य एजेंसियों की मदद लिए जाने की बात कही गई थी, पर सरकार के नुमाइंदे और एजेंसियां मिल कर बिचौलियों के जरिए किसानों का धान खरीद रही हैं. बीते साल उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा था, उस समय भी लक्ष्य की आधी खरीद भी नहीं हो पाई थी.

इस साल यानी, विपणन वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति लागू की. प्रदेश के 10 मंडलों में धान खरीद की अवधि एक अक्टूबर 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक और आठ अन्य मंडलों में धान खरीद की अवधि एक नवम्बर 2015 से 28 फरवरी 2016 तक निर्धारित की गई है. इसके लिए शासन ने खरीद केंद्रों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित कर सम्बद्ध जिलाधिकारियों को हिदायत देने की औपचारिकता भी पूरी कर ली थी, लेकिन जिलों-जिलों में किसानों का धान मंडियों और बाजारों में खुलेआम बिकता हुआ दिख रहा है. धान पैदा करने के बाद किसान उसकी लागत पाने की जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि उस पर दोतरफा मार पड़ी है. धान बोते समय भी बीजों की कीमत में धंधेबाजी की गई थी, लेकिन सरकारी तंत्र एजेंसियों के साथ धन कमाने में लगा रहा. उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ने 140 करोड़ का 28 हजार क्विंटल शंकर धान बीज खरीदा था, लेकिन निगम ने जो जेकेआरएच-401 बीज 274 रुपये में और पीएसी-801 बीज 262 रुपये किलो के भाव से खरीदा, वही बीज बाजार में मात्र 200 रुपये किलो बिक रहा था. सरकारी खरीद और बाजार दर का अंतर यह बताता है कि निगम ने धान बीज की खरीद में करोड़ों की कमीशनखोरी की थी. अब धान की खरीद का गोरखधंधा आप देख ही रहे हैं.

उत्तरप्रदेश में धान खरीद के मामले में करोड़ों रुपये के घपले का पूर्व का मामला भी इस खरीद सत्र के दरम्यान उजागर हुआ है. आवश्यक वस्तु निगम द्वारा हरदोई जिले में धान खरीद में 5.50 करोड़ का घपला किए जाने और नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन (नैफेड) द्वारा भी धान खरीद में करोड़ों का घपला किए जाने का पर्दाफाश हुआ है.

उत्तरप्रदेश में धान खरीद के मामले में करोड़ों रुपये के घपले का पूर्व का मामला भी इस खरीद सत्र के दरम्यान उजागर हुआ है. आवश्यक वस्तु निगम द्वारा हरदोई जिले में धान खरीद में 5.50 करोड़ का घपला किए जाने और नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन (नैफेड) द्वारा भी धान खरीद में करोड़ों का घपला किए जाने का पर्दाफाश हुआ है. इस वर्ष 29 फरवरी को सम्पन्न हुई किसानों से धान खरीद योजना के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु निगम द्वारा केवल हरदोई जिले में निगम के लिए निर्धारित 20 हजार क्विंटल धान खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध 94 हजार क्विंटल धान खरीदा गया था. उक्त धान की 90 प्रतिशत खरीद हरदोई स्थित दो चावल मिलों मेसर्स पशुपतिनाथ एग्रो इंडिया लिमिटेड और मेसर्स पशुपतिनाथ एग्रो फूड प्रोडेक्ट लिमिटेड में ही खरीदा गया. निगम ने धान की मिलिंग का काम सीधे मेसर्स पशुपतिनाथ एग्रो इंडिया लिमिटेड को दिया, जबकि आरएफसी लखनऊ की ओर से उक्त मिल ब्लैक लिस्टेड थी. निगम और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिल मालिक से साठगांठ करके धान खरीद का एग्रीमेंट कर लिया. साठगांठ का असर यह रहा कि खरीद के बाद जारी होने वाला चेक खरीद के पहले ही एडवांस में ही जारी कर दिया गया. उक्त दोनों मिलों को दिए गए धान से उत्पादित चावल की मात्रा लगभग 63 हजार क्विंटल होती है, जिसमें से मात्र 23530 क्विंटल चावल ही आधिकारिक तौर पर प्राप्त हुई है. शेष करीब 40 हजार क्विंटल चावल मिल से गायब है. गायब चावल की मूल्य लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये है.

लखनऊ संभाग के जनपद लखनऊ में 1.83 करोड़ रुपये का चावल, उन्नाव में 2.63 करोड़, रायबरेली में 3.62 करोड़ तथा सीतापुर में 1.17 करोड़ रुपये मूल्य का चावल निगम को अभी तक प्राप्त नही हुआ है. चावल सम्बन्धित जनपदों की मिलों में उपलब्ध ही नहीं है, तो मिले कैसे? इस तरह लखनऊ संभाग में निगम को कुल 14.22 करोड़ रुपये का आधिकारिक तौर पर नुकसान पहुंचा है. अब देखिए नैफेड का कमाल. पिछले खरीद सत्र में धान की खरीद में राज्य सरकार की एजेंसी के रूप में नैफेड को शामिल किया गया था. नैफेड ने प्रदेश में लगभग 1.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी. नियमानुसार किसानों एवं आढ़तियों के माध्यम से खरीदे गए धान की सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई चावल मिलों से कस्टम हॉलिंग कराई जाती है. फिर तैयार चावल की डिलीवरी राज्य सरकार के स्टेट पूल गोदामों में की जाती है. बताया गया कि नैफेड ने धान खरीद के लिए मेसर्स ओलम इंडिया लिमिटेड को अपना सब-एजेंट बनाकर पूरे प्रदेश में धान की खरीद की. वास्तव में इस फर्म ने किसानों से धान न खरीदकर खुले बाजार से सीधे चावल खरीद कर स्टेट पूल में डिलीवर कर दिया. खुले बाजार में 1200 रुपये प्रति क्विंटल का चावल खरीद कर सीएमआर के नाम पर डिलीवर किया है. जबकि नैफेड ने राज्य सरकार से 1366 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान प्राप्त किया. इस प्रकार कुल चावल की मात्रा पर 166 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 13.50 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

भागवत फिर बोले, आरक्षण की समीक्षा हो

राजकुमार शर्मा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से आरक्षण की समीक्षा की बात देहरादून स्थित दरबार साहब में की. उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए और इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. जनसेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था श्री दरबार साहिब पहुंचे संघ प्रमुख ने कहा कि तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर भी विचार किया जाना जरूरी है. इसके लिए उन्होंने तीन सुझाव भी दिए. उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि दस साल बाद हम कितने लोगों का पालन-पोषण कर सकते हैं. दूसरा, दस साल बाद हम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं. तीसरा, दस साल बाद यह देखना चाहिए कि देश के निर्माण में कितने प्रतिशत युवा सहभागिता निभा पाएंगे.

श्री दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास इन दिनों संघ प्रमुख को संकटमोचन की भूमिका में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने संघ प्रमुख को सुझाव दिया कि आरक्षण व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए. समिति तय करे कि कितने लोगों को और कितने वर्षों तक आरक्षण देने की जरूरत है, जिससे समाज में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सके. संघ प्रमुख भागवत ने दरबार साहब द्वार शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में की जा रही जनसेवा को मुक्त कंठ से सराहा और दरबार साहब को मत्था टेका. इंटरनेट के संबंध में चल रही चर्चाओं पर संघ प्रमुख ने कहा कि इंटरनेट विज्ञान की देन है. इस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय

अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि बच्चे खुद ही हर बुरी चीज से दूर रहें. पहली बार दरबार साहब पहुंचकर संघ प्रमुख का मत्था टेकना जितनी मुंह उतनी बाते पैदा कर रहा है, इस मामले से यह साफ हो गया है कि मिशन 2017 को सुखद बनाने के लिए भी भागवत ने दरबार साहब का दास बनना स्वीकारा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कोटद्वार की घटना से हरीश के माथे पर शिकन

कोटद्वार में हाल की घटनाओं से बिगड़ी सांप्रदायिक फिजा ने प्रदेश की हरीश सरकार के माथे पर शिकन पैदा कर दी है. जिसकी वजह जल्द ही होने वाले हरिद्वार के पंचायत चुनाव और 2017 में विधानसभा के चुनाव भी ऐसे में प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैला, तो कांग्रेस को हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. राज्य के मुख्यमंत्री हर तरह से सद्भावना फैलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे है. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव का अनुभव भी यही कहता है. अक्टूबर 2011 के रुद्रपुर दंगों ने 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्पष्ट जीत का गणित बिगाड़ दिया था. इन विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को पहाड़ में जीत हासिल हुई थी. ऊधमसिंह नगर व हरिद्वार जिलों की 20 में से भाजपा ने 12 सीटें हासिल क ली थीं. कोटद्वार के सांप्रदायिक तनाव की घटना का असर लंबे समय तक बरकरार रहता है, तो कोटद्वार में कांग्रेस को सियासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता

है. कांग्रेस के विश्लेषकों का मानना है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण ही ऊधमसिंह नगर जिले की नौ में से सात सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई. उनका मानना है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ही असर रहा कि ऊधमसिंह नगर में भाजपा करीब 36 फीसद वोट हांसिल करने में सफल हुई और काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता जैसी सीटों में भाजपा को 40 से 46 फीसद तक वोट हासिल हुए. विश्लेषकों का मानना है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में खंडूड़ी फैक्टर की बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने परिणाम पलटने और भाजपा को सत्ता की दहलीज तक खड़े कर देने में मदद की थी. उनका मानना है कि इसी वजह से मैदान में भाजपा की सीटें 2007 की तीन गुनी हो गई. कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि रुद्रपुर दंगों ने तराई में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, इसका फायदा भाजपा को मिला. कुछ वर्षों से सूचना तकनीक के साधनों मसलन व्हाट्सऐप, फेसबुक आदि भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में मददगार हो रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस के समक्ष सांप्रदायिक सौहार्द बरकार रखने के साथ हरिद्वार पंचायत चुनाव व 2017 के विधानसभा चुनाव की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं. अब देखना यह है कि वह इन चुनौतियों का कैसे मुकाबला करती है. ■

ब्यूरो कार्यालय

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा में शामिल नहीं होंगे भंडारी

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में हरीश रावत के प्रभाव का सिक्का चल रहा है. मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में बद्रीनाथ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने आगामी-2017 का चुनाव कांग्रेस से ही लड़ने की सार्वजनिक घोषणा कर भाजपा में जाने के कयासों पर विराम लगा दिया है. भंडारी की इस घोषणा से कांग्रेस-भाजपा दोनों में राजनीतिक उथल-पुथल के आसार बढ़ गए हैं. बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी के आगामी विधनसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ने को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे. इसके चलते जहां उनके कांग्रेस में ही अपने विरोधी भाजपा से चुनाव लड़ने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, वहीं भाजपाई भी उनके भाजपा से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं में डूबे थे. वैसे भी भंडारी का राजनीतिक मिजाज पहले से किसी एक दल से जुड़ा नहीं रहा है. वर्ष 2003 में जिलापंचायत सदस्य के पद पर कांग्रेस से उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, तब उनका टिकट काट दिया गया था. उस वक्त उन्होंने निर्दलीय तौर पर सदस्य का चुनाव लड़ा था. इस चुनाव को उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जीत कर विरोधियों को अपना लोहा मनवाया था. वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदप्रयाग विधनसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी की थी. तब पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज ने अपने खास चहेते सत्येंद्र बर्थवाल को नंदप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का टिकट दिलवा दिया था. इससे नाराज भंडारी कांग्रेस को अलविदा कर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए थे. इस चुनाव में भी उन्हें सफलता हासिल हुई थी और वे निर्दलीय तौर पर विधायक बनने में कामयाब हुए. प्रदेश में भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के नेतृत्व वाली सरकार को अपेक्षित समर्थन न मिलने पर समर्थन के एवज में भंडारी को कैबिनेट मंत्री का ओहदा मिला था. भाजपा की सरकार ने वे पूरे पांच साल मंत्री पद पर आसीन रहे और सत्ता की मलाई खाई. वर्ष 2012 के चुनाव में जनरल खंडूड़ी उन्हें भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़वाना चाहते थे, चमोली के भाजपाइयों ने इस सवाल पर विद्रोह का बिगुल बजा दिया था. उस वक्त महाराज ने फिर भंडारी की कांग्रेस में वापसी करवाई और वे रिकार्ड मतों से जीत दर्ज कराने में कामयाब रहे. अब चूंकि भंडारी के राजनीतिक गुरु रहे महाराज कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए हैं, तो माना जा रहा था कि वर्ष 2017 के चुनाव में भंडारी पलटी मार कर भाजपा टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे. यह कयासबाजी यहां आमतौर पर सियासी चर्चा का विषय बनी रही है. शुक्रवार को पोखरी मेले में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री के सम्मुख स्वयं भंडारी ने कहा कि इनके विरोधी लगातार भाजपा में जाने की चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में ही रहकर 2017 का चुनाव कांग्रेस से लड़ेंगे. उनके इस ऐलान से एक बार फिर उनके भाजपा में जाने की चर्चाओं को विराम लग गया है. ■

बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी के आगामी विधनसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ने को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे. इसके चलते जहां उनके कांग्रेस में ही अपने विरोधी भाजपा से चुनाव लड़ने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, वहीं भाजपाई भी उनके भाजपा से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं में डूबे थे.

feedback@chauthiduniya.com

मोहम्मद शहजाद की बसपा में वापसी

रेनू शर्मा

पूर्व विधायक की घर वापसी की धर्म नगरी हरिद्वार में चर्चा है, बरेली में पैसा पकड़े जाने और अब अपनी भाभी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष अंजुम बेगम के प्रशासनिक-वित्तीय अधिकार सीज करने के बाद से राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे बहादराबाद के पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद की बसपा में वापसी हो गई. हरिद्वार के बहादराबाद स्थित एक बारात घर में बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों के साथ शहजाद ने बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखण्ड प्रदेश प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने दोबारा पार्टी की सदस्यता ली. राजनीति में पैसा बोलता है का सीधा असर बसपा नेता की घर वापसी पर जितनी मुंह इतनी बाते हो रही है. इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने जनता को निराश किया है. उत्तराखंड में बारी-बारी से अपनी सरकार बनाने वाले इन दोनों दलों ने राज्य को कंगाल कर दिया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बसपा सुप्रीमो मायावती के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया. यह घर वापसी ने शहजाद के पकड़े गए धन की इस जनचर्चा पर भी मोहर लगा दी की यह धन राजनीतिक डील के लिए ही भेजा जा रहा था. जानकारों का मानना है कि शहजाद को पकड़ी गई रकम से दुगुना धन पार्टी फंड के लिए देना पड़ा. राजनीति में सबकुछ धन बल पर ही निर्भर कर रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

परंपरा नहीं, पाखंड में जली काशी

इस यात्रा का नेतृत्व द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे थे. कांग्रेस पार्टी के करीब कहे जाने वाले विद्या मठ से ताल्लुक रखने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गत 22 सितंबर की रात गोदौलिया चौक पर बटुकों और खुद पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में उक्त यात्रा निकाली थी.

शिव दास प्रजापति

- पुलिस पर वाहन फूंकने का आरोप
- प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस
- मीडियाकर्मियों पर हमले की निंदा
- कांग्रेस विधायक अजय राय समेत 50 लोग गिरफ्तार
- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद घायल

परंपराओं के पालन में नहीं बल्कि पाखंड में काशी झुलस गई. गत 5 अक्टूबर की शाम नगर का दिल कहे जाने वाला गोदौलिया चौक पत्थरबाजी, मारपीट, तोड़फोड़, बमबाजी, लाठीचार्ज समेत आगजनी का गवाह बना. कहीं पुलिस के चार पहिया वाहन जल रहे थे, तो कहीं पुलिस पिकेट. स्थानीय तांगा स्टैंड में रखी मीडियाकर्मियों की मोटरसाइकिलें आग का गोला बनी थीं, तो पुलिस के वाहनों से निकलता धुआं बाशिंदों में खौफ पैदा कर रहा था. उपद्रवियों का झुंड कहीं सरकारी वाहनों को तोड़ रहा था, तो कहीं पुलिस-पीएसी जवानों पर पत्थर बरसा रहा था. कहीं पुलिसकर्मी उनके लात-घूंसों के जद में थे, तो कहीं उनका बोतल बम किसी बड़ी घटना की दहशत पैदा कर रहा था. खबरनवीसों को मीडिया का तमगा भी नहीं बचा पाया. वे भी खाकी वर्दीधारी का शिकार बनें. पीएसी और पुलिस के डंडे उनके शरीर के साथ कैमरे और फ्लैश पर ताबड़तोड़ पड़ रहे थे. प्रशासन के आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां भीड़ को घायल कर रही थीं. यू कहें कि चारों तरफ भगदड़ और हिंसा का मंजर और इसकी पटकथा लिखी, धार्मिक आस्था की सियासी बुनियाद पर निकली अन्याय प्रतिकार यात्रा ने.

संतों पर लाठीचार्ज को लेकर शासन को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में संतों पर लाठीचार्ज करने के मामले में प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास, वाराणसी के जिलाधिकारी और एसएसपी को नोटिस जारी की है. कोर्ट ने लाठीचार्ज के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है. न्यायाधीश रणविजय सिंह ने लाठीचार्ज की घटना के बाद दाखिल एक अवमानना अर्जी पर यह नोटिस जारी करने का आदेश दिया. शंकराचार्य स्वरूपानंद के परम शिष्य और संत डंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में वाराणसी में संत गणेश भगवान की मूर्ति के विसर्जन को गंगा में करने पर अड़े थे. उनका कहना था कि गणेश की मूर्तियों को गंगाजी में प्रवाहित करने से जल को कोई नुकसान नहीं है. इससे गंगा प्रदूषित नहीं होगी. दूसरी ओर, जिला प्रशासन किसी भी कीमत पर इन मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित न होने देने पर अड़ा था.

इस यात्रा का नेतृत्व द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे थे. कांग्रेस पार्टी के करीब कहे जाने वाले विद्या मठ से ताल्लुक रखने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गत 22 सितंबर की रात गोदौलिया चौक पर बटुकों और खुद पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में उक्त यात्रा निकाली थी. वे और मराठा समुदाय के लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद गंगा नदी में गणेश की मूर्ति विसर्जित करने के लिए गोदौलिया चौक पर धरना दे रहे थे. जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज के बल पर उन लोगों का धरना खत्म करा दिया था. जिला प्रशासन की उक्त कार्रवाई के विरोध में उन्होंने 5 अक्टूबर को अन्याय प्रतिकार यात्रा निकालने की घोषणा की थी, जो मैदागिन स्थित टाउन हाल से चलकर दशाश्वमेध घाट तक जानी थी. इस यात्रा को कांग्रेस, भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू युवा वाहिनी, आम आदमी पार्टी समेत कई व्यापारिक और गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त था. इसमें महंत संतोष दास उर्फ सुतआ बाबा, पातालपुरी मठ के महंत बालक दास, कांग्रेस विधायक अजय राय, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, विहिप नेता आनंद सिंह, भाजपा नेता दयाशंकर मिश्र दयालु, विहिप साध्वी प्राची, चक्रपाणी महाराज समेत हजारों लोग के शामिल होने की संभावना भी थी. ऐसा हुआ भी. उक्त लोगों के अलावा करीब तीन दर्जन उपद्रवी युवा भी यात्रा में शामिल हुए. उनके झुंड को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उत्तेजित हैं.

सोमवार को यात्रा बुलानाला, नीचीबाग, चौक होते हुए गोदौलिया चौक के पास स्थित कन्हैया चित्र मंदिर तक पहुंची. तभी किसी ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की अफवाह को हवा दे दी. इसका फायदा उठाते हुए यात्रा के आगे की पंक्ति में चल रहे करीब तीन दर्जन उपद्रवी युवाओं ने गोदौलिया चौक के पास पुलिस-पीएसी जवानों पर पथराव शुरू कर दिया. देखते ही देखते भगदड़ मच गई, जो कुछ ही पलों में हिंसक हो उठी. जिला प्रशासन के आलाधिकारियों ने हालात पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन वह उनके नियंत्रण से बाहर था. जिलाधिकारी राजमणि यादव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने खुद मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. फौरन प्रशासन ने कोतवाली, चौक, दशाश्वमेध और लक्सा थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगने की घोषणा की, जो दो घंटे बाद हटा लिया गया. हालात नियंत्रण में आने तक 13 पुलिसकर्मियों समेत दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे. इनमें मीडियाकर्मी भी शामिल हैं. एक पुलिसकर्मी और एक मीडियाकर्मी को गंभीर चोटे आई हैं. उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज हो रहा है. गोलगड्डा निवासी 32 वर्षीय राजगीर सूर्य प्रकाश बिंद को पुलिस की गोली लगने की बात भी कही जा रही थी. हालांकि चिकित्सकों ने चोट देखने बाद गोली की लगने की घटना से साफ इंकार कर दिया. चिकित्सकों ने सूर्य प्रकाश के कमर में किसी नुकीली चीज से चोट लगने का दावा किया है. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना में दो दर्जन से अधिक वाहनों के जलने की बात भी कही जा रही है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 105 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में नामजद प्राथमिकी दर्ज की है. उन पर घातक आयुधों के साथ बलवा करने, नियमों के विरुद्ध बलवा करने की नीयत से जुटने, हत्या का प्रयास करने, कर्तव्य से डिगाने के लिए सरकारी कर्मी को चोट पहंचाने, सरकारी कर्मचारी को गंभीर चोट पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने, डकैती डालने, प्राण घातक हमला करने, पचास रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी कर संपत्ति का नुकसान करने, आवासीय स्थान पर आगजनी करने या विस्फोटक लगाने आदि का आरोप लगाया गया है. लोकसंपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा-3/4 और क्रमिनल लॉ अमेडमेंट एक्ट की धारा-7 सीएलए के तहत भी कुछ लोगों को नामजद किया गया है. पुलिस प्रशासन ने मंगलवार तक कांग्रेस विधायक अजय राय समेत 50 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया. साथ ही उसने कहा कि करीब एक हजार लोगों को चिन्हित करने की कोशिश जारी है.

गौरतलब है कि गंगा नदी में देवी-देवताओं की मूर्तियों के विसर्जन को लेकर साधु-संतों और वाराणसी प्रशासन के बीच ठन गई है. जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन विभिन्न इंतजाम करने में लगा है, वहीं साधु-संतों और धार्मिक संगठनों समेत कुछ सियासी दलों के लोग परंपराओं के आडंबर को ढाल बनाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं. कांग्रेस और भाजपा समेत कुछ हिंदू संगठनों के नेताओं ने पिछले दिनों केदारघाट स्थित विद्यामठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके बटुकों पर हुए लाठीचार्ज का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गत 26 सितंबर को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और बटुकों पर हुए लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हुए कहा था कि लाठीचार्ज सिर्फ संतों पर नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज पर हुआ है. वहीं विश्व हिन्दू परिषद की साध्वी प्राची ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हाईकोर्ट भी ऐसे ही फैसले देती है. जबतक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांग लेते तब तक आंदोलन चलता रहेगा. यूपी सरकार कंस की तरह हो चुकी है. अखिलेश का सर्वनाश भी कंस की तरह होगा. आजम खान ने मेरी हत्या की योजना बनाई है. देवबंद से इसका फतवा जारी हुआ है. गोमांस खाने वालों को प्रदेश सरकार 45 लाख इनाम देती है और साधुओं को लाठी. कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने संतों के आंदोलन के साथ खड़े रहने की बात कही थी. ■

मीडियाकर्मियों पर हमला

काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब की संयुक्त बैठक में मीडियाकर्मियों की मोटसाइकिलों को फूंके जाने, कैमरा और फ्लैश तोड़ने और उनपर जानलेवा हमला करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया गया और मीडिया कमियों पर हुए हमले की निंदा की गई. पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा संघ के पैड पर दशाश्वमेध थाने में इसके लिए एक तहरीर भी दी गई जिसपर थानाध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार कर दिया. फिलहाल पुलिस कप्तान के हस्तक्षेप के बाद थानाध्यक्ष ने तहरीर ले लिया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की. गौरतलब है कि अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान गोदौलिया चौराहे पर हुई हिंसक घटना में टाइम्स ऑफ इंडिया के छायाकार संजय गुप्ता और खबर फास्ट न्यूज चैनल के वीडियो कैमरामैन विकास गौड़ गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा प्रमोद गुप्ता, शंकर गुप्ता, भैरव जायसवाल, पवन कुमार सिंह, चंदन रुपानी, सौरभ बनर्जी, नितिन तिवारी, शंकर चतुर्वेदी आदि को भी चोटें आईं. विकास गौड़ के दावों की मानें तो पीएसी के जवानों उन्हें और संजय गुप्ता को मारा, क्योंकि वे उन जवानों की करतूत कैमरे में कैद कर रहे थे. उन्होंने दावा किया कि पीएसी के जवानों ने ही तांगा स्टैंट में खड़ी मीडियाकर्मियों की मोटरसाइकिलों में आग लगाई थी. घटना में करीब एक दर्जन मीडियाकर्मियों की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया है. इनमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सहारा के तीन पत्रकारों की मोटरसाइकिलें शामिल हैं. पुलिस को दी गई तहरीर में संजय गुप्ता का दो कैमरा और लेंस, सौरभ बनर्जी का फ्लैश, विकास गौड़ का वीडियो कैमरा और शंकर चतुर्वेदी का कैमरा और लेंस तोड़े जाने की दावा भी किया गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com